06 महागठबंधन व राजग की होगी अग्निपरीक्षा
07 विधानसभा में महिलाओं का कम रहा है प्रतिनिधित्व
20 घटते वजन से परेशान है आलिया

पटना
रविवार
04 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2015
पेज - 20
मूल्य 5 रुपए

गणादेश

जन गण मन... साप्ताहिक

www.ganadesh.com

आर.एन.आई. रजि. नं. 39661/84 | वर्ष : 31, अंक : 38 | बिहार / झारखंड से एक साथ प्रकाशित | मोबाईल नं- 9431433478

इसे भी देखें

नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस कोच्चि

मुंबई : इस सप्ताह भारतीय नौसेना की ताकत में और बढ़ोत्तरी तब हो गई जब आईएनएस कोच्चि को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। रक्षामंत्री मनोहर पार्रिकर ने बुधवार को इस युद्धपोत का जलावतरण किया। आईएनएस कोच्चि को नौसेना के आंतरिक संगठन 'नौसैनिक डिजाइन निदेशालय' ने डिजाइन किया है और मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। रक्षामंत्री ने इस मौके पर बताया कि 15 साल के लिए स्वदेशी योजना का खाका तैयार किया गया है।
रक्षा मंत्रलय के मुताबिक आईएनएस कोच्चि युद्धपोत के शस्त्र और सेंसर अधिक आधुनिक हैं। यह 164 मीटर लंबा और 17 मीटर गहरा है जो चार गैस टर्बाइन से चलता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 7500 टन वजन के साथ 30 नॉट तक की रफ्तार पकड़ सकता है। जहाज पर करीब 40 अधिकारी और चालक दल के 350 सदस्य सवार होंगे।

चुनाव अभियान ने पकड़ा जोर, प्रचार में उतरे दिग्गज

मोदी, सोनिया, नीतीश, लालू ने की रैलियां और जनसभाएं

गणादेश न्यूज नेटवर्क

पटना : बीता सप्ताह (27 सितंबर से 04 अक्टूबर) बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के नाम रहा। अपने-अपने दल और गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान की कमान अपने हाथों में थामे दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सप्ताह की शुरूआत से ही रैलियों और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशें करते दिखे तो सप्ताह के खत्म होते होते पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बिहार विधानसभा के चुनावी जंग में शंखनाद करते दिखाई दिए।

बीते सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी और महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करते हुए भागलपुर और गया में रैलियां की। अपनी चुनावी रैलियों में सोनिया गांधी ने महागठबंधन और नीतीश कुमार के पक्ष में मतदाताओं से वोट देने की अपील करने के साथ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर खोखले वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए ने अपने अधिकतर वादे पूरे किए। सोनिया ने पीएम मोदी पर देश से ज्यादा विदेश में रहने का भी आरोप लगाया।

जुबानी जंग में शालीनता की सीमा लांघ रहे नेता

चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने के साथ नेताओं के भाषणों में तुर्शी आती जा रही है। विरोधियों पर हमला करने का वे कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, मगर इस दौरान वे शालीनता और मर्यादा की सीमाएं भी लांघ रहे हैं। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बताते हुए दुश्मन नंबर वन करार दिया। जवाब में लालू प्रसाद यादव ने भी अमित शाह को नरभक्षी बता डाला। लालू ने नरेंद्र मोदी को नफरत फैलाने वाला और राक्षसी सेना का नेतृत्व करनेवाला कह डाला। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद को विष वमन करनेवाला बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के होते कोई माई का लाल विष वमन नहीं कर सकता। वहीं जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक चुनावी सभा में शिक्षकों की तुलना कुत्तों से करके नया विवाद ही खड़ा कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के शिक्षक कुत्तों तक को पढ़ाने के लायक नहीं है।

इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांका में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर हमला बोला और विकासवाद को वोट देने की अपील की। इस रैली में मोदी के निशाने पर मुख्यरूप से नीतीश कुमार रहे। मोदी ने नीतीश कुमार को अहंकारी बताते हुए लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। मोदी ने कहा कि इसबार बिहार में दो बार दीवाली मनाई जाएगी। एक दीवाली का त्यौहार और दूसरा चुनावी जीत की दीवाली। इस रैली में भाजपा और राजग के कई बड़े नेता भी मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे। भाजपा और राजग की तरफ से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्य के कई अन्य बड़े नेताओं ने भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते और जीत की रणनीति बनाते नजर आए। भाजपा की तरफ से इस सप्ताह गुरुवार को विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया गया। इस विजन डॉक्युमेंट में भाजपा और राजग की सरकार बनने पर 24 घंटे बिजली, महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम समेत कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। विजन डॉक्युमेंट पेश करते केंद्रीय वित्तमंत्री ने बिना नाम लिए लालू नीतीश पर निशाना साधते हुए अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होने का दावा किया।

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी इस सप्ताह चुनावी रैलियों और जनसभाओं को लेकर खासे व्यस्त नजर आए। नीतीश कुमार ने एक दिन में कई-कई जनसभाएं की तो लालू प्रसाद भी पीछे नहीं रहे। नीतीश ने अपनी चुनावी जनसभाओं में फिर एक बार नीतीश कुमार के नारे के बीच अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर तो वोट मांगा ही। भाजपा और नरेंद्र मोदी पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने बिहारी और बाहरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार को बिहारी ही चलाएगा और मैं ठेठ बिहारी हूं। नीतीश ने लालू के साथ अपनी दोस्ती को भी कभी खत्म न होने देनेवाला करार दिया।

शेष पेज 5 पर

ताकि बहाल रहे विश्वसनीयता

दीपक कुमार राय

बिहार में चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ी हुई है। सारे दल प्रत्याशी और नेता, जनता और प्रशासन भी लोकतंत्र की इस आधार गतिविधि में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका के साथ लगे हुए हैं। दरअसल चुनाव लोकतंत्र में उम्मीदों, आकांक्षाओं और सपनों की अभिव्यक्ति का सबसे प्रामाणिक और सुलभ माध्यम है। साफ सुथरे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी सक्रिय है। और उसकी गतिविधियाँ और उनका परिणाम दिख भी रहा है। जनता भी जागरूक हुई है। और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आश्वस्त भी है।

हाँ, यह जरूर हुआ है कि चुनावी तपिश बढ़ने के साथ-साथ, प्रचार और चुनावी शोर भी बढ़ा है। बयान बाजियों का दौर चला तो मर्यादाएँ भी टूटीं। जुबान फिसली तो शब्दों के चयन में गच्चा खा गए माननीय। कहीं चाराचोर तो कहीं नरभक्षी, कहीं धोखेबाज तो कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव राष्ट्रीय फोकस में हैं। इसमें जीत और किसी भी कीमत पर जीत सभी को चाहिए। कोई दल कोई गठबंधन कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता। हार बरदाश्त ही नहीं। जीत की कोशिशों में जुबानी जंग तेज हुई तो आचार संहिता किनारे कर दी गई। इसी कोशिश में तमाम तरह के प्रलोभन भी दिए जाने लगे। आयोग ने संज्ञान लिया तो एफ.आइ.आर भी हुए। टिकट बंटवारे में भाई-भतीजावाद, जातिवाद से लेकर पैसे के लेनदेन तक के आरोप प्रत्यारोप लगे। अंततोगत्वा ये तमाम चीजें हमारे लोकतंत्र, हमारी चुनाव प्रक्रिया और हमारी राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहीं।

जनता इन चुनावों में अपने जेनुइन मुद्दे तलाश रही है। वह चाहती है कि चुनाव के केन्द्र में उसके मुद्दे रहें। अवसरवाद की राजनीति जनता को अच्छी राजनीति से भी विमुख कर सकती है। हमारी राजनीति और राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि हम विश्वसनीयता बहाल रखें तथा सही अर्थों में नेता होने की योग्यताओं के साथ मतदाताओं के बीच जाएँ।

बेशक पिछले कुछ चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। और बढ़िया बात यह कि यह 'क्वालिटी वोटिंग' है। जरूरत है कि हम जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें।

अंदर के पन्नों पर

समान स्कूल प्रणाली एक साहसिक फैसला

पढ़ें पेज 9

चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले

पढ़ें पेज 10-11

अंधेरों की शिकस्त का दावा करने वाला कवि वीरेन डंगवाल

पढ़ें पेज 13

सप्ताह का फैसला | बम धमाकों के 9 साल बाद सुनाई गई सजा

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में पांच को फांसी, सात को उम्रकैद

मुंबई : 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को सजा सुना दी गई। मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने पांच दोषियों को मौत और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष मकोका न्यायाधीश यतीन शिंदे ने सजा का ऐलान करते हुए, जिन पर ट्रेनों में बम रखने का आरोप था उन्हें फांसी और विस्फोट में मदद करनेवालों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में एक बिहार का निवासी समेत सभी भारतीय हैं। बचाव पक्ष के वकील ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। इससे पहले सभी 12 दोषियों ने पीड़ित परिवारों को पत्र लिखा था और सिस्टम से पीड़ित होने की बात कहकर मदद की गुहार लगाई थी।

मुकदमे की नौ साल चली लंबी सुनवाई के बाद 11 सितंबर को 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गय था, जबकि एक को बरी कर दिया गया था 30 सितंबर को इन्हें सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि इस मामले में 30 पर चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 17 फरार हैं। फरार होनेवालों में 13 पाकिस्तानी नागरिक हैं।

11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 10 मिनट के अंतराल में एक के बाद एक सात विस्फोट हुए थे, इस विस्फोट में 189 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 829 लोग घायल हुए। इस मामले में 30 नवंबर 2006 को आरोपपत्र दाखिल किया गया और 19 अप्रैल 2014 को मामले की सुनवाई पूरी हो गई। इस दरम्यान कुल 192 गवाहों से पूछताछ की गई।

इन्हें सुनाई गई मौत की सजा

कमाल अहम्मद अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुदीन सिद्दीकी, नावेद हुसैन और आसिफ खान।

इन्हें मिली है उम्रकैद

तनवीर अहम्मद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सोहेल महमूद शेख और जमीर अहम्मद शेख।

धमाकों का बिहार कनेक्शन

फांसी पानेवाले पांच दोषियों में एक कमाल अहम्मद अंसारी बिहार के मधुबनी जिले के बासोपट्टी का रहने वाला है। कमाल का परिवार बेहद गरीब है और कमाल मुंबई मजदूरी करने गया था। कमाल को एसटीएफ ने ब्लास्ट को बासोपट्टी से ही गिरफ्तार किया था। सजा सुनाए जाने के बाद कमाल का परिवार लोगों से मिलने में कतरा रहा है। कमाल के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और उसकी पत्नी बच्चों के साथ छोटे से खपरैल के घर में रहती है। सजा के ऐलान के बाद से कमाल की मां गुमसुम है और परिजन कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं।

तकनीकी ज्ञान से समृद्ध होगा भारत Est. 2010
विद्यादान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट
अरियांव, अनुमंडल-डुमरांव, जिला-बक्सर (बिहार)
(ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत तथा आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

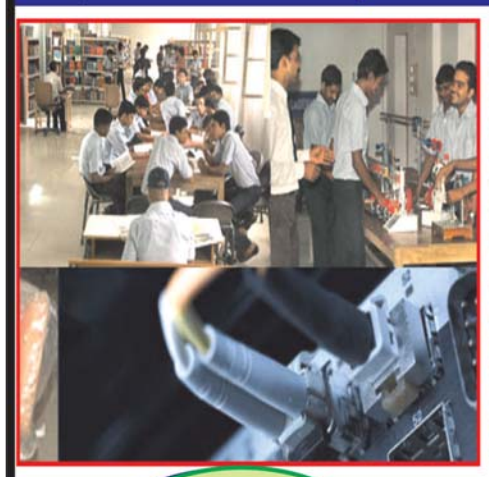

विशेषताएं
- वैज्ञानिकों एवं आई.आई.टी इंजीनियर्स द्वारा स्थापित B.Tech कोर्स की उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा।
- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबंद्ध बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज।
- प्लेसमेंट की व्यवस्था एवं तीसरे वर्ष से ही इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर।

संस्थान द्वारा प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के लिए 15% से 90% तक छात्रवृति एवं सरकार द्वारा SC/ST/OBC के लिए 100% तक छात्रवृति

Branches : ECE, CSE, EEE, IT

2015-16, B.Tech Courses में नामांकन जारी

संपर्क सूत्र :
- संस्थान - 9097432411, 9507411444
- बक्सर: ओशो ऑफसेट (डीएम आवास के सामने, चरित्रवन)- 8863009650, 8002301943
- आरा : परमार कॉम्पलेक्स, पूवी रमना मैदान- 8409256522, 8002301943
- मुजफ्फरपुर : डॉ पी. एन. राय लेन, अपोजिट उमा मार्केट मोतीझील - 9534897559, 9835402060, 8409156797

पटना, 04 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com
गणादेश

मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज

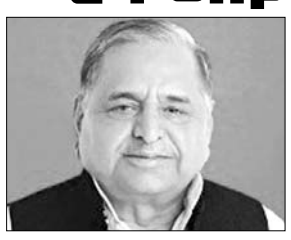

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी चीफ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के स्पेशल वकील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मुलायम सिंह के खिलाफ अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। मुलायम सिंह पर आरोप है कि उन्होंने ठाकुर को फोन पर धमकी दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर अपना जबाव दे रहे थे। चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ही मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस एन शुक्ला की बेंच ने निलंबित आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की रिट याचिका को खारिज कर लिया है। नूतन ठाकुर ने इस मामले में हाई कोर्ट से न्यायिक जांच कराने की प्रार्थना की थी। नूतन ने मुलायम पर सीनियर ऑफिसरों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीनियर वकील जेएन माथुर कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि जल्द ही एफआईआर दर्ज होने जा रही है। अमिताभ ठाकुर के वकील ने अशोक पांडे ने कहा कि कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो नूतन राहत के लिए कोर्ट में फिर से संपर्क साध सकती हैं।

यूएन में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कहा

आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। सुषमा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यूएनजीए में दिए भाषण की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, भारत से बातचीत के लिए उन्होंने जो चार सूत्र बताए हैं उसके जवाब में मेरा तो यही कहना है कि इसके लिए एक ही सूत्र काफी है और वह है आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए।

न्यूयॉर्क : सुषमा ने अपने भाषण की शुरूआत करते हुए कहा, हम 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने जा रहे हैं। किसी के भी जीवन में 70 वर्ष अच्छा पड़ाव होता है। क्या हमने पाया क्या हमने खोया। संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया क्या नहीं किया। विश्व को तीसरे युद्ध से बचाने के लिए, रंगभेद हटाने, गरीबी दूर करने के लिए, लोकतंत्र को बढ़ाने में यूएन सफलता हासिल की है। तमाम जगहों में संघर्ष शांत नहीं कर पाए।

सुषमा ने कहा कि विश्व को तीसरे युद्ध से बचाने के लिए, रंगभेद हटाने, गरीबी दूर करने के लिए, लोकतंत्र को बढ़ाने में यूएन सफलता हासिल की है। तमाम जगहों में संघर्ष शांत नहीं कर पाए। तमाम जगहों पर लोग मर रहे हैं। इन जगहों पर शांति लाने में विफल रहा है यूएन। नीले झंडे के तले तमाम लोग काम कर रहे हैं। 180000 शांतिसैनिक भारत ने उपलब्ध कराए हैं। 8000 तो काफी चुनौती पूर्ण स्थिति में काम कर रहे हैं। हम अपना योगदान बढ़ाने को तैयार हैं। हम ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार हैं।

भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि तमाम राष्ट्र जो इस मिशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं उनकी निर्णय प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। शहीद लोगों की याद में स्मारक बनाने में भारत योगदान देने को तैयार है। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी आतंकी हमला हुआ। तब से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन इन्हें पालने वाले राष्ट्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।

विश्व को दिखाना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जो राष्ट्र आतंकियों की मदद करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 1996 में भारत ने एक प्रस्ताव दिया था लेकिन अभी तक आतंकावाद की परिभाषा तय नहीं हो पाई है। आतंकवाद को कोई वैध हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मुंबई हमले के योजनाकार सरेआम घूम रहे हैं। सीमापार से भारत में हमले हुए हैं और दो में जिंदा आतंकी पकड़े गए हैं। यह आतंकी हमले पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है ताकि कश्मीर पर कब्जा वैध हो सके।

केंद्र का दखल राज्यों को कमजोर कर रहा है : अरविंद केजरीवाल

- मोदी सरकार राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है और न्यायपालिका को भी कमजोर कर रही

नई दिल्ली : केंद्र के साथ अपनी सरकार की खींचतान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के संघवाद को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह विकेंद्रीकरण की मांग की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है और न्यायपालिका को भी कमजोर कर रही है। 'सहयोगात्मक संघवाद' पर अपनी सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने राजग सरकार पर धन के आवंटन में राजनीति करने और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राज्यों को डराने-धमकाने के लिए करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह केंद्र राज्य संबंधों को कमजोर कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल नजीब जंग आप सरकार के 30 आदेशों को अमान्य करार देकर केंद्र के 'एजेंट' की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश के इतिहास में अप्रत्याशित है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में केजरीवाल ने दावा किया कि सिर्फ न्यायपालिका के पास सरकार के आदेशों को अवैध घोषित करने की शक्ति है, बशर्ते वे संविधान के खिलाफ हों। उन्होंने आश्चर्य जताया कि ऐसी स्थिति में अदालतों की क्या आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, 'केंद्र और उपराज्यपाल न सिर्फ राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहे हैं, बल्कि वे न्यायपालिका की शक्तियां भी छीन रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम आदेशों को अमान्य कर देंगे, न कि न्यायपालिका।

ऐसा लगता है कि दिल्ली में न्यायाधीशों की कोई आवश्यकता नहीं है।' दिल्ली सरकार ने सम्मेलन में भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों समेत सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया था लेकिन सिर्फ बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने इसमें हिस्सा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मिजोरम के मुख्यमंत्री लल थनहावला और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने अपनी तरफ से समर्थन का पत्र भेजा।

निर्वाचित सरकारों की सर्वोच्चता की वकालत करते हुए उन्होंने सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्तियों में राज्य सरकारों का भी दखल होने की मांग की। उन्होंने कहा, 'राज्य केंद्र को तीन नामों का एक पैनल भेज सकते हैं, जिसमें से वह किसी एक को चुन सकती है।' केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए 'तीन उपकरणों' का इस्तेमाल कर रही है। ये हैं उपराज्यपाल या राज्यपाल, केंद्रीय जांच एजेंसियां यथा सीबीआई और वित्त।

चुनावों से पहले यूपी में कत्लेआम करवाना चाहती है बीजेपी : आजम

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में हुई अखलाक की मौत के बाद नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। अब यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। आजम खान ने आरोप लगाया कि भाजपा 2017 के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में कत्ल-ए-आम करवाना चाहती है। आजम खान ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को रोकिए। जीवन, राजनीति और पद सदैव के लिए नहीं होते हैं, लेकिन बदनामी हमेशा के लिए होती है। अभी आपके माथे और दामन से 2002 के गुजरात दंगों का दाग नहीं हटा है और रहती दुनिया तक हटेगा भी नहीं। आप अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी हरकतें मत कराइए। ये देश को आप कहां लेजा रहे है।

क्या है पूरा मामला

दादरी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति पर गौ मांस खाने और उसे रखने की अफवाह फैली। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला, जबकि बेटे को लगभग अधमरा कर दिया। पुलिस ने बताया था कि गांव में अफवाह फैली की मोहम्मद अखलाक और उनका परिवार घर में गाय का मांस रखता है और उसे खाता भी है। गांव में अफवाह फैली कि अखलाक बीफ लेकर जा रहा था, तभी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और उसने पॉलीथीन वहीं छोड़ दी। वहीं यह भी आरोप है कि स्थानीय मंदिर से भी इस बात का एलान किया गया कि अखलाक का परिवार गाय का मांस खाता है। एसएसपी किरण एस के मुताबिक इस मामले में मंदिर के पुजारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दस अन्य लोगों के खिलाफ दंगे और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। वहीं गिरफ्तारी के विरोध में गांववालों ने जमकर हंगामा किया था। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें एक युवक घायल हो गया।

राज्यसभा की भूमिका में बदलाव चाहते हैं नकवी

नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा और विधानपरिषद की भूमिका को फिर से परिभाषित करने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में ऐसा करना जरूरी हो गया है। उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि लोकसभा में भारी बहुमत होने के बावजूद सरकार इसलिए कई बिल पारित नहीं करा पा रही है, क्योंकि राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है।

विशाखापत्तनम में 17वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में नकवी ने कहा कि लोग 80 फीसदी तक वोटिंग करके यह उम्मीद करते हैं कि सरकारें जनादेश का सम्मान करेंगी, लेकिन इसके बावजूद जनता के हितों से जुड़े कानून भी सियासत की सूली पर चढ़ जाते हैं। राज्यों में तो कभी-कभार ही विधान परिषदों को लेकर दिक्कत होती है, लेकिन केंद्र में तो सरकार को अक्सर इस तरह के संकट का सामना करना पड़ता है। नकवी का इशारा लैंड और जीएसटी जैसे बिलों की ओर था, जिन्हें मोदी सरकार इसलिए पारित नहीं करा पा रही है क्योंकि लोकसभा में भले ही एनडीए का बहुमत हो, लेकिन राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है।

उन्होंने संसद और विधानमंडलों में कुछ सदस्यों के अशोभनीय व्यवहार का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में एक तरह से राजनीतिज्ञों के प्रति नेगेटिव माहौल बनता है। इससे संसद और विधानमंडलों की साख भी प्रभावित होती है।

यूपी- पंचायत चुनाव के प्रचार में आई तेजी

लखनऊ : पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद यूपी में जिल पंचायत और क्षेत्र पंचायत के पदों के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रचार में तेजी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि संभावित प्रत्याशी तो काफी पहले से ही मतदाताओं को लुभाने की कवायद शुरू कर चुके थे। लेकिन कई क्षेत्रों में पदों के आरक्षित होने की वजह से कईयों को मायूसी का भी सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ तो खुद खड़े न हो पाने के गम को अपने द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार को खड़ा करके हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं को कई मायूसी से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। जो उम्मीदवार पहले से ही तैयारी कर चुके थे वे अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं।

कई जगहों पर प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के भी मामले सामने आए

समय के साथ पंचायत चुनाव में भी प्रचार के रंग ढंग बदलते गए हैं, इस बार के चुनाव प्रचार से इसे आसानी से समझा जा सकता है। खासतौर पर जिला पंचायत सदस्यों के प्रत्याशियों के प्रचार का अंदाज तो विधानसभा के चुनाव प्रचार से होड़ लेता नजर आ रहा है। उपर से जिला पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थित उम्मीदवार खड़ा करने से इसमें राज्यस्तरीय राजनीति का भी तड़का लग गया है। अपनी-अपनी पार्टियों का झंडा, बैनर लगाए महंगी गाड़ियों के काफिले पर सवार उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से प्रचार में वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है और प्रचार को तड़क-भड़क से भरपूर बनाया जा रहा है, उससे इसपर होनेवाले खर्च का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई जगहों पर प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के भी मामले सामने आए हैं। जहां तक जिला पंचायत चुनाव में मुकाबले की बात की जाय तो मुकाबला सपा, बसपा और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के बीच ही दिखाई पड़ता है। हालांकि विधानसभा चुनाव से इतर इसमें प्रत्याशियों का अपना व्यक्तित्व भी मायने रखता है। बहरहाल पंचायत चुनावों में बाजी किसके हाथ लगेगी कहना मुश्किल है, किंतु इस चुनाव को विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों के बीच सेमीफाइनल मैच की तरह से जरूर देखा जा रहा है।

कांग्रेस शासन की एक और योजना मोदी सरकार के टारगेट पर

नई दिल्ली : इंदिरा आवास योजना में बड़े बदलाव के प्रस्ताव को नीति आयोग की हरी झंडी नीति आयोग ने गावों में गरीबों को आवास मुहैया कराने वाली दशकों पुरानी इंदिरा आवास योजना में बड़ा बदलाव करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगले सात सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपये की लागत से 2.95 करोड़ लोगों के लिए घर बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की बात कही है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का नाम बदलकर द नैशनल मिशन फॉर रूरल हाउसिंग (राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन) किया जा सकता है। इस योजना को एक्सपेंडिचर फाइनैंस कमिटी ने अनुमति दे दी है। अब इसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, स्कीम को अधिकतम दो महीनों में मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद मिनिस्ट्री स्कीम के तहत सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर पात्र लाभार्थियों की सूची जारी करेगी। अधिकारी ने बताया कि स्कीम की फंडिंग पूरी तरह से केंद्रीय बजट के जरिए होगी और मिनिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि यह पैसा लाभार्थियों के पास समय से पहुंचे। इस योजना की फंडिंग मैदानी राज्यों में केंद्र और राज्य 75:25 और पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में करते हैं। अधिकारी ने कहा, मिनिस्ट्री ने नई स्कीम में भौगोलिक स्थितियों के अनुसार घरों के लिए लोकल डिजाइन तैयार करने और कंस्ट्रक्शन के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध मटीरियल का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार स्कीम को लागू करने और इसकी निगरानी के लिए एक ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाना चाहती है। इसके तहत तेज रफ्तार से काम करने के मकसद से सरकार की योजना इंस्टीट्यूशनल या विदेशी सॉवरेन फंडिंग हासिल करने की भी है।

इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। इसके तहत अभी तक लगभग एक लाख करोड़ रुपये के खर्च से 3.25 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के लिए प्रस्तावित बदलावों में घरों का साइज 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर करना, घर में अनिवार्य तौर पर टॉयलेट बनाना, प्रति यूनिट लागत को बढ़ाना और पुरानी स्कीम के स्टैंडर्ड ब्लॉक डिजाइन को समाप्त करना शामिल है।

राम मंदिर निर्माण की बाधा को दूर करे केंद्र सरकार : विहिप

नई दिल्ली : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह अयोध्या में मुख्य स्थान पर भगवान राम का मंदिर निर्माण सुनिश्चित कराने के रास्ते की सभी बाधाएं एक साल के भीतर दूर करे। विहिप ने यह मांग भी की कि राम मंदिर के निर्माण का जायज अधिकार राम जन्मभूमि न्यास का दिया जाना चाहिए।

विहिप के संरक्षक अशोक सिंघल ने यहां एक संवददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार एक वर्ष में बाधाएं दूर करने के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करे। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी राम जन्मभूमि न्यास को दी जानी चाहिए, क्योंकि इसने तीन लाख पत्थर पहले से तैयार कर रखे हैं और उसे संतों का समर्थन प्राप्त है। सिंघल ने यह भी कहा कि सरकार मस्जिद निर्माण के लिए कोई दूसरा स्थान पेश करे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि मंदिर के बगल में एक मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन मामले के दोनों पक्षों ने उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की, जहां मामला अभी लंबित है। भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी भी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा नहीं है और इसलिए सरकार को प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

उन्होंने भाजपा नेतृत्व से आग्रह किया कि उसे लोकसभा चुनाव के दौरान इस संदर्भ में किए गए वादे पूरे करने चाहिए। विहिप ने नौ-10 जनवरी को इस मुद्दे के समाधान पर चर्चा के लिए हिंदू संगठनों और संतों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी बुलाई है।

अयोध्या आंदोलन आजाद भारत के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक : राजनाथ

लखनऊ : गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रामजन्मभूमि आंदोलन को आजाद भारत के दो बड़े आंदोलनों में शामिल किया है। विश्व हिंदू परिषद(विहिप) प्रमुख अशोक सिंघल के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहाकि, रामजन्मभूमि आंदोलन के समय सिंघल के भाषणों में जो ओज होता था वो मैं आज भी महसूस करता हूं। राजनाथ ने पहले नंबर पर जयप्रकाश नारायण आंदोलन को रखा। इस दौरान राजनाथ ने इस बात से इनकार किया कि मंदिर आंदोलन के चलते देश के कई भागों में दंगे हुए। उन्होंने कहाकि हिंदुत्व जाति और समुदाय से परे है।

लाइव कवर स्टोरी

हो रही ऑक्सीजन के अभाव में मौते

व्यवस्था की बदहाली और कर्मचारियों की लापरवाही

राज्य के दरभंगा जिले में ऑक्सीजन के अभाव में पिछले दिनों तीन मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं, 17 सितबंर को पीएमसीएच पटना में एक नौ वर्षीय बालक की भी ऑक्सीन नहीं मिलने से मौत हो गयी। इन दोनों घटनाओं में कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई है। जिसके कारण ऑक्सीन रहने के बाद भी रोगियों को मौत की नींद सोना पड़ा।

पटना/बक्सर : कर्मचारियों की लापरवाही कमोबेश हर जगह दिख रही है। जिसके कारण मरीजों को केवल परेशान ही नहीं होना पड़ता है, बल्कि जान भी गवानी पड़ती है। अस्पतालों में दलालों की सक्रियता से भी मरीज परेशान है। सूत्र बतातें हैं कि अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी ही दलालों की सक्रियता बढ़ाने में मदद करते हैं। जिससे दलालों के चंगुल में मरीज फंस जाते हैं और चिकित्सा के नाम पर लाखों रुपये ठगे जाते हैं।

यहां हुई मौतें

घटना 1-पटना पीएमसीएच में 18 सितंबर को नौ वर्षीय रौशन की मौत हो गयी। रौशन के पिता मजदूर हैं। वे इस मौत के लिए पूरी तरह कर्मचारी को जिम्मेवार मानते हैं। रौशन के पिता सुरेंद्र साव ने बताया कि ऑक्सीन आपूर्ति के लिए उनसे कर्मचारी ने यूस मांगा था, जिसे वे नहीं दे पाये। इस संबंध में सुरेंद्र साव ने पीरबहोर थाना में कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। हालांकि इस बात से कर्मचारी ने इंकार किया है। बालक की मौत के बाद थोड़ी सी हो हल्ला मची फिर मामला स्थिर हो गया।

घटना 2-डीएमसीएच दरभंगा में गैस आपूर्ति बंद होने से तीन लोगों की मौत हो गयी। मरने वालों में उमेश महतों की तीस वर्षीय पत्नी रानी देवी, मुज्जफरपुर के छतरी सहनी की 68 वर्षीय पत्नी चंपा देवी व मधुबनी मधवापुर के मो. अब्दुल्लाह की चालीस वर्षीय पत्नी शबनम खातून शामिल हैं। बताया जाता है कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वे अपनी ड्यूटी समाप्त कर चले गये जबकि दूसरे पाली के कर्मचारी नहीं आये और कर्मचारी चलाा गया। जिसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति एका-एक ठप हो गयी और मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद प्रथम पाली के कर्मचारी अमलेश प्रसाद को अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार मिश्रा ने जहां निलंबित कर दिये हैं वहीं, दूसरे पाली के अन्य दो कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा और इनके वेतन पर तत्काल रोक लगा दी है।

पहले भी हुई है लापरवाही

केस वन- अगस्त 2014 को पीएमसीएच में एक कर्मचारी ने बच्चे के मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा लिया था। परिजन का कहना था कि कर्मचारी ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अवैध पैस की मांग की थी। जिसे वे देने में सक्षम नहीं थे। घटना के बाद इसकी जांच हुई और इस मामले में दो लोगों को निलंबित किया गया।

केस टू-अगस्त 2014 में ही एनएमसीएच में भी ऑक्सीजन के अभाव में एक बच्चे की मौत हो गयी थी। घटना की जांच के लिए एक जांच कमिटी बनाई गयी। हालांकि कमिटी ने जांच में बच्चे की मौत का कारण ऑक्सीजन का अभाव नहीं माना और इसमें किसी पर कार्रवाई नहीं हुई।

केस थ्री-जुलाई 2015 में भागलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रंजन बासुकी की बगैर ऑक्सीजन के मौत हो गयी थी। इलाज के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति ठप थी। इस घटना के बाद काफी हो-हल्ला मचा था।

मौत का कारण ऑक्सीजन आपूर्ति ठप नहीं : डॉ. बीके सिंह

डीएमसीएच में ऑक्सीजन से तीन मरीजों की मौत के बाद काफी हो-हल्ला मचा। परिजन बताते हैं कि करीब सवा घंटे तक ऑक्सीजन आपूर्ति बंद रही और कोई भी कर्मचारी नहीं आया। यदि कर्मचारी आते तो मरीजों की जानें बच सकती थी। पर ठीक इसके विपरीत मेडिसीन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. बीके सिंह ने मरीजों की मौत का जिम्मेवार ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं माना। डॉ. श्री सिंह ने बताया कि मरीज काफी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे जिसके कारण उनकी मौत हुई है। परिजनों को पहले ही किसी अन्य अस्पताल में ले जाने को कहा गया था। पर वे नहीं ले गये जिसके कारण उनकी मौत हो गयी।

जानें कैसे भराता है ऑक्सीजन

राज्य के सभी जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ऑक्सीजन सीलिंडर की रीफिलिंग पटना के बाइपास रोड स्थित उषा एयर प्रोडक्ट प्लांट से कराया जाता है। यहां प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालें रीफिलिंग करती हैं। एक सीलिंडर में 5 सीएम ऑक्सीजन को भरा जाता है। जिसका खर्च 75 रुपया पड़ता है। एक सीलिंडर करीब 4 घंटे तक चलता है।

बक्सर का क्या है हाल

सदर अस्पताल बक्सर की बात करें तो यहां भी ऑक्सीजन को लेकर कुछ हालात ठीक नहीं नजर आते हैं। यह संयोग ही रहा है कि यहां अब तक ऑक्सीजन के अभाव में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सदर अस्पताल में करीब 35 से 40 ऑक्सीजन सीलिंडर हैं। सभी को स्टोर रूम में रखा जाता है। स्टोर रूम की जिम्मेवारी एक भंडारपाल के जिम्मे हैं। जिसकी ड्यूटी 24 घंटे रहती है। पर अचानक कभी किसी काम से जब भंडारपाल बाहर चला जाता है और इसी समय कोई मरीज आ जाता है तो भंडार में रखे मेडिकल किटों को उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अस्पताल के कर्मी भंडारपाल को तुरंत सूचित कर बुला लेते हैं। हालांकि भंडारपाल सभी आवश्यक दवाइयों और ऑक्सीजन को प्रर्याप्त मात्रा में सभी जरूरी वार्डों में हमेशा रखता है। शायद ही कभी भूलवश यदि ऑक्सीजन या अन्य आवश्यक जरूरत की चीजों को नहीं रख पाने की स्थिति में ही परिजन को परेशानी होती है। अस्पताल के कर्मी बताते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। बक्सर जिले के सभी पीएचसी में भी दो-दो ऑक्सीजन सीलिंडर उपलब्ध कराया गया है। ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। चिकित्सक बताते हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जिले में कभी भी परेशानी नहीं हुई है। विशेष परिस्थिति में मरीजों को बक्सर रेफर कर दिया जाता है। जिससे स्थिति को कंट्रोल किया जाता है।

क्या कहते हैं अस्पताल प्रबंधक

अस्पताल प्रबंधक चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि सदर अस्पताल बक्सर में ऑक्सीन सीलिंडर प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। सीलिंडर खत्म होने से पहले ही उसे भरा लिया जाता है। भंडारपाल सभी वार्डों में ऑक्सीजन को रख देता है और सभी की समय-समय पर जांच भी होती रहती है। इसीलिए यहां ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है।

विडंबना

इनसान के लिए ऑक्सीजन काफी महत्वपूर्ण है। इसके बिना लोगों की जान निकल जाती है। इसी का फायदा उठा कर निजी अस्पतालों में तीन सौ से चार सौ रुपया प्रति घंटा ऑक्सीजन की आपूर्ति मरीजों की जाती है। जबकि इस पर खर्च रीफिलिंग और भाड़ा खर्च को लेकर महज सौ रुपया ही पड़ता है। सूत्र बताते हैं कि पांच सौ रुपये में ऑक्सीजन सीलिंडर की अवैध रीफिलिंग जिले में होती है। जिस पर प्रशासन की अब तक नजर तक नहीं पड़ी है। ऐसे में जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन पूरी तरह मौन है। जिसके फलस्वरूप मरीजों की आर्थिक दोहन जारी है।

गणादेश की खबर का असर

तीन किसान सलाहकारों पर प्राथमिकी

बक्सर : जिले में डीजल अनुदान में किसान सलाहकारों की गड़बड़ी को लेकर पिछले अंक में गणादेश सप्ताहिक अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी के पहल पर डुमरांव में तीन किसान सलाहकारों पर बीडीओ जनार्दन तिवारी ने डीजल अनुदान में हेरा-फेरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। बीडीओ ने बीएओ के माध्यम से इनसे स्पष्टीकरण की मांग भी की। इस मामले में बीएओ ने तीनों किसान सलाहकारों को तीन दिनों के अंदर गबन की राशि जमा करने का आदेश दिया था।

जिसका पालक किसान सलाहकारों ने नहीं की है। जिसके बाद इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस घटना से अन्य किसान सलाहकारों में हड़कंप मचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि मठिला पंचायत के किसान सलाहकार कन्हैया लाल श्रीवास्तव, कुशलपुर पंचायत के किसान सलाहकार हरेंद्र सिंह एवं मुंगाव पंचायत के किसान सलाहकार सुग्रीव कुमार पर डीजल अनुदान का लगभग चार लाख रुपया गबन का आरोप है। इन किसान सलाहकारों में सबसे अधिक राशि की हेराफेरी मठिला पंचायत के किसान सलाहकार ने की है।

मालूम हो कि जिले में बारिश कम होने से खेती पर असर नहीं हो इसके लिए किसानों को डीजल अनुदान दिया गया पर किसान सलाहकारों ने जहां एक तरफ किसानों को डीजल अनुदान देने मे लापरवाही बरते तो वहीं, इस मामले में राशि की हेरा-फेरी कर गबन भी किये हैं। यदि किसान सलाहकारों की लापरवाही की जांच हो, तो अभी कई मामले सामने आ सकते हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

गणादेश
पटना, 27 सितंबर - 03 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com
पड़ताल 03
लाइव कवर स्टोरी
डीजल अनुदानः ये क्या हुआ!
हाल राजधानी का
19 जिलों में 46 प्रतिशत तक कम हुई बारिश
27 हजार 736 आवेदन रद
किसानों का हाल

गणादेश
जन गण मन... साप्ताहिक
साप्ताहिक समाचार पत्र गणादेश
के लिए बिहार भर में हर जिले में संवाददाताओं तथा वितरकों की आवश्यकता है।
विज्ञापनदाता भी संपर्क करें...
प्रसार प्रबंधक :- बिमल कुमार सिंह
9473150509, 8409674858
गणादेश, बिहार

Since - 2004
Join No.1 Institute
ZENITH
ENGLISH
(Spoken/ Grammar/ Competitive/ 10+2)
By- B.K.Singh
CHEMISTRY
(For - 11th, 12th & B.sc)
By- S.K. Mishra

Add- Opp. L.B.T College
Chini mill, Buxar
Mob- 9204521029
Email- bimalzenith@gmail.com
Head office - Near Foundation School, Gurudas Mathia, Buxar

पटना, 04 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com
गणादेश

सालों बाद भी नहीं बनी छपरा से मढ़ौरा की सड़क

❍ मढ़ौरा, तरैया और अमनौर प्रखंड के सैकड़ों गांवों के लोग आज भी हैं परेशान

मढ़ौरा : देश-दुनिया लगातार तरक्की कर रहा है। पर आज भी छपरा जिले का मढ़ौरा गांव की स्थिति खराब है। मढ़ौरा जाने से जिला मुख्यालय जाने की सड़क वर्षों बाद भी नहीं बन पायी। इतने वर्षों में यहां कई राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि चुने गये पर सभी ने सिर्फ वोट की राजनीत की। सड़क नहीं बनने के कारण जिला मुख्यालय से मढ़ौरा का डगर मुश्किल भरा बन गया है।

मढ़ौरा बाजार से लेकर खैरा तक यह सड़क खस्ता हाल है। वाहनों को कौन कहे पैदल चलने में भी दुर्घटना का भय लोगों को सताते रहता है। इस मुख्य पथ के जर्जर हालात से मढ़ौरा, तरैया अमनौर प्रखंड के सैकड़ों गांवों के हजारों लोग वर्षों से जूझ रहे हैं। छपरा-थावे छोटी लाइन रेल सेवा बंद है और यहां के लोगों का जिला मुख्यालय तक जाने का यही सड़क विकल्प है।

लेकिन इसके हालात ऐसे हो गए हैं कि यात्रा करने से लोग खतरे के अंदेशा से सहम रहे हैं। बावजूद जान जोखिम में डाल लोग हर दिन यात्रा करने को मजबूर हैं।

सड़क बनाने का सिर्फ करते हैं वादा

सड़क के बदहाली को लेकर यहां के लोगों में काफी आक्रोश देखा जाता है। लोग बताते हैं कि जब चुनाव आता है तो राजनेता सड़क बन जाने का भरोसा देते हैं पर चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सड़क बनाना भूल जाते हैं। लोग प्रशासनिक, राजनैतिक उदासीनता को जिम्मेवार बताते हैं। लोगों का आरोप है कि जब यहां के विधायक सत्ता से बाहर थे तो सड़क को लेकर उदासिन रहे। सत्ता में आने के बाद भी सड़क को नहीं बनाया। वहीं अनुमंडल मुख्यालय होने के बावजूद प्रशासनिक पहल नहीं हुई और इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका।

16 फुट चौड़ी बननी है सड़क

पथ निर्माण विभाग ने इस सड़क के निर्माण को लेकर पिछले जुलाई माह में टेंडर निकाला। लेकिन टेंडर केवल एक ठेकेदार ने ही भरा। इसलिए टेंडर रद्द हो गई। फिर अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में टेंडर निकला, जो अभी प्रक्रिया में है। टेंडर के हिसाब से खैरा से मढ़ौरा तक यह सड़क 16 फुट चौड़ी बननी है, जिसका अनुमानित लागत 27 करोड़ है।

यात्री परेशान

छपरा-मढ़ौरा की दूरी 25 किमी है। लेकिन सफर डेढ़ घंटे से अधिक समय में पूरा होता है। छपरा के लिए निकलने वाले लोगों का पूरा दिन आने-जाने में ही गुजर जाता है। सुबह यदि किसी काम से छपरा जाना है तो आप जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए उन्हें या तो छपरा में रुक जाना पड़ता है या फिर एक दिन पहले निकलना पड़ता है।

> मढ़ौरा-छपरा रोड के हालात जर्जर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव अवधि में इस सड़क को परिवहन के योग्य बनाने की पहल विभागीय स्तर पर की जाएगी। चुनाव के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा।
>
> **संजय कुमार राय, एसडीओ, मढ़ौरा**

पूर्णिया में नगर निगम का बढ़ा हुआ टैक्स अब तक नहीं हुआ वापस

❍ बढ़े हुए टैक्स से शहरवासियों में काफी आक्रोश

❍ नगर निगम ने 28 अगस्त को बैठक की और बढ़ा हुआ टैक्स वापस लिया था

पूर्णिया : नगर निगम ने अब तक बढ़ाया हुआ टैक्स वापस नहीं ले पाया है। जिसके कारण शहरवासियों में काफी आक्रोश है। उल्लेखनीय है कि इस विरोध के दबाव में आकर नगर निगम बोर्ड ने 28 अगस्त को बैठक की और तय हुआ था कि बढ़ा हुआ टैक्स वापस लिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी भी बढ़ा हुआ टैक्स ही लागू है। क्योंकि यहां जिन लोगों ने बढ़े हुए टैक्स को वापस लिया उनको वापस लेने का अधिकार ही नहीं है और जिनको अधिकार है उन्होंने इनके फैसले को एप्रुवल नहीं किया है। दरअसल नगर निगम को पत्र आया था कि जिस नगर पालिका ने पिछले पांच साल से टैक्स को नहीं बढ़ाया है वो बढ़ा लें। कम से कम पंद्रह प्रतिशत बढ़ाया जाए या फिर कार्यालय खर्च और शहर के विकास को देखते हुए टैक्स तय किया जाए। जो भी टैक्स तय हुआ उसे एप्रुवल के लिए नगर विकास पटना को भेजने से पहले नई दर को कई जगहों पर नोटिस लगा कर चिपका दिया गया कि अगर किसी को इससे ऐतराज हो तो बताएं। लेकिन इसके विरोध में एक भी शिकायत नहीं आई। उसके बाद इस आशय की एक चिट्ठी के साथ बढ़े हुए टैक्स को एप्रुवल के लिए नगर विकास ऑफिस पटना भेज दिया गया। एक अप्रैल 2005 से बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लागू कर दिया गया। पांच महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। शहर के लोग बढ़े हुए टैक्स को जमा भी करते रहे। इसके बाद अचानक बढ़े हुए टैक्स के विरोध में शहर उबलने लगा। मालूम हो कि किशनगंज में पांच वर्ष पहले होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की लेकिन वहां निगम अब तक इसे लागू नहीं करा पायी है।

क्या कहते हैं मेयर

यह रेवेन्यू का मामला है। नगर विकास कार्यालय ही तय करेगा। टैक्स को कम करने के लिए सड़कों का वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे मुख्य प्रधान सड़क और प्रधान सड़क। इससे टैक्स कम हो जाएगा। आवासीय इलाकों में भी वर्गीकरण किया जाएगा।

कनीजरजा, मेयर

अनंत सिंह से जेल में हुई तीन घंटे पूछताछ

पटना : पूर्व विधायक अनंत सिंह से सीबीआइ की टीम की एक विशेष बेऊर जेल में करीब तीन घंटे तक पूछताछ की. । दिल्ली से आयी सीबीआइ की इस टीम में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी मौजूद थे। अनंत सिंह से खासतौर से बाढ़ एनटीपीसी में हुए टेंडर घोटाला से जुड़ी बातों पर गहन पूछताछ हुई।

सीबीआइ अपने साथ एनटीपीसी से जुड़े कई दस्तावेज भी लेकर आये थे, जिन्हें दिखा कर पूर्व विधायक से कई तरह के सवाल किये गये। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अनंत सिंह ने इस मामले में क्या-क्या जवाब दिये हैं। यह पूछताछ इतनी गुप्त थी कि किसी पुलिस अधिकारी तक को आसपास नहीं रहने दिया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एनटीपीसी में पिछले 10 साल के दौरान जितने ठेके या टेंडर हुए हैं, उनमें से पूर्व विधायक समेत अन्य बाहुबलियों को सिर्फ काम मिला है। इन बाहुबलियों की कंपनियों या चहेतों को मनमाने तरीके से टेंडर दे दिया गया. इस तरह की तमाम बातों पर सीबीआइ ने पूर्व विधायक से पूछताछ की। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि उस दौरान जितनी बाहरी या दूसरे राज्यों की बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां टेंडर लेने आयी थीं, उन सभी को डरा कर भगा दिया गया। पूरा काम अनंत सिंह समेत कुछ अन्य बाहुबलियों ने ही किया है।

3.5 करोड़ का घोटाला

शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आयी है कि एनटीपीसी में टेंडर घोटाला 3 से 3.5 ह्जार करोड़ के आसपास का है। इसमें बड़े स्तर पर स्थानीय बाहुबली और कुछ अन्य नामचीन लोग शामिल हैं। इस मामले में सीबीआइ फिर से नयी एफआइआर करने की तैयारी में है, जिसमें अनंत सिंह समेत अन्य दर्जनभर बाहुबलियों को मुख्य आरोपित बनाया जा सकता है। इस कड़ी में अनंत सिंह से हुई यह पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बेलागंज विधायक पर रंगदारी की प्राथमिकी

पटना : बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव के खिलाफ ठेकेदार अरुण कुमार (नीलगिरी अपार्टमेंट 406 नंबर फैलट, श्रीकृष्णापुरी) ने श्रीकृष्णापुरी थाने में रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज करा दी। दिन में 3.15 बजे ठेकेदार के मोबाइल फोन नंबर 9470418244 पर धमकी भरा फोन आया और फोन करनेवाले ने खुद को सुरेंद्र यादव बताया और कहा कि शनिवार को लघु सिंचाई प्रमंडल गया द्वारा बेलागंज के चिरमिच्ची बिगहा के वीयर में छह करोड़ 94 लाख के टेंडर में भाग न लें और अगर लेते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे. इस धमकी भरे फोन के आने के बाद अरुण कुमार प्राथमिकी दर्ज करायी। उनके लिखित आवेदन पर आइपीसी की धारा 387 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ठेकेदार को सरकारी अंगरक्षक भी प्रदान कर दिया गया है और मामले की खुद सिटी एसपी मध्य चंदन कुमार कुशवाहा जांच करेंगे. एसएसपी विकास वैभव ने मामला दर्ज किये जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।

त्योहार को लेकर बाजार गुलजार, लुभा रहे कपड़ों के नए डिजाइन

पटना : दुर्गापूजा त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह सज गयी है। लोग अब खरीदारी भी शुरू कर दिये हैं। दुकानदार इस बार युवक, युवतियों, महिलाओं और बच्चों के च्वाईस पर ज्यादा ध्यान दिये हैं। पटना के बाजार में सरगर्मी बढ़ चुकी है। कपड़ों की बिक्री अचानक बढ़ गई है। पटोला साड़ी से लेकर लखनवी सलवार सूट और पंजाबी सूट से लेकर ब्रांडेड क्लोथिंग की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ने लगी है। बच्चों के लिए ब्रांडेड से लेकर लोकल ब्रांड की दुकानों तक नये-नये डिजाइन के कपड़े उतारे गए हैं।

कांचीपुरम की साड़ियों की है मांग

बोरिंग रोड की कुछ दुकानों ने पटोला साड़ी का विशेष कलेक्शन उतारा है। इसे हाथ से दोनों तरफ महीन काम करके तैयार किया जाता है। मूलरूप से गुजरात की इस साड़ी की कीमत पांच हजार रुपए से शुरू है। बोरिंग रोड की इक्का-दुक्का दुकानों में ही यह उपलब्ध है। इसे बनाने के लिए रेशम के धागों पर डिजाइन के मुताबिक वेजीटेबल और केमिकल कलर से रंगाई की जाती है, फिर हैंडलूम पर बुनाई का काम होता है। हालांकि, अब मशीन से भी इससे मिलती-जुलती साड़ियां बनने लगी हैं, जो उसके मुकाबले सस्ती हैं। पारंपरिक साड़ियों में बनारसी साड़ी, साउथ सिल्क और तमिलनाडु की कांचीपुरम साड़ी की मांग बनी हुई है।

सर्राफा बाजार

सर्राफा बाजार की रौनक भी धीरे-धीरे लौटने लगी है। इस सप्ताह लगातार सोने का दाम घटा है। जिन लोगों ने पिछली बार भाव कम के बावजूद इंतजार में मौका गंवा दिया था वे इस बार बाजार पहुंचने लगे हैं। बाकरगंज के रमेश सर्राफ कहते हैं कि दुर्गापूजा, दीपावली में बिक्री बढ़ेगी। कई लोग लगन की खरीदारी भी करने लगे हैं, क्योंकि सभी को कीमतें कम होने का इंतजार था।

> आशियाना नगर की शालिनी बताती हैं कि वे जबतक 3-4 मार्केट घूम नहीं लेंगी, तबतक पूजा की शॉपिंग पूरी नहीं होगी। पटना मार्केट की एक प्रतिष्ठित दुकान ने सुप्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई की चित्रकला पर आधारित कांचीपुरम की मशहूर साड़ियां और नई-नई डिजाइन में सलवार-कुर्ते को डिस्पले में लगाया है। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर कहते हैं कि हर पांच-छह साल पर फैशन और चाहतें भी दोहराती हैं।

शेष पेज 1 पर

चुनाव अभियान ने पकड़ा जोर, प्रचार में उतरे दिग्गज

वहीं लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण खत्म करने की वकालत करने वाले बयान को अपने भाषणों में मुद्दा बनाकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने खुद को गरीबों और पिछड़ों के हितों का रक्षक बताते हुए उनकी लड़ाई हमेशा लड़ने की बात कही। लालू प्रसाद यादव के निशाने पर मोदी भी खूब रहे। लालू प्रसाद ने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, किंतु गरीबों की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। हालांकि महागठबंधन के अन. नेताओं ने भी चुनाव सभाओं में शिरकत की, किंतु महागठबंधन की तरफ से शनिवार को हुई सोनिया गांधी की रैली के अलावा यही रहे।

आरके सिंह के भाजपा पर टिकट बेचने के आरोप से मची खलबली

टिकट बंटवारे से नाराज आरा से भाजपा सांसद आरके सिंह ने भाजपा पर पैसे लेकर अपराधियों को टिकट बेचने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी। भाजपा नेता और सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आरके सिंह का समर्थन करके अपनी पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया। बयान से मुश्किल में पड़ी भाजपा सिंह के बयान का खंडन करने में जुट गई, किंतु तबतक विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल गया।

आक्रोशित छात्राएं सड़क पर उतरीं मना करने पर गृहरक्षकों को दिखाया तमाचा

❍ खराब भोजन और कुव्यवस्था से थीं नाराज

❍ एसडीओ की पहल पर टूटा जाम

जहानाबाद : स्कूल की लचर व्यवस्था से नाराज सैकड़ों आवासीय छात्राएं अहले सुबह सड़क पर उतर आयीं। काको प्रखंड के दक्षिणी गांव में संचालित भीमराव अंबेदकर बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं स्कूल के गेट का ताला तोड़ निकल गयीं। गृहरक्षकों ने ताला तोड़ने से रोका तो उन्हें भी तमाचा दिखाया गया। आक्रोशित छात्राओं के आगे बेवश दिखे गृहरक्षक। छात्राओं ने करीब दो घंटे तक जहानाबाद-घोसी मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर आवागमन को ठप कर दीं । सूचना पर जहानाबाद एसडीओ मनोरंजन कुमार वहां पहुंचे। आक्रोशित छात्राओं को बेहतर व्यवस्था का वादा कर पहले सड़क जाम हटवाया। हालांकि उन्हें भी छात्राओं को सड़क से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

छात्राओं की परेशानी बारिकी से सुनकर दूर करने का ठोस आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने भी कबूल किया कि छात्राओं की शिकायत है कि कई दिनों से स्कूल में अच्छे भोजन नहीं परोसे जा रहे जबकि पहले बेहतर भोजन मिलता था। कई दफा इसकी शिकायत अधीक्षक और रसोइया से की जाती रही। मगर मामला जस का तस रहा. बीती रात रसोइया द्वारा छात्राओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया. जिससे छात्राएं खिन्न हो गयीं और गोलबंद होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। हाल के कई दिनों से खराब भोजन का विरोध छात्राएं कर रहीं थी। मगर सुधार नहीं होता देख छात्राओं का मिजाज बदला और खाने से भरी टोकरी पलट डाली। इन दिनों जो सब्जियां बच्चियों को परोसी जा रही थी वो खाने लायक नहीं थी. जिसकी शिकायत फिर से खाना बनाने वाली उपलब्ध कराने वाली संस्था के मुंशी से की गयी. बस मुंशी की शिकायत सुनकर भड़क गया और अपनी भड़ास छात्राओं पर निकाल डाली।

मुंशी भी करता था दुर्व्यवहार

स्कूली छात्राओं का आरोप है कि मुंशी ने कई छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया था जो आग में घी काम किया।

पूर्व से ही नाराज छात्राएं मुंशी द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने से और भी आक्रोशित हो गयीं। तथा अपना आक्रोश जताने के लिए गुरुवार की अहले सुबह विद्यालय के मुख्य द्वार में लगा ताला तोड़कर सड़क पर उतर गयीं तथा स्कूल की व्यवस्था के खिलाफ जम कर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान करीब दो घंटे तक दक्षिणी स्थित विद्यालय के समीप सड़क जाम रहा। जिससे जहानाबाद-घोसी मुख्य पथ पर यातायात बाधित रहा। छात्राओं का यह भी आरोप था कि विद्यालय में कई विषयों के शिक्षक नहीं है जिसके कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है।

एसडीओ की पहल पर टूटा जाम

डा. भीमराव अंबेदकर बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा सड़क जाम किये जाने की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी मनोरंजन कुमार दक्षिणी गांव पहुंच सड़क पर उतरी छात्राओं को मनाने में जुट गये। हालांकि छात्राएं काफी आक्रोशित थीं। काफी प्रयास के बाद तथा विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ करने का वादा करने के बाद छात्राएं एसडीओ की बात मानी तथा वे सड़क से हटने को तैयार हुईं। छात्राओं को सड़क से हटाकर विद्यालय पहुंचाया गया। उसके बाद एसडीओ द्वारा मामले की गहन जांच की गयी। आखिर छात्राएं सड़क पर क्यों उतरी, इस मामले को लेकर एसडीओ ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक से लेकर अधीक्षक तक से विस्तार से जानकारी ली। एसडीओ ने विद्यालय अधीक्षक की लापरवाही को दर्शाते हुए कहा कि अधीक्षक ने जानकारी दी थी कि छात्राओं को घटिया भोजन दिये जाने के कारण आवाज बुलंद किया गया है। लेकिन समय रहते अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण छात्राएं सड़क पर उतरीं।

जेनरिक दवा नहीं लिखते डॉक्टर, मरीज परेशान

पीएमसीएच में दवाओं की किल्लत से खरीदनी पड़ रहीं महंगी दवाएं

पटना : दवा नहीं रहने से जहां मरीजों को परेशानी हो रही है, वहीं इसका फायदा दवा कंपनियों के एजेंट को मिल रहा है। वे ओपीडी व इमरजेंसी में डॉक्टरों से मनचाही महंगी दवा लिखवाते हैं और इसका फायदा डॉक्टरों की जेब में जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने गरीबों को सस्ती दवा देने के लिए सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जेनरिक दवा की दुकानें खुलवायीं, लेकिन वहां उपलब्ध दुकानों की दवा डॉक्टर नहीं लिखते हैं।

ओपीडी के समय भी पहुंच जाते हैं एमआर

सूबे में दवा की किल्लत का फायदा कंपनियां उठा रही हैं। एमआर अस्पतालों में ओपीडी के समय पहुंच जा रहे हैं। इसके कारण मरीजों को काफी परेशानी होती है।

लेकिन, इसका गम डॉक्टर व अस्पताल प्रशासन दोनों को नहीं है। गौरतलब है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट निर्देश है कि ओपीडी के बाद एमआर डॉक्टर के चैंबर में जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है।

पीएमसीएच तक में दवा की किल्लत

पीएमसीएच सहित शहरी अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। इस कारण से ओपीडी व इमरजेंसी में मरीजों को डॉक्टर सिर्फ बाहर की दवा लिख रहे हैं।

एक नजर

यूनिसेफ की नसीहत- बच्चों की रिपोर्टिंग में सावधानी रखे मीडिया

पटना : रिपोर्टिंग करते वक्त सनसनी फैलाने और खबर की तह तक पहुंचने के नाम पर तमाम हदों को लांघने वाली मीडिया को आइना दिखाते हुए यूनिसेफ ने कहा कि बच्चों की रिपोर्टिंग के दौरान मीडिया को सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों से संबंधित रिपोर्टिंग के नीतिपरक सिद्धांत को मीडिया के लिए जारी करते हुए यूनिसेफ ने कहा कि बच्चों से उन्हें खतरे में डालने वाले, उन्हें पीड़ा या सदमे की याद दिलाने वाले सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। यूनिसेफ के मुताबिक यौन प्रताड़ना के शिकार, एचआईवी पॉजीटिव, किसी अपराध का अभियुक्त या दोषी ठहराए गए बच्चों के नाम बदल देने चाहिए तथा उनकी तस्वीर धूमिल कर देनी चाहिए। बच्चों से इंटरव्यू और फोटोग्राफी के लिए अभिभावक की अनुमति ले लेनी चाहिए। यूनिसेफ के मुताबिक रिपोर्टिंग के दौरान बच्चों की निजता के अधिकार का आदर करना चाहिए।

सीतामढ़ी में पत्रकार की हत्या

सीतामढ़ी : बिहार समेत पूरे देश में मीडिया पर हमले रूकने का नाम नहीं ले रहे। मंगलवार को सीतामढ़ी में स्वतंत्र पत्रकार और समाजसेवी अजय विद्रोही को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अजय की अस्पतास जशाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने अजय को उनके घर के नजदीक अपने पास बुलाया और गोली मार दी। पत्रकार की हत्या से क्षुब्ध बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, व्यवसायियों समेत अन्य नगरवासियों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। हत्या के विरोध में दुकानें भी बंद रहीं। लोगों ने जशल्द से जल्द अजय के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों के आक्रोश का निशाना अस्पताल में पहुंची पुलिस भी बनी।

जन विरोधी और कॉरपोरेट मित्र है, मोदी सरकार- मेधा पाटकर

पटना : मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी मेधा पाटकर ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उसे जन विरोधी और कॉरपोरेट सरकार करार दिया। '2015 के बिहार चुनाव में जनता के मुद्दे' विषय पर पटना के किदवई पुरी में आयोजित परिचर्चा में बोलते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि इसे (मोदी सरकार को) आम लोगों की कोई चिंता नहीं है, इसीलिए गरीबों की जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। उन्होंने युवाओं से आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि आज विकास के नाम पर हिंसा हो रही है। कॉरपोरेट शक्तियां जनानंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। युवाओं को आगे बढ़ कर इसका मुकाबला करना होगा। उन्होंने लोगों को सांप्रदायिक और जातीय राजनीति सावधान रहने की भी नसीहत दी। मेधा पाटकर ने कहा कि योग्य उम्मीदवार न मिलने की सूरत में नोटा बटन का इस्तेमाल करें। पाटकर ने आरक्षण खत्म न करने की वकालत करते हुए कहा कि 68 साल बाद भी दलितों-आदिवासियों के हालात में बदलाव नहीं आया है। रोजगार के अवसर नहीं बढे हैं और आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिला है। इस परिचर्चा का आयोजन नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट के बिहार राज्य समन्व. समिति ने किया था। परिचर्चा में पाटकर के अलावा अन्य कई वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

सोलर लाइट से रोशन होंगे बिहार के गांव

पटना : अगर सबकुछ ठीक रहा तो आनेवाले दिनों में बिहार के गांव सोलर लाइट से रोशन होंगे। ग्रीन लाइट प्लेनेट ने इसके लिए खास किस्म के सोलर पावर का निर्माण किया है, जो 24 घंटे से लेकर 45 घंटे तक बैकअप देता है। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक गांवों में लोगों को टार्ट और लालटेन से मुक्ति मिल सकती है। यह पूरी तरह से वाटरप्रुफ है और एक साथ दो-दो मोबाइल चार्ज कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक गांव-गांव तक पहुंचाने में अपने स्तर से मदद पहुंचा रहा है। इसे उन गांवों में लगाने की योजना है, जहां बिजली नहीं पहुंची है या कम आती है।

डॉक्टरों ने निकाला रंगदारी के खिलाफ जुलूस

आरा : बिहार में रंगदारी अघोषित रूप से उद्योग में तब्दील है। तमाम दावों के बावजूद राज्य में रंगदारी मांगने की घटनाएं नहीं रूकी है। खासकर रंगदारी का सबसे ज्यादा हमला डॉक्टरों को झेलना पड़ता है। हालांकि धीरे-धीरे अब भयमुक्त होकर रंगदारी के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी है। बीते दिनों आरा में भी डॉक्टरों ने डॉ. कुमार जितेंद्र से रंगदारी मांगने के खिलाफ शहर में काला बिल्ला लगाकर मौन जुलूस निकाला और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस दौरान शहर के निजी क्लीनिकों के बंद होने के चलते मरीजों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा।

सीबीएसइ सर्टिफिकेट पर दिये जायेंगे बार कोड

2015-16 सत्र से सीबीएसइ कर रहा लागू

पटना : छात्र ठगे न जाएं, फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में न फंसे, इसको लेकर (सीबीएसइ) की ओर से सर्टिफिकेट को सुरक्षित करने के उपाय किये जशा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीबीएसइ के सर्टिफिकेट पर बार कोड दिये जायेंगे। इससे सर्टिफिकेट के फर्जी होने से बचा जा सकेगा। यह 10वीं और 12वीं बोर्ड के सर्टिफिकेट पर 2015-16 सत्र से लागू होगा। मार्च 2016 में 10वीं और 12वीं बोर्ड की होनेवाली परीक्षा में सफल स्टूडेंट्स को बार कोड वाले ही सर्टिफिकेट दिये जायेंगे। गौरतलब है कि सीबीएसइ के पास फर्जी सर्टिफिकेट के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे बोर्ड को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस कारण वह बार कोड वाला सर्टिफिकेट जारी करने जा रहा है।

अभिभावक का भी नाम रहेगा

बार कोड वाले सर्टिफिकेट में स्टूडेंट्स की तमाम जानकारियां भी कोड के रूप में रहेंगी। इसमें स्टूडेंट से संबंधित कई ऐसी जानकारियां रहेंगी, जिससे पता चल जायेगा कि सर्टिफिकेट उसी छात्र का है। सीबीएसइ की मानें तो ऐसे सर्टिफिकेट की जब भी जांच होगी, तो उसे आसानी पकड़ा जा सकेगा। बार कोड वाले सर्टिफिकेट में स्टूडेंट, परीक्षा, अभिभावक, केंद्र के नाम के अलावा रोल नंबर तथा बोर्ड द्वारा जारी तिथि भी अंकित रहेगी।

क्या कहते हैं कोर्डिनेटर

यह सच है कि सीबीएइ के नाम पर जालसाज फर्जी सर्टिफिकेट बांटते हैं। उसे रोकने के लिए ही बोर्ड यह कदम उठा रहा है। इसके अलावा बोर्ड की विश्वनीयता भी बढ़ेगी। इससे स्टूडेंट को सही सर्टिफिकेट मिल पायेगा।

राजीव रंजन सिन्हा, सिटी कोर्डिनेटर, सीबीएसइ

हफ्ते में दो दिन दरभंगा से दिल्ली जायेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

अप एवं डाउन दिशा में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, बरेली एवं मुरादाबाद स्टेशनों पर रूकेगी

दरभंगा : दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने दरभंगा से दिल्ली तक सप्ताह में दो दिन पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसका नाम सुविधा स्पेशल ट्रेन रखा गया है। पहली बार यह सुविधा ट्रेन 13 से 28 अक्टूबर तक चलेगी. जबकि दूसरी बार यह ट्रेन 14 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी. यात्रियों की सुविधा को लेकर यह स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा रेलवे ने की है.गाड़ी संख्या 04408/04407 दिल्ली-दरभंगा-दिल्ली सुविधा स्पेशल एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को दिल्ली से 11.15 बजशे खुलकर अगले दिन 9 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

वापसी में यह ट्रेन बुधवार एवं शनिवार को दरभंगा से 12 बजे खुलकर अगले दिन 12.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन दरभंगा और दिल्ली के बीच अप एवं डाउन दिशा में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, बरेली एवं मुरादाबाद स्टेशनों पर रूकेगी. इस स्पेशल ट्रेन में 3एसी के 4 कोच, स्लीपर क्लास के 12 कोच एवं एसएलआर के 2 कोच सहित कुल 18 कोच होंगे. यह जानकारी मुख्य जनसपंर्क अधिकारी अरविन्द कुमार रजक ने दी।सीबीएसइ के सर्टिफिकेट पर अब होगा बार कोड

घर में घुस हथियार दिखा महिला के साथ किया गैंगरेप

पुलिस ने मामले में आरोपित दोनों युवकों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी तेज कर दी

मकेर (सारण) : थाना क्षेत्र के बाघाकोल गांव में एक महिला के घर में घुस कर दो युवकों ने हथियार का भय दिखा कर सामूहिक दुष्कर्म किया । घटना के बाद सुबह में पीड़ित महिला थाना-पुलिस को सूचना देने के बजाय अपने मायके चली गयी और अपने पति को मोबाइल पर घटना की जानकारी दी। उसके पति उत्तरप्रदेश के कानपुर शहर में रहते हैं। घटना की सूचना पाकर उसके पति ससुराल पहुंचे और महिला को लेकर शुक्रवार की सुबह थाना पहुंचे। पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दजकर ली है और महिला की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करायी गयी।

पुलिस ने इस मामले में आरोपित दोनों युवकों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी तेज कर दी है। आरोपित दोनों युवक उसी गांव के निवासी हैं, जो घटना के बाद से फरार बताये जाते हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है तथा दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.। पीड़ित महिला का सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया।

संजय कुमार गुप्ताथानाध्यक्ष, मकेर, सारण

पितृपक्ष मेले में मटरगश्ती करने वाले एक दारोगा और सात पुलिस कर्मी निलंबित

गया : पितृपक्ष मेले में ड्यूटी के बजाय मटरगश्ती करनेवाले पुलिसकर्मियों की पहचान करने के लिए सिटी एसपी रविरंजन कुमार ने विशेष अभियान शुरू किया। उन्होंने सिटी डीएसपी आलोक कुमार सिंह के साथ पितृपक्ष मेला क्षेत्र में बनाये गये 37 पुलिस केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अभियान में एक दारोगा व सात सिपाही ड्यूटी से गायब मिले। गायब दारोगा ग्रवियर मूर्मू , सिपाही वकील अख्तर व बबीता कुमारी, होमगार्ड गनौरी यादव, नंदकिशोर प्रसाद सिंह, देवनारायण यादव, गोविंद प्रसाद व रामचलितर यादव के विरुद्ध सिटी एसपी ने कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन की अनुशंसा एसएसपी मनु महाराज से की है। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ने संबंधित पुलिस केंद्रों पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों का जम कर क्लास लिया और उनसे पूछा कि अगर कोई दारोगा या सिपाही अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है, तो इसकी सूचना उनके मोबाइल फोन पर मैसेज से क्यों नहीं दी गयी ?

इस दौरान कई पुलिसकर्मी नींद भी लेते पाये गये. कुछ पुलिसकर्मी अपने फुल ड्रेस में नहीं थे। किसी-किसी पुलिस केंद्र में हथियारों को लापरवाह तरीके से रखा गया था. सिटी एसपी ने वहां मौजूद दारोगा व सिपाहियों को कहा कि अगर आपका वेश-भूषव रहन-सहन ऐसा रहेगा, तो देश-दुनिया के कोने-कोने से पिंडदानियों के मन में गयाजी के बारे में कैसा मैसेज जायेगा. पिंडदानी क्या कहेंगे। कैसे पुलिसवाले हैं, जिन्हें ड्रेस भी पहनने नहीं आता है. सिटी एसपी ने लापरवाह तरीके से ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को जम कर फटकार लगायी. सिटी एसपी के कड़े रुख से मेला क्षेत्र में ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया।

एसएसपी ने भी दिखायी सख्ती

एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि एक ही समय में पितृपक्ष मेला भी है और चुनाव भी। मेले में देश-दुनिया से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान करने आये हैं। वे गयाजी के साथ-साथ बिहार के बारे में अच्छी भावना लेकर जायें, इस बाबत 24 घंटे इलाकों पर नजर रखी जशा रही है. एक भी श्रद्धालु के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया। तो काफी बदनामी होगी. ऐसे संवेदनशील मौकों पर ड्यूटी में लापरवाही करनेवाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जायेगा। गायब रहनेवाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

महात्मा गांधी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

बक्सर : दो अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर शहर में कार्यक्रमों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्नि कार्यक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रपिता को याद करते उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस क्रम में जिला प्रशासन की ओर से कमलदह पोखरा परिसर में महात्मा गांधी व लालबहादुर शस्त्री की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सर्वप्रथम गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते जिलाधिकारी रमण कुमार ने नैतिक मतदान का संदेश दिया और आगामी 28 अक्टूबर को मतदान में बढ-चढ़कर भाग लेने की लोगों से अपील की। तत्पश्चात संध्या समय प्रेरणा के तत्वावधान में कमलदह पोखर से कैंडल मार्च निकाला गया। जो शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए भगत सिंह चैक पर पहुंचा। जहां गांधीजी और शास्त्री जी के आदर्शो से लोगों को अवगत कराया गया। इस दौरान डीडीसी मोबिन अली अंसारी, एसडीओ गौतम कुमार समेत जिले के विभिन्न प्रखंडों के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करायी। वहीं, इस अवसर पर जहां रोटरी द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं, पतंजलि योग समिति द्वारा स्वच्छता की अलख जगाते रामरेखाघाट पर सफाई कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ भारत की संकल्पना को अमली जामा पहनाया। गांधी जयंती पर प्रखंडों में भी स्वच्छता व मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की धूम रही। जिले के अहिरौली में

प्रशासन के तत्वावधान में स्वच्छता की महता पर प्रकाश डालते लोगों अवगत कराया गया। जबकि, चैसा, कृष्णाब्रहम, नावानगर, सिमरी, डुमरांव, ब्रहमपुर, इटाढ़ी आदि जगहों पर कैंडल मार्च व मतदाता जागरूकता रैली के जरिये लोगों को बापू के संदेशों से अवगत कराया गया। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने अपनी सषक्त भागीदारी निभायी।

बिना परची दी दवा, तो लाइसेंस होगा रद्द

भागलपुर : नवंबर से अगर कोई दवा दुकानदार किसी को बिना परची के दवा देगा, तो वैसे दवा दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो सकता है। दरअसल स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वैसे दुकानदार जो बिना डॉक्टर के परची के दवा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। जो दवा दुकानदार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 व नियम-1945 का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाये। इस निर्देश को नवंबर से पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि दवा अधिनियम के अनुसार लोगों को दवा दुकान से दवा लेने के लिए डॉक्टर की परची जरूरी है, लेकिन प्राय: देखा जाता है कि दवा दुकानदार बिना परची के दवा लोगों को दे देते हैं। परची के बिना दवा मिलने से खासकर नशे बाज इसका फायदा उठाकर नशा के लिए कफ सिरप का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं कई ऐसे दवा हैं, जो प्रतिबंधित हैं, लेकिन दुकानदार खुलेआम लोगों को बेचते हैं।

बिना परची की मिलती है दवाई

पूरे बिहार में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 व नियम-1945 को लागू कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है। बिहार में अभी दवा दुकानों से दवा लेने के लिए दवा परची की जरूरत नहीं है। ऐसे में लोग कोई भी दवा कहीं से लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। बहुत से नशेबाज तो कफ सिरप खरीद कर रोज पीते हैं। इन सभी को दुकानों में परची की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा दुकानदार नियम का उल्लंघन कर बहुत सी प्रतिबंधित दवाएं भी खुलेआम बेचती है।

सीबीएसइ के टॉप-20 में बिहार के किसी भी स्कूल को जगह नहीं

मुजफ्फरपुर : सीबीएसइ के टॉप-20 स्कूलों की लिस्ट में इस बार भी बिहार से एक भी स्कूल शामिल नहीं हो सका है.। सीबीएसइ ने 2015 में आयोजित 12वीं के रिजल्ट के आधार पर टॉप स्कूलों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में बिहार का एक भी स्कूल शामिल नहीं है। सीबीएसइ की मानें तो टॉप -20 स्कूलों की लिस्ट में दक्षिण भारत के 15 स्कूल इस बार बेस्ट स्कूल में शामिल हुए हैं। वहीं पटना जोन (बिहार और झारखंड) से एकमात्र स्कूल रामकृष्ण मिशन, देवघर को टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। सीबीएसइ की ओर से हर साल बोर्ड रिजल्ट के आधार पर टॉप स्कूलों की लिस्ट जारी की जाती है. इस लिस्ट में स्कूल के ओवरऑल रिजल्ट को मुख्य माध्यम बनाया जाता है। इस बार बोर्ड ने 92.3 परसेंट से लेकर 89.6 परसेंट तक का रिजल्ट परसेंटेज रखा था। इन परसेंट के बीच बिहार का एक भी स्कूल नहीं आ पाया। बोर्ड की मानें तो बिहार के एक भी स्कूल में ओवरऑल रिजल्ट 89.6 परसेंट तक भी नहीं पहुंच पाया. इस परसेंटेज के नीचे ही तमाम स्कूल रहे. बिहार के स्कूल पिछले तीन वर्षों से सीबीएसइ के टॉप लिस्ट स्कूल में शामिल नहीं हो पा रहे हैं । यह राज्य के लिए चिंता का विषय है।

देवघर के रामकृष्ण मिशन को मिला 91.8 परसेंट

झारखंड के देवघर स्थित रामकृष्ण मिशन को देश भर के टॉप-20 स्कूलो की लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। राम कृष्ण मिशन को 91.8 फीसदी अंक प्राप्त हुए हैं। देश में पहला स्थान डीएवी ब्वॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चेन्नइ को मिला है। स्कूल 92.3 परसेंटेज के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे और तीसरे टॉप स्कूल भी चेन्नई से ही चुने गये हैं। बिहार के स्कूल इस बार भी टॉप लिस्ट में शामिल नहीं हो पाये। हमें बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। टॉपर तो यहां पर अच्छे परसेंटेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट में स्कूल पिछड़ जाते हैं।

वोट बहिष्कार वापस लेने का अनुरोध

बेगुसराय, बखरी : प्रखंड की राटन पंचायत के बभईन गांव के लोगों द्वारा विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की घोषा के पश्चात प्रशासन हरकत में आ गयी है। बीडीओ राजेश कुमार रंजन बभईन पहुंचे और ग्रामीण से वोट बहिष्कार के निर्णय को वापस लेकर मतदान में भाग लेने की अपील की। हालांकि लोगों का आक्रोश चरम पर था। वे लोग जिले के वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे। मौके पर प्रखंड लोक शिक्षा समिति के समन्वयक जितेंद्र कुमार जीतू सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञात हो कि चंद्रभागा नदी पर पुल नहीं होने से यहां के लोगों को बखरी मुख्यालय आने के लिए तीन किलोमीटर के बजाय 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसी से आक्रोशित बभईन ग्रामवासियों ने बैठक कर सामूहिक वोट बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसके बाद प्रखंड लोक शिक्षा समिति द्वारा बीडीओ को पत्र प्रेषित कर मामले से अवगत कराया गया था।

लाइनमैन को बनाया बंधक

मुजफ्फरपुर : एस्सेल के विद्युत व्यवस्था ऐसी है कि फॉल्ट ठीक करने में 18 से 24 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही अहियापुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में हुआ। एसडीओ निरंजन महतो के घर में लगी डीटी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गयी। इससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी थी. लोगों ने इसकी शिकायत विद्युत विभाग से की। लेकिन शिकायत के 15 घंटे बाद ठीक करने पहुंचे लाइन मैन की बातों से लोग भड़क गये। लोगों ने लाइन मैन के साथ हाथापाई की. उसे बंधक बना लिया।

साथ ही हंगामा करने लगे। लोग एसकेएमसीएच के एरिया मैनेजर की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे थे। जेइ के लिखित आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ।

स्थानीय राम किशोर सिंह, विजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, राजू कुमार, नीरज कुमार का आरोप था कि एस्सेल की विद्युत व्यवस्था एकदम चौपट है। फॉल्ट ठीक करने के लिए लाइन मैन को कई बार फोन किया गया। लेकिन लाइन मैन 18 घंटे बाद पहुंचा।

लाइन मैन ने कहा, हमको बार-बार फोन करने के बजाय अधिकारियों को फोन करिये। इसके बाद एरिया मैनेजर दिवाकर कुमार को फोन किया गया। उन्होंने भी बात अनसुनी कर दी. तब लोगों ने इसे बंधक बना लिया. विरोध करने पर हाथापाई हो गयी। आक्रोशित लोगों ने कहा, अपने पदाधिकारियों को बुलायो तब छोड़ेंगे। इसके बाद जेई को मौके पर बुलाया गया। जेई दिलीप कुमार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि बार-बार फेज उड़ने व लो-हाइ वोल्टेज की समस्या दो दिनों में दूर करेंगे। लोड की जांच कर कार्रवाई करेंगे। तब लोग मान गये।

मिथिला विवि के सेवानिवृत्त प्राध्यापक राम किशोर सिंह का आरोप है कि एक माह में बिजली नौ हजार रुपये आया है.। जबकि पंखा, बल्ब, टेलीविजन, पानी का मोटर ही चलता है। विजय कुमार सिंह का आरोप है कि दो माह का बिजली बिल एक साथ देता है। उसमें भी फाइन जोड़ कर पैसा ले लेता है। सहवाजपुर में गुरुवार की नौ बजे रात में फेज उड़ गया। उसे 17 घंटे बाद शुक्रवार को ठीक किया. मुरादपुर में दिन में चार बार फेज उड़ जाता है। डीटी बॉक्स में आग लग जाता है। शिकायत पर वरीय अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं।

पटना, 04 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com
गणादेश

पहला चरण- जो मारे सो मीर!

महागठबंधन व राजग की होगी अग्निपरीक्षा

हिंदी में एक कहावत है कि जो मारे सो मीर यानी जो पहले बाजी मारता है विजयी वही कहलाता है। हालांकि चुनावी समर में इस कहावत का कोई खास मतलब नहीं है, किंतु बिहार विधानसभा के पहले चरण में 12 अक्टूबर को मतदान होना है, उसके मद्देनजर इस कहावत को यहां भी अमल में लाया जा सकता है। क्योंकि इस चरण की विधानसभा सीटों पर अपनी जीत और हार को लेकर महागठबंधन और राजग दोनों के पास अपने अपने दावे और आशंकाएं हैं। इस चरण का चुनाव महागठबंधन और राजग दोनों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। इसीलिए सबकी निगाहें इस चरण के चुनाव पर टिकी हैं। सभी पहली बाजी अपने नाम करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाय तो पहले चरण के चुनाव में जदयू की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि पिछले चुनाव में यहां उसने अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी।

गणादेश न्यूज नेटवर्क

पटना : इसबार जिन 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान है 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां जदयू ने न सिर्फ विजय हासिल की थी, बल्कि अपना दबदबा कायम किया था। 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू को यहां 49 सीटों में से 29 सीटों पर जदयू ने कब्जा किया था। किंतु उस वक्त स्थिति दूसरी थी। तब जदयू का भाजपा के साथ गठबंधन था और भाजपा ने भी 13 सीटों पर विजय हासिल की थी, जबकि राजद के हिस्से में 4 और कांग्रेस, सीपीआई और जेएमएम के हिस्से में 1-1 सीट आई थी।

इसबार समीकरण बिल्कुल उलट हैं। भाजपा और जदयू आमने सामने हैं। पिछली बार के विरोधी राजद और कांग्रेस इसबार जदयू के साथ हैं तो लोजपा और जदयू से टूटकर अलग हुई रालोसपा और हम भाजपा की सहयोगी बनी है। रोलसपा के उपेंद्र कुशवाहा के चलते कुशवाहा बहुल कई विधानसभा क्षेत्रों में राजग को फायदा हो सकता है। यही नहीं रामविलास पासवान और जीतनराम मांझी के चलते राजग दलित वोट भी अपने पाले में आने की आस लगाए हुए है। खगड़िया रामविलास पासवान का गृहजिला भी है।

उधर नये बने समीकरण में जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को भी पहले चरण की वोटिंग में अपनी जीत की उम्मीद है। नए समीकरण के चलते वर्तमान में यहां की 34 सीटें महागठबंधन के पास है। पिछले चुनाव में राजग की एकतरफा जीत के बावजूद राजद के साथ मुकाबला बेहद कड़ा रहा था। करीब 24 सीटों पर हार-जीत का अंतर पांच हजार वोटों से कम था। राजद को मिले ये वोट इसबार महागठबंधन को मिल सकते हैं। पिछले चुनाव के प्रदर्शन और इसबार नए बने समीकरण के आलोक में देखा जाय तो महागठबंधन और राजग दोनों के पास पहले चरण की सीटों को अपने अपने पक्ष में बताने के लिए काफी कुछ है तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं, जो इनकी उम्मीदों के खिलाफ जा सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि पहले चरण के चुनाव में जदयू के लिए जहां पुरानी सफलता दोहराने की चुनौती है, वहीं बीजेपी को भी ये साबित करने का मौका है कि नीतीश कुमार का सिक्का तभी खरा था, जब वह बीजेपी के साथ थे।

वर्तमान विधानसभा में पहले चरण की सीटों की स्थिति

जदयू कल्याणपुर(सुरक्षित) से रामसेवक हजारी, वारिसनगर से अशोक कुमार, मोरवा से बैद्यनाथ सहनी, सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी, विभूतिपुर से रामबालक सिंह, हसनपुर से राज कुमार राय, चेरिया बरियारपुर से कुमार मंजू वर्मा, मटिहानी से नरेंद्र सिंह उर्फ बोंगो सिंह , साहेबपुर कमाल से परवीन अमानुल्लाह, अलौली(सुरक्षित) से रामचंद्र सदा, खगड़िया से पूनम देवी यादव, बेलदौर पन्नालाल सिंह पटेल, गोपालपुर से नरेंद्र कुमार नीरज, सुल्तानगंज से सुबोध राय, नाथनगर से अजय कुमार मंडल , अमरपुर से जर्नादन मांझी, धुरैया सुरक्षित से मनीष कुमार, बेलहर से गिरिधारी यादव, तारापुर से नीता चौधरी, मुंगेर से अनंत कुमार सत्यार्थी, जमालपुर से शैलेश कुमार, शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, बरबीघा से गजानंद शाही, नवादा से पूर्णिमा यादव, गोबिंदपुर से कौशल यादव, वारसिलीगंज से प्रदीप कुमार, सिकंदरा सुरक्षित से रामेश्वर पासवान, जमुई से अजय प्रताप, झाझा से दामोदर रावत

भाजपा बिहपुर कुमार से शैलेंद्र , सूर्यगढ़ा से प्रेम रंजन पटेल, कटोरिया(सुरक्षित) से सोनेलाल हेम्ब्रम, भागलपुर से अश्विनी कुमार चौबे, पीरपैंती(सुरक्षित) से अमन कुमार, बेगूसराय से सुरेंद्र मेहता, तेघड़ा से ललन कुमार, मोहिउद्दीननगर से राणा गंगेश्वर सिंह ,रोसड़ा से मंजू हजारी, बखरी(सुरक्षित) से रामानंद राम, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, रजौली से कन्हैया कुमार, हिसुआ से अनिल सिंह

राजद समस्तीपुर से अख्तारूल इस्लाम शाहीन, उजियारपुर से दुर्गा प्रसाद सिंह, बांका से जावेद इकबाल अंसारी, परबत्ता से सम्राट चौधरी

कांग्रेस- कहलगांव से सदानंद सिंह
सीपीआई- बछवाड़ा से अवधेश कुमार राय
जेएमएम- चकाई से सुमित कुमार सिंह

चुनाव @ 12 अक्टूबर

प्रथम चरण- 10 जिले, 49 विधानसभा क्षेत्र, 586 उम्मीदवार

पांच चरणों में संपन्न होनेवाले बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को होगा। सभी दल और गठबंधन तथा सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। 10 जिलों के 49 विधानसभा सीटों के लिए कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के लिए 605 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिसमें से 19 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। मैदान में बचे 586 उम्मीदवारों की किस्मत 12 अक्टूबर को ईवीएम में बंद हो जाएगी। प्रथम चरण के तहत समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जबकि मतो की गिनती सभी चरणों का चुनाव खत्म हो जाने के बाद 8 नवंबर को होगी। आइए जानते हैं किस जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं...

समस्तीपुर

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
कल्याणपुर(सु)-	14
वारिसनगर-	15
समस्तीपुर-	17
उजियारपुर-	14
मोरवा-	18
सरायरंजन-	12
मोहिउद्दीन नगर-	18
विभूतिपुर-	09
रोसड़ा (सु.)-	10
हसनपुर-	12

खगड़िया

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
अलौली (सु)-	09
खगड़िया-	14
बेलदौर-	11
परबत्ता-	15

भागलपुर

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
बिहपुर-	14
गोपालपुर-	12
पीरपैंती (सुरक्षित)-	11
कहलगांव-	13
भागलपुर-	11
सुलतानगंज-	12
नाथनगर-	13

लखीसराय

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
सूर्यगढ़ा-	15
लखीसराय-	10

बेगूसराय

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
चेरिया बरियापुर-	10
बछवाड़ा-	10
तेघड़ा-	07
मटिहानी-	10
साहेबपुर कमाल-	12
बेगूसराय-	09
बखरी (सु.)-	09

बांका

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
अमरपुर-	14
धोरैंया-	08
बांका-	11
कटोरिया (सु.)-	09
बेलहर-	11

मुंगेर

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
तारापुर-	13
मुंगेर-	14
जमालपुर-	12

नवादा

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
रजौली (सु)-	12
हिसुआ-	09
नवादा-	12
गोविंदपुर-	10
वारिसलीगंज-	06

कुल उम्मीदवार- 586

जमुई

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
सिकंदरा (सु)-	08
जमुई-	16
झाझा-	14
चकाई-	12

शेखपुरा

विधानसभा	उम्मीदवारों की संख्या
शेखपुरा-	17
बरबीघा-	12

दो सीटों पर सर्वाधिक 18-18 और एक सीट पर सबसे कम 6 प्रत्याशी

पहले चरण के चुनाव के 49 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उम्मीदवार समस्तीपुर जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में हैं। समस्तीपुर के मोरवां और मोहिउद्दीन नगर सीट से सबसे अधिक 18-18 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर सबसे कम 6 प्रत्याशी खड़े हैं। इसके अलावा इसके अलावा लखीसराय और समस्तीपुर सीट पर 17-17 और जमुई सीट से 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

आधी आबादी को नहीं मिला पूरा हक

विधानसभा में महिलाओं का कम रहा है प्रतिनिधित्व

भारत के किसी भी राज्य में आधी आबादी को अबतक जनसंख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चाहे बात संसद की हो या राज्यों की विधानसभाओं का महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम ही रहा है। ये बात बिहार विधानसभा पर भी लागू होती है। 1951 से लेकर 2010 के विधानसभा चुनावों तक जीतने वाली महिला प्रत्याशियों की कुल संख्या सिर्फ 232 रही है। हालांकि 2010 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 34 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी।

गणादेश न्यूज नेटवर्क

पटना : महिला विधायकों की ये संख्या बिहार में अबतक के विधानसभा चुनावों में सर्वोच्च तो है ही, देश में भी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से दूसरी है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी 34-34 महिला विधायकों ने जीत हासिल की है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 35 महिलाएं चुनकर विधानसभा में पहुंची है। लेकिन इसके बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि बिहार विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या अभी भी काफी कम है।

गौरतलब है कि अबतक के चुनावों में महिलाओं ने ज्यादा उन सीटों पर ही जीत दर्ज की है, जो महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। सामान्य सीटों से बहुत कम महिलाएं चुनाव जीतने में सफल रही हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि महिला प्रत्याशियों को चुनने के मामले में न तो मतदाता उदार रहे हैं और न उन्हें टिकट देने के मामले में राजनीतिक दलों ने कोई खास उदारता दिखाई है। हालांकि पिछले दो चुनावों से जिस तरह महिला विधायकों की संख्या बढ़ी है (2005 में 25 महिलाओं ने जीत हासिल की थी), उससे लगता है कि इस मामले में जागरूकता बढ़ी है। यहां एक बात और गौर करने लायक है कि 1967 से महिला विधायकों की संख्या कम होने लगी थी।

1969 में सबसे कम सिर्फ 4 महिलाएं जीत कर विधानसभा पहुंची थी, जो अबतक की बिहार विधानसभा में सबसे कम संख्या रही है। ध्यान देनेवाली बात यह भी है कि अबतक चुनी गई महिला विधायकों में अनुसूचित जाति की 35 और अनुसूचित जनजाति की बस 11 महिला विधायक ही रही हैं, जबकि राबड़ी देवी के रूप में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री। देखना है कि इसबार कितनी महिलाएं चुनकर विधानसभा में पहुंचती है। हालांकि जिस तरह से सभी प्रमुख दलों ने महिलाओं को टिकट देने के मामले में कोताही बरती है, उससे बहुत ज्यादा की उम्मीद करना बेमानी ही होगा।

किसी विधानसभा में कितनी महिला प्रतिनिधि

वर्ष	कुल सीट	महिला विधायक
1951	276	13
1957	264	30
1962	318	25
1967	318	06
1969	318	04
1972	318	13
1977	324	13
1980	324	11
1985	324	15
1990	324	10
1995	324	11
2000	324	19
2005 (फर.)	243	03
2005 (अक्टू.)	243	25
2010	243	34

कुल महिला विधायकों की संख्या- 232

कम रहा है विधानसभा में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व

गणादेश न्यूज नेटवर्क

पटना : बिहार में न तो मुस्लिम आबादी कम है और न ही मुस्लिम महिला मतदाताओं की संख्या, फिर भी यह एक कटु तथ्य है कि बिहार विधानसभा में मुस्लिम महिला प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। निवर्तमान विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या 34 है, किंतु इनमें मुस्लिम महिला विधायक महज दो हैं और ये आंकड़ा भी लंबे अर्से बाद हासिल हुआ। गौरतलब ये भी है कि 2010 में विधानसभा चुनाव जीतनेवाले कुल मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या 19 रही थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम महिला प्रत्याशी के रूप में परवीन अमानुल्लाह और रजिया खातून ने जीत हासिल की थी। मुस्लिम महिला विधायकों की संख्या के मामले में बिहार विधानसभा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। 2010 में दो सीटों पर जीत से पहले के 20 वर्षों में यानी 1995 से 2005 तक के चुनावों में कोई भी मुस्लिम महिला उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाई। 2010 में 2 मुस्लिम महिला विधायकों की संख्या भी इससे पहले 1972 में ही पहुंची थी। 1972 के चुनाव में भी दो मुस्लिम महिला विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंची थी। अगर आजादी के बाद से हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो वर्तमान विधानसभा को मिलाकर कुल 8 बार ही मुस्लिम महिला प्रत्याशियों को जीत नसीब हुई है, जिसमें 2010 और 1972 में दो-दो जबकि 1985, 1980, 1962 और 1957 में एक-एक मुस्लिम महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जबकि 1952 से 2010 तक के चुनाव में कुल 239 महिलाएं जीत दर्ज कर चुकी हैं। आंकड़ों से साफ है कि विधानसभा चुनाव के अबतक के इतिहास में महिलाओं की जीत का आंकड़ा कम रहा है, मुस्लिम महिलाओं का तो और भी कम। अब देखना है इसबार इस आंकड़े में कोई बेहतर सुधार होता है या फिर इस चुनाव में भी मुस्लिम महिला विधायकों की संख्या न के बराबर ही रहेगी।

चुनाव में बह सकता है पानी की तरह पैसा और शराब !

मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान पर गणादेश ने जानी लोगों की राय

पटना : बिहार में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। हालांकि इसबार निर्वाचन आयोग ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है, फिर भी चुनाव निष्पक्ष होगा इसकी आशंका बनी हुई है। किसी और को छोड़ दें तो जिसपर चुनाव साफ सुथरे ढंग से कराने की जिम्मेदारी है यानी चुनाव आयोग, वह भी इसे लेकर आशंकित है। चुनाव आयोग के साथ साथ लोगों का भी मानना है कि चुनाव में धनबल का खेल देखने को मिलेगा। 28 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पानी की तरह पैसा और शराब बहाए जाने की संभावना जाहिर की तो इस आशंका को और बल मिल गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक हर चौथे विधानसभा में शराब और पैसा बांटे जाने की आशंका है। उनके मुताबिक बिहार विधानसभा में 62 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसा और शराब बांटा जा सकता है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 2010 के चुनाव में 35 लाख रुपए जब्त किये गए थे, जबकि इसबार अबतक करीब 9 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि इस तरह की किसी भी आशंका से निपटने और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी उपाय किये जाएंगे और इसबार अपने अधिकारियों पर भी नजर रखी जाएगी। चुनाव आयुक्त के अनुसार वे चुनाव आयोग की अभी तक की तैयारियों से मोटे तौर पर संतुष्ट हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त की इस आशंका के मद्देनजर गणादेश की टीम ने लोगों से इस बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की तो जो जवाब मिले वे चुनाव आयोग की आशंका को सही ठहराते हैं। अधिकतर लोगों के मुताबिक सिर्फ 62 ही नहीं करीब-करीब सभी विधानसभाओं में वोटरों को लुभाने के लिए शराब और पैसे का खेल होगा। लोगों के मुताबिक शायद ही कोई विधानसभा क्षेत्र हो, जहां उम्मीदवारों की तरफ से ऐसे प्रयास नहीं किये जाएं। हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो ये मानते हैं कि शराब और पैसे का खेल सभी उम्मीदवारों की तरफ से नहीं बल्कि कुछ ही प्रत्याशियों की तरफ से होगा। वहीं कई लोगों के अनुसार अब समय बदल गया है और मतदाता जागरूक हो गए हैं। वे ऐसे प्रलोभनों में नहीं आएंगे।

नारों के सहारे नेताजी !

चुनावों में नारों का होता है अपना महत्व

गणादेश न्यूज नेटवर्क

पटना : सत्तर के दशक की शुरूआत में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था- 'गरीबी हटाओ' और 1989 के आम चुनाव में वीपी सिंह को केंद्र में रखकर जनता दल ने नारा दिया था- 'राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है'। इन नारों का उन चुनावों में कितना असर हुआ सभी जानते हैं। गरीबी हटाओ ने इंदिरा गांधी को पुनः सत्ता दिला दी तो 1989 के नारे ने राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की गद्दी थमा दी। 2014 के आम चुनाव में मोदी की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचाने और रिकॉर्ड जीत दिलाने में भी उनके लिए गढ़े गए नारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 'अच्छे दिन आनेवाले हैं' का नारा तो इतना लोकप्रिय हुआ कि आज मोदी सरकार की आलोचना भी इस नारे के सहारे की जाती है। बिहार चुनाव में नारों का खेल जोर पकड़ चुका है।

दरअसल नारों का अपना महत्व होता है और चुनावों में तो खासकर। चुनावों में नारे पॉलिस का काम करते हैं, जिसके जरिए उम्मीदवार और पार्टियां अपनी छवि चमकाने की कोशिश करती हैं। भारत की चुनावी राजनीति में तो नारे अनिवार्य रूप से चुनाव प्रचार का अंग होते हैं। बिहार के चुनावों में भी नारों के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की जाती है। इस चुनाव में भी हर दल और उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने में नारों का सहारा ले रहे हैं।

बिहार चुनाव में इसबार मुकाबला जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन तथा भाजपा की अगुवाई वाले राजग के बीच है, लिहाजा नारों की लड़ाई भी मुख्यतः दोनों के बीच नजर आ रही है। जैसे-जैसे चुनाव प्रचार परवान चढ़ता जा रहा है, नए-नए नारे सामने आ रहे हैं। जदयू के नारों में जहां ज्यादा नीतीश की तारीफ सुनाई दे रही है, वहीं राजद और कांग्रेस के नारों में बीजेपी और खासकर पीएम मोदी पर हमला बोला जा रहा है।

इसके जवाब में बीजेपी भी नए नए नारों के साथ महागठबंधन के घटक दलों पर हमला बोलने में पीछे नहीं है। बीजेपी मोदी की लोकप्रियता भुनाने के लिए भी नारों का सहारा ले रही है। राजग के अन्य घटक दल मसलन लोजपा और रालोसपा भी नारों के जरिए चुनाव प्रचार को गति देने में लगे हैं।

महागठबंधन और राजग के अलावा बिहार चुनाव में उतरी अन्य पार्टियां और गठबंधन भी नारे गढ़ने के मामले में पीछे नहीं है। मुलायम सिंह यादव की सपा की अगुवाई वाला गठबंधन हो या फिर बिहार में पहली बार छ वामपंथी पार्टियों को मिलाकर बना वाम मोर्चा सब के सब नारेबाजी के खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनके निशाने पर महागठबंधन और राजग दोनों हैं। इन सबके बीच निर्दलीय अपने फेमस नारे, 'सभी दलों में दल-दल है, सबसे अच्छा निर्दल है' के साथ चुनाव मैदान में तो हैं ही।

इस चुनाव के कुछ मशहूर नारे

महागठबंधन

- 'न जुमलों वाली, न जुल्मी सरकार, गरीबों को चाहिए अपनी सरकार' (राजद)
- 'झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे' (जदयू)
- 'युवा-युवती भरे हुंकार, कहां गया हमारा रोजगार' (राजद)
- 'सूट-बूट और जुमला छोड़, थामकर कांग्रेस की डोर, चला बिहार विकास की ओर' (कांग्रेस)
- 'आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार' (जदयू)

राजग

- 'अपराध भ्रष्टाचार और अहंकार, क्या इस गठबंधन से बढ़ेगा बिहार' (भाजपा)
- 'हम बदलेंगे बिहार, इस बार भाजपा सरकार' (भाजपा)
- 'आओ चलें चिराग के साथ, मिलकर बनाएं नया बिहार' (लोजपा)
- 'बिहार विकास में अब नहीं बाधा, मोदी जी ने दिया है वादे से ज्यादा' (भाजपा)
- 'नया बिहार बनाएंगे, लालू-नीतीश को भगाएंगे' (रालोसपा)

वाममोर्चा

- 'न मोदी न नीतीश सरकार, वामपंथ की है दरकार' (वाममोर्चा)
- 'मोदी-नीतीश धोखा है, परिवर्तन का मौका है' (वाममोर्चा)

चुनावी सभा में नीतीश को दिखाया चप्पल

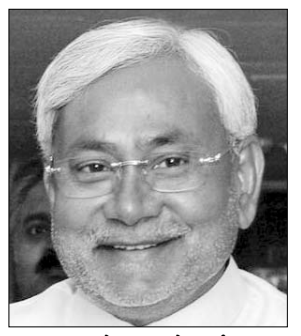

गणादेश न्यूज नेटवर्क

पटना/नवादा : इसे चुनावी जंग में अपने विरोधियों पर भारी पड़ने के लिए इस्तेमाल किया हथकंडा कहें या समर्थकों का अति उत्साह कि वे विरोधी दल के शीर्ष नेताओं के साथ भी दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी तब ऐसी असहज स्थिति का सामना करना पड़ गया, जब बीजेपी समर्थकों ने उनकी चुनावी सभा में न सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाए, बल्कि उन्हें चप्पल भी दिखाया। वाकया नवादा के वारिसअलीगंज का है।

मंगलवार को वारिसअलीगंज में नीतीश कुमार की चुनावी सभा थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नीतीश कुमार ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, सभा में पहुंचे करीब 20-25 भाजपा समर्थकों ने मोदी-मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इनमें से कइयों ने मंच की तरफ चप्पल भी दिखाया। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपना भाषण रोकते हुए कहा कि 'जब विपक्षी हमसे चुनाव लड़ने में अक्षम हो गए, तो उन्होंने ऐसे लोगों को भेज दिया'। नीतीश ने सभा में मौजूद भीड़ से पूछा कि 'आप मेरा भाषण सुनना चाहते हैं कि नहीं?' ये सुनते ही जदयू कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थकों को सभा से खदेड़ दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने भाषण दिया। चुनाव मैदान में हुई इस घटना की चर्चा सियासी हलके से लगाय मीडिया में भी खूब हुई। जाहिर है इस घटना को भी महागठबंधन और राजग अपने-अपने तरीके से अपने-अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे।

लालू का कटाक्ष- भागवत को मिले भारत रत्न

पटना : आरआरएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान को राजग खासकर भाजपा भुला देने की चाहे जितनी कोशिश करे, महागठबंधन इसे एक चुनावी मुद्दे के तौर पर गरमाए रखना चाहता है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे पर भागवत को कोई ढील या छूट नहीं देना चाहते।

लालू प्रसाद ने भागवत पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। मंगलवार को ट्वीटर पर लालू प्रसाद ने ट्वीट किया कि `आरक्षण खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागवत को भारत रत्न दे देना चाहिए'। इसके बाद उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में ये भी कहा कि `वे आरक्षण बढ़वाकर और जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करा कर ही दम लेंगे'। लालू ने कहा, `मोदी सरकार चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मैं चुप नहीं बैठूंगा और पिछड़ों, दलितों और गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा'।

आरक्षण मुद्दे पर भागवत के बयान को लेकर लालू प्रसाद जिस तरह लगातार हमलावर रुख अख्तियार किये हुए हैं, उससे साफ है कि वे आगे भी चुप नहीं होंगे। उन्हें पता है कि इस मुद्दे को गरमाए रखकर वे भाजपा को तो असहज स्थिति में रख ही सकते हैं, साथ ही दलितों-पिछड़ों के हितैषी नेता की अपनी छवि को भी चमकाए रख ही सकते हैं।

पटना, 04 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com
गणादेश

यूपी के सीमावर्ती जिलों पर चढ़ा बिहार चुनाव का रंग

बिमल कुमार सिंह

बक्सर/सीवान/कैमूर : पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश तो वैसे भी चुनावी मोड में आ गया है, किंतु बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते बिहार से सटे यूपी के सीमावर्ती जिलों पर तो बुरी तरह से चुनावी रंग चढ़ा दिखाई दे रहा है। इन जिलों में बिहार चुनाव को लेकर उत्सुकुता का आलम ये है कि कहीं-कहीं और कभी-कभी पंचायत चुनाव की चर्चा भी इसके आगे फीकी पड़ जा रही है।

एक तरफ लोग बिहार चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी के नमोमंत्र के कड़ा इम्तिहान मान रहे हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन के भविष्य और उसकी उम्मीदों पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बनारस से लेकर गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, जिनकी सीमाएं बिहार के विभिन्न जिलों से सटी हुई है। ऐसे में दोनों राज्यों के इन जिलों के बीच भौगोलिक संबंध तो है ही, किंतु इससे भी बढ़कर इनके बीच आपस में सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ता भी है। जिसके चलते दोनों राज्यों की राजनीतिक हलचलों पर दोनों तरफ के लोगों की निगाह और उत्सुकुता बनी रहती है। यही उत्सुकुता बिहार चुनाव को लेकर भी है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के इन सीमावर्ती जिलों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहां भी चर्चा के केंद्र में महागठबंधन और

राजग के बीच मुकाबला है। इसबात पर लगभग सभी एकमत हैं कि बिहार मोदी और अमित शाह की बीजेपी के लिए अग्निपरीक्षा की तरह है और इस चुनाव के परिणामों से ही बीजेपी की आगे की रणनीति तय होगी। बीजेपी के लिहाज से लोगों का यह भी मानना है कि बिहार चुनाव के परिणाम निश्चित तौर पर 2017 में होनेवाले यूपी विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे।

लोगों के बीच नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की राजनीतिक दोस्ती भी चर्चा का कारण बनी हुई है। कुछ लोगों का आकलन है कि ये दोस्ती लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी, जबकि कइयों का मानना है कि इनको अपनी दोस्ती बनाए रखना मजबूरी है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में दोनों का राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। एक होकर ही ये भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। लोगों की निगाह यूपी की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों सपा और बसपा के प्रदर्शन पर भी लगी हुई है।

हालांकि ज्यादातर लोगों की राय यही है कि ये दोनों दल बिहार चुनाव में वैसी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब नहीं होंगे, जैसी उपस्थिति इनकी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा लोगों की उत्सुकुता अपने जिले से सटे विधानसभा सीटों और उनपर खड़े उम्मीदवारों को लेकर भी है। लोग इन विधानसभा सीटों से परिचित तो हैं ही, साथ ही अधिकतर उम्मीदवारों को भी जानते हैं।

झटके देने को तैयार बसपा!

- 1995 में बसपा को 2 सीटें मिली
- 2000 में पांच सीटें जीती
- 2005 में चार सीटें

गणादेश न्यूज नेटवर्क

पटना : यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार और पिछले लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होने के बाद बसपा राजनीति के मैदान से बाहर हो जाने के कगार पर खड़ी दिखाई दे रही है। पार्टी अपनी हार से इस कदर हतप्रभ थी कि यूपी के उपचुनावों में उसने प्रत्याशी भी नहीं खड़े किए थे। ऐसे में उसे उस ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसके बूते वह 2017 में होनेवाले यूपी विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ उतर सकती है। सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या उसे ये ऑक्सीजन मिल सकता है। जवाब हां भी है और नहीं भी। हां, इसलिए क्योंकि बिहार के पिछले चुनावों में बसपा की उपस्थिति महसूस

की जा चुकी है, जबकि ना, इसलिए कि बिहार में बसपा का अबतक का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। दरअसल बसपा बिहार में 1995 से ही चुनाव लड़ती आ रही है। 1995 में बसपा को 2 सीटें मिली थीं। उस समय कयास लगाये गये कि आनेवाले वक्त में बसपा बिहार में भी एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेगी। 2000 में इसने जब पांच सीटें जीती तो इस कयास को बल मिला, किंतु 2005 में सिर्फ चार सीटों पर ही बसपा को संतोष करना पड़ गया और जब 2010 के विधानसभा चुनाव में जब ये एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी तो बसपा के बिहार में पनपने और बढ़ने की उम्मीद कम हो गई। इस चुनाव में इसका वोट प्रतिशत भी घटकर 3.21 रह गया।

बिहार चुनाव में बसपा को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

लेकिन इसबार बदली राजनैतिक परिस्थितियों में हो रहे बिहार चुनाव में बसपा को अपने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बसपा का दावा है और उसकी ख्वाहिश भी यही है कि इसबार बिहार में जो सरकार बने वह बसपा के सहयोग से बने। बसपा अध्यक्ष मायावती इसके लिए आक्रामक अंदाज में बिहार में कई चुनावी रैलियां और जनसभाएं करने की तैयारी कर चुकी हैं। मायावती का चुनाव प्रचार 9 अक्टूबर से शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि मायवती की छवि एक दलित नेता की है और यूपी से सटे बिहार के इलाकों मसलन बक्सर, सिवान, गोपालगंज, छपरा, कैमूर आदि में बसपा का असर है। अब ये असर कितना प्रभावी है इसका पता चुनाव में चलेगा।

लालू, मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

दोनों पर दर्ज हुई एफआरआई

गणादेश न्यूज नेटवर्क

पटना/ राघोपुर/ भभुआ : जैसै जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें भी तेज होती जा रही हैं। इस चक्कर में नेता निर्वाचन आयोग द्वारा खींची गई आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा को भी पार करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे नेता ही नहीं बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो रहा है। बीते दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी पर भी आचार संहिता के उल्लघंन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। अपनी-अपनी चुनावी सभाओं में लालू प्रसाद पर जातिगत विद्वेष फैलाने और सुशील मोदी पर वोट के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगा है।

लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने राघोपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अगड़े और पिछड़े के नाम पर उकसाने के साथ एक जाति विशेष को एकजुट करने के लिए भड़काया था। दरअसल यहां एक चुनावी सभा में लालू प्रसाद ने यादव जाति से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा था कि भाजपा यादवों का वोट बांटकर उन्हें कमजोर करने की तैयारी कर रही है। दलाल को पहचानों, कमंडल को फोड़ देना है। राघोपुर से लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं।

दूसरी तरफ भभुआ की एक जनसभा में भाजपा नेता सुशील मोदी ने अपने भाषण के दरम्यान कहा कि

चुनाव में जीत के बाद दलित और महादलित बस्तियों में रंगीन टीवी दी जाएगी ताकि लोग नरेंद्र मोदी का भाषण सुन सकें। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर 50 हजार मैट्रिक और इंटर के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने के साथ गरीबों को धोती और साड़ी खरीदने के लिए पैसा भी दिया जाएगा।

दोनों मामलों की जांच करने के बाद चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी है। इसमें लालू प्रसाद पर पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव एक्ट के सेक्शन 123 ए और धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी जबकि सुशील मोदी पर आईपीसी की 188 और आरपी एक्ट के तहत 123 और 171 ई के तहत मामला दर्ज किया गया है।

"जातियों का समूह भर नहीं है जनता"

नागेन्द्र नाथ ओझा
पूर्व सांसद

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नागेन्द्र नाथ ओझा बक्सर की राजनीतिक फिजा में बक्सर की जनता के बीच विकास पुरूष के रूप में जाने जाते है। इनके चेहरे से बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे लेकिन इनकी कृतियों से और कीर्ति से नावाकिफ़ भी नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि आज यह बहुत सुकून देह है कि हर पेशे और हर समुदाय के लोग अपने जनतांत्रिक अधिकारों का निर्भिक होकर प्रयोग कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर ही मतदान होता था। हमेशा यह जरूरी नहीं था कि ऐसे प्रभाव वाले बाहुबली जमीदार या सामत ही होते थे। बहुत बार ऐसे प्रभाव के साथ विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक बौद्धिक हैसियत वाले जेनुइन जन नेता थे और उनके कहने पर भी लोग मतदान करते थे।

नागेन्द्र नाथ ओझा बताते हैं कि जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, और जैसे-जैसे जन चेतना तथा लोकतांत्रिक चेतना बढ़ी लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करने लगे, स्वतंत्र होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगे तो एक ऐसा भी दौर आया जब बूथ कब्जा किये जाने लगे, लोगों को बूथों पर जाने से रोका जाने लगा। कालान्तर में जब धीरे-धीरे अर्थिक समृद्धि आई और लोग जीवन यापन के लिए किसी की दया पर आश्रित नहीं रहे तो वर्चस्व से भी बाहर आए। पहले की अपेक्षा इन मायनों में तो बेहतर हुई है दुनिया।

अपने अनुभवों को साझा करने हुए पूर्व सांसद ने बताया कि राज्य सभा सांसद के रूप में मैने जो किया और उसके बाद विधानसभा के लिए चुनाव लड़ते हुए जब मैं लोगों के बीच गया तो लगा कि मेरी छवि तो विकास पुरूष की ही है और यह तब था जब कि जातिवाद का जहर समाज की नस-नस में तैर रहा था। उसी समय यह भी लगा कि विकास पुरूष की छवि अलग बात है, चुनावी जीत अलग बात है।

उन्होंने कहा कि यदि आज जब विकास-विकास के गगन भेदी नारे हैं उस समय भी मैं जीत का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी भी अपनी जाति के ठेकेदारों को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता। आज विकास जाति से टैंग हो गया है। विकास तो पैसे से होगा। विकास के नाम पर पैसा भी आया, योजनाएँ भी बनी; लेकिन वे सफल कितनी हुंइं यह जानना बाकी है। विकास का वास्तविक मुद्दा गौड़ हो गया, लूट की संस्कृति प्रधान हो गई इसे सुगम बनाने के लिए जाति कवच बन गई।

आगे बताते है ओझा जी कि गैर कम्युनिस्ट सारे दल 1991 से जारी अर्थनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वाम ही है जो वैकल्पिक अर्थनीति में साथ जनता के बीच है। वे जनता को जातियों के समूह के रूप में नहीं एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में

इस वर्ष के विधानसभाई चुनावों की गहमागहमी कितना बदला चुनाव, कितनी राजनीति। में बिहार की जनता भी अपनी अधिकतम भागीदारी को लेकर उत्सुक है। गणादेश टीम को भी उत्सुकता हुई कि हमारे पूर्व जन प्रतिनिधि क्या सोचते हैं, उसे जाना जाए। वे इस समय चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। पर चुनावों पर सचेत निगाह बनाए हुए है। `कितना बदला चुनाव, कितनी बदली राजनीति' प्रस्तुत है इस श्रृखला भी पहली कड़ी में पूर्व राज्य सभा सांसद नागेन्द्र नाथ ओझा के अनुभव।

चुनाव में तीन मुस्लिम दल ठोंकेंगे ताल

पिछले दिनों एआईएमआईएम द्वारा बिहार चुनाव में शिरकत करने की घोषणा ने सियासी हलकों में तो खलबली मचाई ही, किंतु दो और मुस्लिम पार्टियों द्वारा चुनाव में उतरने के ऐलान ने मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए दलों के भीतर बेचैनी पैदा कर दी है। असउद्दीन की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अलावा मौलाना तकीर रज़ा की इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल और केएम शरीफ की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक इकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआइ) भी बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है।

पटना : उल्लेखनीय है कि तीनों पार्टियों की पहचान मुस्लिम पार्टियों के रूप में है और तीनों मुस्लिमों के हित की आवाज उठाने का दावा करती हैं। उल्लेखनीय यह भी कि तीनों ही पार्टियां बिहार से बाहर की हैं और बिहार में पहले से इनका कोई जनाधार नहीं रहा है। जाहिर है इन तीनों दलों की नजर राज्य के मुस्लिम वोट पर है, जिनकी बिहार में अच्छी खासी संख्या है। बिहार में 16 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। बिहार चुनाव के समीकरणों के मद्देनजर देखा जाय तो राज्य के तकरीबन सभी प्रमुख दलों की इस मुस्लिम वोटबैंक पर नजर है। जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को जहां अपनी जीत के लिए इस बड़े वोट बैंक की दरकार है तो वाममोर्चा और तीसरा मोर्चा भी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हालांकि भाजपा को बहुत उम्मीद तो नहीं है फिर भी उसकी कोशिश है कि शाहनवाज हुसैन जैसे अपने मुस्लिम नेता और सहयोगी पार्टियों की बदौलत इस वोट बैंक में वह सेंध लगाने में कामयाब हो। ऐसे में इन तीनों दलों का बिहार चुनाव में क्या प्रदर्शन रहेगा देखना दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए भी कि मुस्लिम मतों को बांटने का आरोप लगाते हुए तीन मुस्लिम संगठनों इंडियन नेशनल लीग, परचम पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल द्वारा गठित इत्तेहाद फ्रंट ने इन तीनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है।

सासाराम विधानसभा-ऐतिहासिक शहर पर है सबकी नजर

सासाराम : जिला मुख्यालय होने के साथ सूबे का एक ऐतिहासिक पहचान रखने वाला शहर सासाराम आज भी एक योग्य प्रत्याशी की तलाश में हैं । शेरशाह सूरी की नगरी के रूप में यह शहर देश हीं नहीं विदेशों में भी मशहूर है। इस शहर ने कई जनप्रतिनिधियों को उंचे मुकाम तक पहुंचाया लेकिन शहर का दुर्भाग्य है कि तरक्की के नाम पर सासाराम आज भी पिछडा है.कारण चाहे जो भी रहे हो लेकिन शहर के विकास के लिए एक विजन के साथ काम करने वाला जनप्रतिनिधि इसे कभी नहीं मिला. 1990 से लेकर 2015 तक 25 वर्षों में 2000-05 को छोड कर 20 वर्ष से स्थानीय विधायक जवाहर प्रसाद सासाराम विधानसभा में एक बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनावी अखाडे में उतर चुके हैं.उनके मुकाबले उनके पुराने चिर-परिचत डॉ अशोक कुमार राजद से महागठबंधन के उम्मीदवार है । ह्यह्यह्यएक ओर निर्वाचन आयोग जहां मतदान प्रतिशत को बढाने के लिए सिर्फ विज्ञापन पर अरबों

रुपये खर्च कर रही है वहीं केवल रोहतास जिले में सरकारी आंकडों के मुताबिक आठ गांवों में अलग-अलग कारणों से कहीं शराबबंदी को लेकर तो कहीं सडक विद्यालय को लेकर मत-बहिष्कार की बातें अभी से होने लगी हैं।

वहीं पुराने खिलाडियों के बीच निर्दलीय पूर्व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह ताल ठोंक कर चुनावी समर में उतर चुके हैं. तो समाजवादी पार्टी से वैश्य पात्याशी सत्येंद्र शाह भी लडाई को रोचक बनाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखना चाह रहे हैं ।

वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप् में सत्येंद्र शाह ने 7000 से अधिक मत लाकर कई राजनैतिक

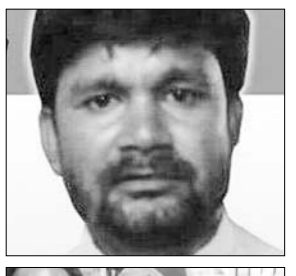

पंडितों को हैरत में डाल दिया था. जहां पांच वर्ष के दौरान सत्येंद्र शाह विभिन्न मोरचों पर शहर की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहे. हालांकि कृष्ण कुमार सिंह अपने जातिगत वोट के साथ अकलियतों और दलितों-पिछडों का समर्थन भी मिलने के संकेत दे रहे हैं.वैसे अब सासाराम में मतदाताओं का रूझान किस ओर जायेगा यह कहना तो अभी मुश्किल है लेकिन इतना तो तय है कि परिवर्तन की चाह रखनेवाले यहां

के लोगों ने महागठबंधन से किसी नये चेहरे को जगह मिलती तो निश्चित तौर पर सासाराम में महागठबंधन एनडीए के मुकाबले आगे होता. चूंकि पिछले एक वर्ष से सरकार की नीतियों के साथ जदयू के पक्ष में जिस तरह से लोगों का जुडाव हुआ था उसके लिए पूर्व जिलाध्यक्ष ईश्वरचंद कुशवाहा का अहम योगदान था।

सासाराम सीट से पांच बार के पराजित उम्मीदवार को पुन: प्रत्याशी बनाना और ईश्वरचंद कुशवाहा और रामधनी सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं का टिकट काट कर जदयू ने क्या संदेश देने की कोशिश की है यह आम मतदाताओं की समझ से बाहर की चीज है. हालांकि करगहर में रामधनी सिंह का टिकट काट कर युवा कार्यकर्ता वशिष्ठ सिंह और चेनारी में पूर्व विधायक मुरारी प्रसाद गौतम का टिकट काट कर पूर्व प्रमुख व सामान्य कार्यकर्ता मंगल राम को टिकट देकर जदयू-कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को तरजीह तो दी है लेकिन इन उम्मीदवारों को जनता का कितना आर्शीवाद मिलेगा यह तो आठ नवंबर के बाद ही पता चल सकेगा. वैसे सासाराम में मुसलिम समुदाय का मत काफी प्रभावशाली है जिसे लेकर अभी से सभी प्रत्याशी इन मतों को अपनी ओर करने में हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. वैसे कुशवाहा बहुल इस सीट पर अन्य जातियों की संख्या भी अच्छी होने से इस बार परिवर्तन की उम्मीद भी आम मतदाता संजाये हुए है लेकिन पुराने प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना यहां की मजबूरी भी है।

समान स्कूल प्रणाली
एक साहसिक फैसला

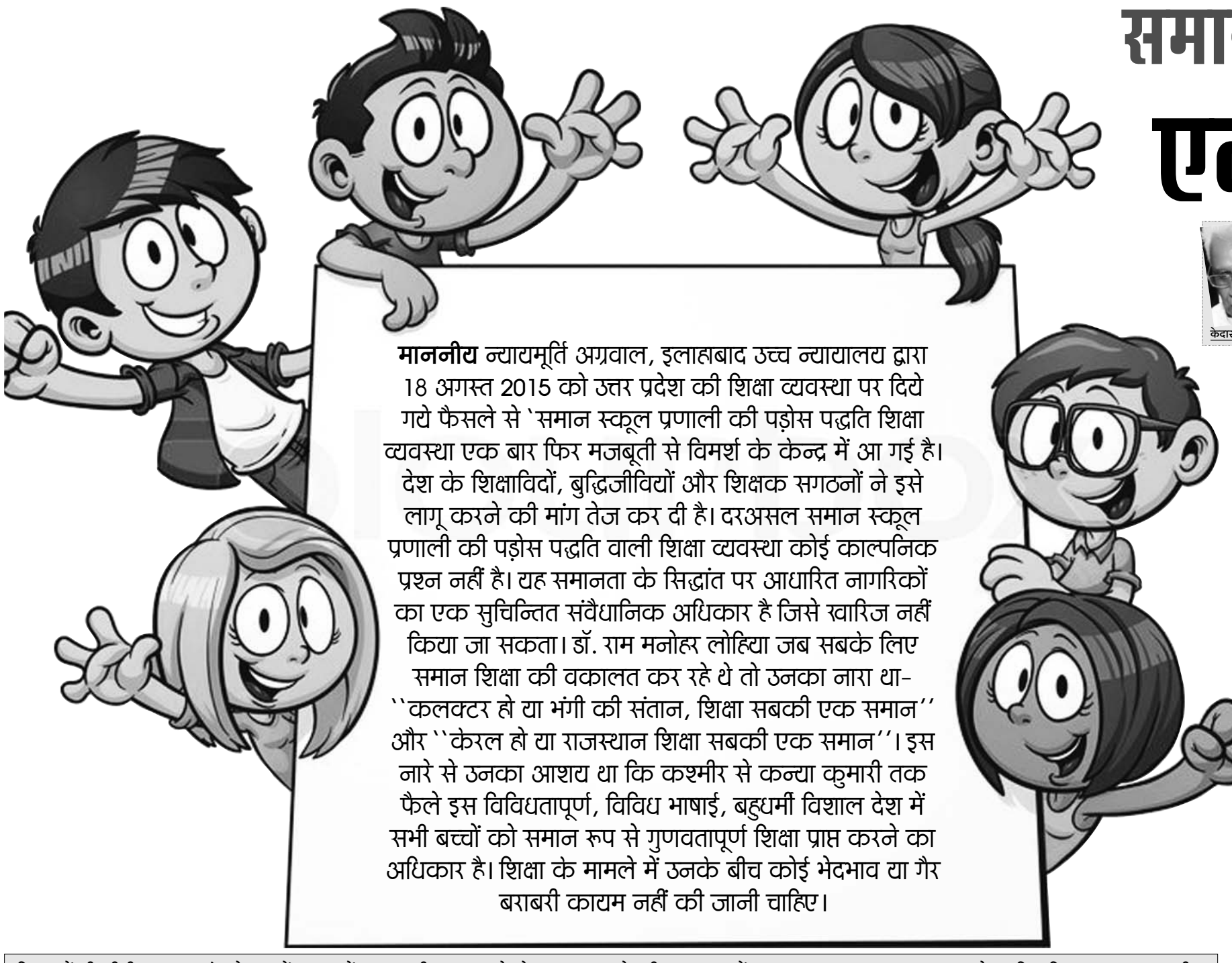

माननीय न्यायमूर्ति अग्रवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 18 अगस्त 2015 को उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर दिये गये फैसले से `समान स्कूल प्रणाली की पड़ोस पद्धति शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर मजबूती से विमर्श के केन्द्र में आ गई है। देश के शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और शिक्षक सगठनों ने इसे लागू करने की मांग तेज कर दी है। दरअसल समान स्कूल प्रणाली की पड़ोस पद्धति वाली शिक्षा व्यवस्था कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित नागरिकों का एक सुचिन्तित संवैधानिक अधिकार है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। डॉ. राम मनोहर लोहिया जब सबके लिए समान शिक्षा की वकालत कर रहे थे तो उनका नारा था- ``कलक्टर हो या भंगी की संतान, शिक्षा सबकी एक समान'' और ``केरल हो या राजस्थान शिक्षा सबकी एक समान''। इस नारे से उनका आशय था कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक फैले इस विविधतापूर्ण, विविध भाषाई, बहुधर्मी विशाल देश में सभी बच्चों को समान रूप से गुणवतापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा के मामले में उनके बीच कोई भेदभाव या गैर बराबरी कायम नहीं की जानी चाहिए।

बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2006 में राजग की सरकार ने प्रो. मुचकुन्द दूबे की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर समान स्कूल आयोग गठित किया था। इसका बीज कोठारी आयोग की उसी अनुशंसा में निहित था। जिसकी चर्चा उपर की जा चुकी है। अयोग ने निर्धारित समय सीमा में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, भावी दशा-दिशा का सम्यक् विश्लेषण करते हुए जून 2007 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उसने बिहार में समान स्कूल प्रणाली की पड़ोस पद्धति शिक्षा स्थापित करने हेतु एक रोड मैप और वित्तीय आकलन भी प्रस्तुत किया था। जिसमें पाचं वर्षों में कुल साढ़े सतरह हजार करोड़ का बजट आकलित था। लेकिन जिस उत्साह से सरकार ने आयोग गठित किया था। और शिक्षा सुधार का दावा पेश किया था उसी उत्साह से उसने आयोग की रिपोर्ट को आलमारियों में बन्द भी कर दिया। कई बार विधान परिषद में प्रश्न उठाने जाने के बावजूद रिपोर्ट विधान मंडल के पटल पर भी नहीं रखी जा सकी और नहीं उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक समझा गया।

केदार नाथ पांडेय

स्वातंत्र्योत्तर काल में जब भारत की सम्पपूर्ण शिक्षा पर सांगोपांग विचार करने के लिए सन् 1964 में डॉ. डी. एस कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ जिसमें देश-विदेश के विद्वान शामिल थे, तो उसने काफी सचिन्तित से विमर्श कर 1966 में जो रिपोर्ट सौंपी उसका नाम रखा-`` Education for National development'' यानि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। आयोग का मानना था कि शिक्षा की समुचित व्यवस्था के बगैर राष्ट्रीय विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। 1968 में देश की संसद ने उसे प्रतिवेदन पर एक राष्ट्रीय शिक्षा की नीति स्वीकृत की। जिसमें शिक्षा संरचना, शिक्षक, शिक्षा के माध्यम की भाषा और राष्ट्रीय विकास के लिए सारे मुद्दे समाहित थे। 10+2+3 की शिक्षा संरचना उसी नीति की देन है। आयोग ने विश्व के विकसित देशों की शिक्षा प्रणालियों के अध्ययन के आधार पर सुझाया कि भारत में समान स्कूल प्रणाली की शिक्षा लागू की जानी चाहिए जो पड़ोस पद्धति पर आधारित हो। यानि एक विद्यालय को केन्द्र मानकर उसकी निर्धारित परिधि के सारे नागरिकों को चाहे मंत्री, सांसद, विधायक, उच्चाधिकारी अथवा किसान, मजदूर हों उनके लिए उसी स्कूल में शिक्षा की बाध्यकारी व्यवस्था होनी चाहिए। आयोग का मत था कि इस व्यवस्था से संविधान प्रदत्त समानता का अधिकार तो कायम होगा ही, नागरिकों के बीच जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव भी अंकुरित नहीं होगा। जो एक स्वस्थ और दीर्घकालिक के लिए आवश्यक शर्त है। चूंकि सभी वर्गों के बच्चे अपने पड़ोस के विद्यालय में अध्ययन करेंगे इसलिए मंत्री, सांसद, विधायक, उच्चाधिकारी, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, किसान, मजदूर सभी लोगों का ध्यान भी उस विद्यालय पर होगा।

उसकी आधारभूत संरचना तथा शिक्षक सभी विचार दृष्टि के केन्द्र में होंगे। शिक्षक भी योग्य, कुशल एवं सम्मान-जनक वेतन प्राप्त करने वाले होंगे। आपसी समन्वय से जो राष्ट्र बनेगा उसका आपसी सद्भाव भी ठीक होगा। आयोग की यह अनुशंसा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली आदि जी आठ के देशों में पहले से सफलतापूर्वक संचालित शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। उन देशों में आज भी यह शिक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है।

आयोग के सुझाव पर राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी

आयोग का सुझाव था कि कानून सम्मत तरीके से इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए और शिक्षा को समाजिक आर्थिक रूपान्तण का हथियार मानते हुए देश के बजट का छह फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। जिसे 1980 के बाद बढ़ती आबादी के हिसाब से और बढ़ाया जाना चाहिए। दुर्योग से कोठारी आयोग की इन दो महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी से लागू नहीं किया गया। देश के सारे नागरिकों को अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनने की आजादी प्रदान कर दी गई। फिर 1986 में राजीव गांधी ने पुन: राष्ट्रीय शिक्षा की नयी नीति बनाई तो उसमें भी स्वीकार किया गया कि गलतियां हुई हैं और उन्हें सुधारा जाना चाहिए और इस प्रकार नयी शिक्षा नीति में भी समान स्कूल प्रणाली की पड़ोस पद्धति शिक्षा व्यवस्था और जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की स्वीकारोक्ति की गई।

लेकिन हुआ उल्टा, समान स्कूल की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में दून टाइप नवोदय विद्यालय स्थापित कर फिर एक समान बार समानता के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। शिक्षा की बहुपरती व्यवस्था अविच्छिन्न रूप जारी रही बल्कि और बढ़ा दी गई। शिक्षा पर जीडीपी का खर्च नेहरू की तुलना में और घटा दिया गया। इसलिए वी पी सिंह की सरकार ने जब नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया तो समिति का साफ-साफ मानना था कि देश में शिक्षा के दो पिरामिड बन गये हैं अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। विडम्बना है कि 69 साल की आजादी के बाद भी स्थिति जस की तस है बल्कि और बिगड़ती चली गई है। वैश्विक पूंजी के हमले के बाद तो इसे रोकने या सुधारने की कोई कवायद दिखाई भी नहीं पड़ती।

माननीय उच्चतम न्यायालय के 93 के उन्नीकृष्णन न्याय निर्णय के बाद संविधान में संशोधन कर और अनुच्छेद 21 (क) जोड़कर छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का नि:शुल्क एवं अनिवार्य अधिकार लागू अवश्य कर दिया गया है लेकिन वह एक छलावा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। पूर्व में संविधान के अनुच्छेद 45 में वर्णित 0-14 वर्ष के बच्चों में से 0-5 वर्ष के लगभग 17 करोड़ बच्चों के दायित्व से सरकार मुक्त हो गई है।

इसलिए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के बहाने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की जो तस्वीर सामने रखी है वह निहायत गन्दी और अफसोसनाक है। न्याय निर्णय के अनुच्छेद 80-90 के अन्तर्गत उन्होंने सम्पूर्ण स्थितियों का वास्तविक चित्र सामने रखा है और सरकार को कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 90 प्रतिशत बच्चों के स्कूलों का कामन मैन स्कूल की संज्ञा दी है। जहां न तो आधारभूत संरचनाएं हैं, न पीने के पानी की व्यवस्था और नहीं गुणवतापूर्ण शिक्षा देने वाले सुयोग्य, प्रशिक्षित और पर्याप्त शिक्षक। ये सभी स्कूल वहां की सरकार, बोर्ड द्वारा संचालित हैं। ये पहली कोटि के विद्यालय हैं।

उन्होंने दूसरी कोटि में उच्च सुविधा प्राप्त वर्ग के बच्चों के स्कूलों को रखा है और उन्हों Elite School की संज्ञा दी है। जहां उत्तम आधारभूत संरचना, शौचालय, पानी की व्यवस्था, अच्छे पुस्कालय, एसी कमरे आदि सब कुछ हैं।

इन्हीं विद्यालयों में देश के मंत्रीयों, सांसदों, विधायकों, उच्च नौकरशाहों और समृद्ध वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें सुयोग्य, कुशल, अच्छे वेतनधारी शिक्षक नसीब हैं। तीसरी कोटि में वैसे विद्यालयों की चर्चा की है जो Semi Elite स्कूल हैं जो Elite से नीचे और 'कॉमन मैन' स्कूल से थोड़ा उपर हैं। यहां मध्यवर्ती, अर्द्ध-समृद्ध वर्ग, निचले स्तर के नौकरशाहों के बच्चे पढ़ते हैं। यहां कॉमन मैन स्कूल से सुविधाएं थोड़ी बेहतर हैं। आगे के अच्छेदों में शिक्षा की नंगी सच्चाई वर्णित है कि कामन मैन स्कूलों में शिक्षाकों की नियुक्तियां सिर्फ अपने मतदाताओं को रिझाने, फुसलाने तथा राजनैतिक लाभ के लिए की जाती हैं। इनका उद्देश्य देश के बच्चों की उचित शिक्षा की व्यवस्था करना नहीं है। देश के समृद्ध वर्ग, शासक वर्ग यहां तक की नौकरशाही, और नागरिकों का भी ध्यान इन स्कूलों की ओर नहीं जाता है और नहीं कोई सुविधा, आधारभूत संरचना, शिक्षक की ओर दृष्टि डालता है। ये उपेक्षित और त्याज्य हैं।

इसी प्रसंग में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को याद किया है जिन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की थी और इसे सुधारना केन्द्र तथा राज्य सरकारों का दायित्व बताया था। माननीय न्यायमूर्ति ने निदेश दिया है कि जो लोग सरकारी खजाने से वेतन प्राप्त करते हैं, चाहे माननीय मंत्री हों, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी,पूलिस अधीक्षक अथवा नौकरशाही के अंग हों सभी अपने बच्चों को पड़ोस के सरकारी विद्यालय में ही पढ़ावें ताकि उन बच्चों में समुदाय की भावना का विकास हो सके। उनके बीच समाजिक वैषम्य खाई पाटी जा सके और सामाजिक भेदभाव और बटबारा न हो।

उनका कहना है कि इस व्यवस्था से इन स्कूलों पर सबका ध्यान केन्द्रित होगा। वे उपेक्षित, अमर्यादित और दोयम दर्जे के नहीं समझें जायेंगे और एतदर्थ उत्तर प्रदेश की सरकार कानून बनाना चाहिए। न्याय निर्णय में यह भी दर्ज है कि यदि समाज यह वर्ग अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं पढ़ावें तो उनके वेतन से उतनी राशि काटकर जितनी वे Elite स्कूलों में अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, उन स्कूलों की व्यवस्था, निर्माण पर खर्च किया जाय। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट छह माह में शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित करने का निदेश भी दिया है।

आजादी के बाद देश में शिक्षा किस रास्ते जा रही!

काठोरी आयोग की अनुशंसा अथवा मुचकुन्द दूबे आयोग की अनुशंसाएं स्वतंत्र भारत अथवा बिहार में क्यों नहीं लागू हुई इसके उत्तर के लिए पिछली सदी के पचासोत्तरी काल में जाना पड़ेगा। उस समय आजाद भारत में एक नया माहौल पैदा हुआ था। जिसकी व्यवस्था तत्कालीन कवि, रचनाकार, राजनीतिज्ञ अपने-अपने तरीके से कर रहे थे। उनके पास आजादी से उत्पन्न सामाजिक विकास को समझने की एक वैज्ञानिक विश्व दृष्टि थी, लेकिन उनमें गहरे मतभेद थे। बावजूद इस बात पर वे एकमत थे कि यह वो आजादी नहीं है जिसकी वो कल्पना कर रहे थे।

उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में शिक्षा पर चली बहस में जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बालक-बालिकाओं की अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा की वकालत की तो लम्बे विमर्श और मशक्कत के बाद भी इसे मौलिक अधिकारों के खंड तीन में शामिल नहीं किया जा सका। शिक्षा नीति निर्देशक तत्वों के खंड चार अनुच्छेद 45 में समाहित की गयी। उसके दस वर्षों का अतिरिक्ति समय तय किया गया। कुछ लोग तो बाबा साहेब पर दबाव भी डाल रहे थे कि देश गरीब है इसलिए चौदह वर्ष की उम्र घटाकर कम की जानी चाहिए। लेकिन अम्बेडकर चूंकि सामाजिक उत्पीड़न, विषमता के भोक्ता थे इसलिए वे इसे घटाने पर सहमत नहीं हुए और शिक्षा कम से कम नीति निर्देशक तत्वों वाली खंड में जगह पा सकी।

आजादी के बाद तो धीरे-धीरे यह साफ ही हो गया कि देश का रास्ता किधर से होकर जा रहा है? सत्ता मिलते ही कांग्रेस सुख भोग की राजनीति में ढल और नये सत्ताधारी वर्ग ने जो रास्ता चुना वह 'महाजनों येन गत: स पन्था:' न होकर महाजनी सभ्यता का रास्ता बन गया। पूंजीवादी समाज के निर्माण की कोशिशों से भारतीय समाज के भीतर पूंजीवादी चेतना का विकास तेजी से हुआ। पुराने नैतिक मूल्य ध्वस्त होने लगे और उच्च वर्ग के साथ मध्यवर्ग ने भी धनवान होने तथा अपने परिवार में केन्द्रित होने सारे हथकंडे अपना लिए। 90 के बाद आये भूमंण्डलीकरण के प्रभाव ने इसे और मजबूत दिशा दे दी। फलत:, अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, आदि पूंजीवादी देशों में अपनायी गयी समान शिक्षा प्रणाली यहां लागू नहीं हो पायी। मध्यवर्ग को लाली पाप जरूर दिखाया गया कि यही बेहतर प्रणाली है लेकिन उसकी धार को कुंद करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय सामने ला दिये गये। उन्नीकृष्णन न्याय निर्णय को भी 'डाइल्यूट' कर दिया गया।

ऐसे में इलाहाबाद का न्याय निर्णय कितना कारगार होगा यह एक विचारणीय प्रश्न है? लेकिन राष्ट्रीय विकास की दिशा में इस प्रणाली की महती भूमिका को खारिज नहीं किया जा सकता? इस दौर में भी न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले को साहसिक और ऐतिहासिक मानना ही होगा।

गणदेश
पटना, 04 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com

चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले

दुनिया में कही भी जनतंत्र जन की जिम्मेदारी और भागीदारी पर ही संभव हो सका है और जनतंत्र का दीर्घ जीवन समाज के सोच के खुलेपन और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर निर्भर रहा है। संकीर्णता कट्टरता, असहिष्णुता और संवाद के सिकुड़ते दायरे हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं। शायद लगभग विगत दो वर्षों में तीन तर्कशील अभियानियों की हत्या सिर्फ उनकी वैचारिकी को लेकर गम्भीर संदेश देती है। नागेन्द्र दाभोलकर, गोविन्द पानसरे और एम.एम. कलबुर्गी की हत्याएँ हमें आशकाओं से भर देती हैं। पेरुमल मुरुगन ने लगातार प्रताड़नाओं से तंग आकर अपनी मृत्यु की घोषणा करदी महाराष्ट्र के ऐक्टिविस्ट भरत पाटनेकर भी हत्या की धमकियों से परेशान रहे। कई पत्रकारों, साहित्यकारों की हत्याएँ साबित करती हैं कि असहमत आवाजों से संवाद के लिए स्पेस नहीं छोड़ा हमने। उन आवाजों को बंद कर देना ही सुविधाजनक हो गया है। धर्म, संप्रदाय जाति और अपनी-अपनी अस्मिताओं को लेकर विश्वासों-अंधविश्वासों पर कोई संवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। बौद्धिक परिदृश्य में गहरे आतंक और भय का माहौल है। इसी तंगदिली पर खुलेपन के साथ बात चीत करता प्रस्तुत है इसबार का बहसतलब । इस खुलेपन के साथ कि चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा का सवाल

डॉ. व्रजकुमार पांडेय

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था की आधारशिला है। प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता को बड़ा महत्व देती है। इसके बिना जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को जो लोकतांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना संभव नहीं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है - शब्दों, लेखों मुद्रणों ;च्तपदजपदहद्धए चिन्हों या किसी अन्य प्रकार के अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्ति करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके। इस प्रकार इन संकेतों, अंकों, चिन्हों तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। संविधान के अनु. 19 में प्रयुक्त 'अभिव्यक्ति' शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों के व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वे अभिव्यक्ति पदावली के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 19 (क) में 'जानने का अधिकार' भी है -

अनु. 19 (1) (क) में 'जानने का अधिकार' ;त्पहीज जव ाददवूद्ध भी शामिल है। इसमें सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएँ जानने का अधिकार भी आता है। केवल आपवादिक मामले में जब की सुरक्षा अथवा लोकहित में आवश्यक हो तभी उनका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार एक खुली सरकार होती है जिसके विषय में जनता को जानने का अधिकार होता है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वाक् और स्वतंत्र विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित है। उस स्वतंत्रता के लिए परिचालन की स्वतंत्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि प्रकाशन की स्वतंत्रता। निस्संदेह परिचालन के बिना प्रकाशन का कोई महत्व नहीं होगा।

लोकहित के महत्व की बातों का प्रकाशन करने का समाचार पत्रों को पूर्ण अधिकार है और उस पर पूरा अवरोध नहीं लगाया जा सकता है। नागरिकों को 'जानने का अधिकार' एक मूल अधिकार है, इस पर ''वर्तमान और आसन्न'' खतरे के आधार पर निर्बन्ध लगाये जा सकते हैं।

ऐसी बातों के प्रकाशन पर पूर्व अवरोध से प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता है और वह असंवैधानिक है।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। इसमें दूसरों के विचारों के प्रसार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है।

संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को लेकर बहुत सारी बहसें और न्यायालयों में परिवाद उठे और न्यायिक निर्णयों द्वारा इसे सुरक्षा प्रदान करने संबंधी निर्णय भी हुए। दुनिया के लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गुहार लगायी। 1935 के अन्तर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन ने जो पेरिस में आयोजित हुआ था - उसका मुख्य प्रस्ताव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर ही था।

जब से भाजपा की सरकार बनी है - राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने शिक्षा, संस्कृति और इतिहास एवं भारत की विरासत को तहस-नहस करने का व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। छात्र क्या पढ़ें या नहीं पढ़ें, क्या खायें या क्या नहीं खायें, क्या पहने या क्या नहीं पहने - इनकी हिदायतें दी जा रही हैं। लेखक वही लिखें जो हमारी विचारधारा कहती है। महत्वपूर्ण अकादमिक और बौद्धिक संस्थाओं पर कब्जा कर - उनके परम्परागत विचारों और निधियों को तहस- नहस करने का अभियान तेजी पर है। ऐसे लेखक जिनकी विचारधारा और लेखन से आर.एस.एस. और अन्य हिन्दू धार्मिक संस्थाओं का विरोध है - वे वैचारिक आधार पर, तर्क-वितर्क, शास्त्रार्थ एवं बहस करना नहीं चाहते हैं बल्कि सीधे उन्हें कत्ल कर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं।

अंध विश्वास, धर्मान्धता, जादू-टोना और बाबाओं के खिलाफ मुखर रहे अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख नरेन्द्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 की हत्या, 16 फरवरी 2014 को कम्युनिस्ट नेता गोविन्द पानसरे और उनकी पत्नी उमा पानसरे पर जानलेवा हमला और पानसरे को गोली मारकर की गई हत्या - ये दोनों हत्याएं सनातन संस्था के कार्यकर्त्ताओं ने की है और इसकी पुष्टि भी हुई है। 2015 के सितम्बर में तर्कवादी लेखक और कन्नड़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. एम. कालबुर्गी की नृशंस हत्या कर दी गई। प्रो. कालबुर्गी बहुत लम्बे समय से अपने प्रगतिशील, आदर्शवादी, तर्कवादी सोच और धर्मनिरपेक्षतावादी सोच के साथ लोगों को जागरूक करते रहे थे। उन्होंने अंध विश्वास के खिलाफ जंग छेड़ा था। इस वजह से वे चरमपंथियों के निशाने पर थे। पुलिस और उस क्षेत्र के लोगों के कथनानुसार उनकी हत्या भगवा संगठनों ने की है।

इन घटनाओं के आलोक में हम सोचने को मजबूर हैं कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधान के रहते हुए, उसके उल्लंघन करनेवालों पर दण्ड के नियमों के बावजूद ऐसे लोग देश में विचरण कर रहे हैं और दूसरों की अभिव्यक्ति के अधिकार पर जो उनके विचारों से मेल नहीं खाते उनको खत्म करने का अभियान चला रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार जिसके मंत्री संविधान की शपथ लेकर सरकार चला रहे हैं और उनमें से ही कुछ मंत्री अपने बयानों से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पार्टी के कुछ सांसद भी कुछ उसी तरह के बयान देकर दहसत फैलाने की कोशिश करते हैं और ये बयान दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि जर्मनी में हिटलर लोकतांत्रिक तरीके यानी चुनाव जीतकर ही सत्ता में आया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद लोकतंत्र को खत्म कर दिया था। फासीवाद लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है। इस विचार के अनुसार प्रकृति ने जन्म से व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से असमान बनाया है। सब लोग शासन करने के योग्य नहीं हैं। शासन केवल योग्य व्यक्ति ही कर सकते हैं। साधारण जनता का यह कर्तव्य है कि अपने नेताओं के आदेशों का पालन करे और अनुशासन बनाए रखे। वे इस बात के विरोधी थे कि आम जनता सरकार की आलोचना कर सकती है। इसीलिए फासिस्टों के सत्तारूढ़ होते ही समाचार पत्रों और अन्य प्रचार के साधनों पर प्रतिबंध लगा दिये गये थे। फासीवादियों को व्यक्ति के अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार नहीं है।

जैसा हम देख रहे हैं आर.एस.एस. फासीवादी विचारों के रास्ते की ओर बढ़ रहा है। सरकार इनके विरोध की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए जरूरी है कि जनता इनके खिलाफ गोलबन्द हो। यह गोलबन्दी न केवल अभिव्यक्ति की रक्षा करेगी बल्कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों पर भी लगाम लगायेगी।

हिंसक समय में चुप्पी

अपूर्वानंद

क्रोध कहां है? या क्षोभ? अठहत्तर साल के एक विद्वान, शोधकर्ता, अध्यापक, पूर्व कुलपति और लेखक की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाए और कक्षाएं चलती रहें, शोध-संगोष्ठियां होती रहें, इससे बड़ा मजाक नहीं। जो मारा गया, वह साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेता था, कर्नाटक के कन्नड़ विश्वविद्यालय का कुलपति रह चुका था। न तो लेखकों के इस संगठन ने और न देश के विश्वविद्यालयों ने अपनी बिरादरी के एक सदस्य की हत्या पर कोई दुख प्रकट किया, नाराजगी की तो बात ही छोड़ दें! डॉक्टर मलेशप्पा मदिवल्लपा कलबुर्गी प्रख्यात पुरालेख विशेषज्ञ थे। अकादमिक जगत में सम्मानित और लेखक समुदाय में भी समादृत, वे वचन साहित्य के विशेषज्ञ थे। कर्नाटक के ताकतवर लिंगायत समुदाय के सदस्य कलबुर्गी ने वचन की अपनी व्याख्याओं से लिंगायत समुदाय के कट्टरपंथी हिस्से को क्षुब्ध किया था। वे तर्कशील थे, मूर्तिपूजा के आलोचक और कन्नड़ समाज में यूआर अनंतमूर्ति के साथ मिल कर एक उदार, बुद्धिवादी नजरिया विकसित करने का उद्यम कर रहे थे। ज्ञान के काम को, अगर वह वास्तविक ज्ञान का हो, हमेशा यथास्थितिवादियों का विरोध झेलना पड़ता है। विचार, जिसका कोई विरोध न हो रहा हो, नया है भी कि नहीं, इस पर शक किया जाना चाहिए। बल्कि किसी विचार की परीक्षा का एक तरीका यह भी है कि उसके विरोधियों को देखा जाए। किताबें लिखी जाती हैं, सेमिनार किए जाते हैं, वे समाज के सोचने-समझने के तरीके को झकझोरते हों, जरूरी नहीं। इसीलिए, ज्ञान-सृजन-कर्म में लगे कुछ लोग इस सीमा से बाहर निकल कर कुछ और करते हैं। उन्हें सुरक्षित अकादमिक दायरे में चक्कर लगाते रहने से घुटन होती है। प्रायः अकादमिक दुनिया के लोग इन्हें किंचित मुदित भाव से देखते हैं, मानो ये विद्वत्ता की गंभीर शालीनता का उल्लंघन कर रहे हों, शोर मचा रहे हों, जो बौद्धिकों का काम नहीं। कलबुर्गी की हत्या पर सार्वजनिक क्षोभ व्यक्त करने वाले पहचाने चेहरे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष के तौर पर बदनाम हैं! लेकिन जो खुद को इस तरह के विशेषण के तंग जैकेट में नहीं डालना चाहते, उन्हें क्षोभ हुआ कि नहीं या उन्होंने गिरीश कर्नाड जैसे लोगों को ऐसे वक्तों की रूदाली मान कर अपना काम भी उन्हीं के जिम्मे लगा दिया है! कलबुर्गी तो फिर भी विश्वविद्यालय समुदाय के सदस्य थे। उनके पहले मारे गए गोविंद पानसरे या नरेंद्र दाभोलकर बाहरी ही कहे जाएंगे, हालांकि जो वे कर रहे थे, उसे बुद्धि या ज्ञान का काम ही कहा जाएगा। पिछले तीन वर्षों में इन तीन तर्कशील विद्वानों की हत्या को इस महाद्वीपीय देश में नगण्य मान लिया गया है। इसलिए इन्हें किसी सामाजिक प्रवृत्ति, किसी खास राजनीतिक रुख से जोड़ने पर कुछ लोग अतिशयोक्ति का आरोप लगाते हैं। लेकिन हम सब अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले दिनों अभिजीत रॉय, वशिकुर्रहमान और अनंत विजय दास की हत्याओं को उस समाज के असहिष्णु हो जाने का पक्का प्रमाण मानते हैं। खुद को उदार, सहिष्णु और अन्य समाजों को मूलतः कट्टर मानने वाले इस पर ध्यान नहीं देते कि उनके यहां हिंसा की कितनी स्वीकृति है। हिंसा का खुलेआम प्रचार कितना सह्य है! आखिर कर्नाटक में ही अनंतमूर्ति को एक व्यक्ति विशेष की चुनावी विजय के बाद पाकिस्तान भेज देने का एलान करने वाले और फिर उनकी मृत्यु पर खुलेआम खुशियां मनाने वाले तो अब भी छुट्टा घूम रहे हैं! तमिलनाडु में लेखक पेरुमल मुरुगन को धमकियां देने वालों की तंबीह की बात तो दूर, पुलिस ने खुद मुरुगन को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। और अभी कलबुर्गी की हत्या के बाद उस पर खुशी जताने वाले और मैसूर के एक दूसरे तर्कशील विद्वान भगवान को तैयार रहने की धमकी देने वाले ट्विटरबाज को गिरफ्तार तो नहीं ही किया गया है। यह ठीक है कि हर समाज और देश में ऐसे हिंसक तत्त्व होंगे और शायद कलबुर्गी जैसे लोगों को बचाने की पक्की गारंटी करना संभव न होगा। लेकिन जनतांत्रिक राज्य का काम है स्वतंत्र विचारों को सुरक्षा का अहसास दिलाना। जनतांत्रिक समाज का बुनियादी गुण है, परस्पर विरोधी विचारों की टकराहट के अवकाश की हिफाजत। कोई नहीं कह सकता कि 'अंधविश्वासी विचारों' का खात्मा राज्य का काम है। वे रहेंगे और 'तर्कशील' विचारों पर हमला भी करेंगे। लेकिन इस टकराहट में अगर वे हिंसा के जरिए किसी को खामोश करते हैं, तो समाज के उदार और राज्य के जनतांत्रिक होने में संदेह है। भारत के बारे में कहा जाता है कि वह उदार और धर्मनिरपेक्ष इसलिए है कि वह हिंदूबहुल है। मजा यह कि हिंदू सचमुच खुद को स्वभावतः उदार समझ बैठे हैं! हालांकि इस धर्म का इतिहास भी वैसी ही हिंसा और क्रूरता से अटा पड़ा है जैसी किसी भी दूसरे धर्म के इतिहास में पाई जाती है। लेकिन अगर उसे इस आत्मछवि से प्रेम है, तो फिर हिंसा के विरुद्ध उदार हिंदुओं की खामोशी के क्या मायने हैं? क्या इसका अर्थ है उदार हिंदुओं की पराजय? दूसरे, हिंदू धर्म और सामुदायिक अहंकार के बीच एक नया गठजोड़ दिखाई देता है। जैसे कलबुर्गी की हत्या क्या लिंगायत क्रोध के कारण हुई या हिंदू क्रोध के कारण? कहां दोनों एक-दूसरे से अलग होते हैं? जैसे मुरुगन के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने इसे मुरुगन के समुदाय का निर्णय बता कर पल्ला झाड़ा, हालांकि विरोध की शुरुआत में वे सक्रिय थे। लेकिन समुदाय के आगे आते ही वे परदे के पीछे चले गए। एक दूसरे प्रसंग में यह जानना कठिन हो सकता है कि मुजफ्फरनगर या हरियाणा की हिंसा जाटों ने की या हिंदुओं ने? या इस हिंसा का स्रोत कोई एक है और अब उसका नाम कोई लेना नहीं चाहता। बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद, रामसेने या कोई और हिंदू वाहिनी, ये सब उस विशाल परिवार के सदस्य हैं। यह परिवार एक संगठन है भी और नहीं भी। इसका अधिकतर काम अनौपचारिक तरीके से चलता है। जैसे इसकी सदस्यता का रजिस्टर नहीं, वैसे ही इसके किसी भी निर्णय का कोई प्रमाण नहीं। आप चाहें तो इसे दुनिया का एकमात्र खुला भूमिगत तंत्र मान सकते हैं। यह अपने किसी अपराध का कोई निशान नहीं छोड़ता। अगर अपराध में कोई गिरफ्त में आ गया तो फौरन उससे हाथ धो लेता है, लेकिन उसके कृत्य का समर्थन अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर करने की छूट लेता है। यह इस हद तक है कि अपने मुखपत्र को भी मौका पड़ते ही अपना मुखपत्र मानने से इनकार कर देता है। हिंदू धर्म को ही राष्ट्र मान कर उसकी सेवा करने वाले इस संगठन के सदस्य जो करते हैं, वह सांगठनिक नहीं, व्यक्तिगत माना जाता है। इसलिए गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे दोषी हुआ, लेकिन इस हत्या पर दीवाली मनाना क्या किसी दंड संहिता में अपराध माना जा सकता है? अगर मैं किसी को राक्षस मानता हूं तो उसकी हत्या को वध कहना कानूनी दृष्टि से कैसे अपराध ठहराया जा सकेगा? बाबरी मस्जिद के ढाहने का अभियान यह चलाएगा, लेकिन ढाहने वालों के कृत्य का जिम्मा नहीं लेगा। इसके बाद उस कृत्य का समर्थन जनतांत्रिक अधिकार के नाम पर करता रहेगा! ग्राहम स्टेंस की हत्या भी दारा सिंह का निजी निर्णय है, लेकिन उसका औचित्य निरूपण विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी है! भारतीय और खासकर हिंदू समाज जब तक इस धोखाधड़ी को बर्दाश्त करता रहेगा, कलबुर्गी की हत्या पर शोक प्रस्ताव आत्मवंचना के अलावा और कुछ न होगा।

(साभार- जनसत्ता)

बंददिमागी के विरुद्ध बोलने की सजा

एक ऐसे समाज के बारे में क्या कहेंगे, जहां लेखकों को बंदूक की गोलियों का सामना करना पड़ता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पत्थर या बम बरसाए जाते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले भारत में दो साल के अंदर तीन तर्कशील विचारकों, कार्यकर्ताओं की हत्या ऐसे ही सवाल खड़े करती है। दो साल पहले पुणे में तर्कशील आंदोलन के कार्यकर्ता और लेखक नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई। इस साल फरवरी में कोल्हापुर में पानसरे की हत्या और अब कर्नाटक में वामपंथी विचारक और कन्नड भाषा के विद्वान एमएम कलबुर्गी की हत्या कर दी गई।

तीनों हत्याओं में एक समानता यह है कि उन्हें सांप्रदायिक ताकतों, जनद्रोही शक्तियों की तरफ से, जो लोगों के दिमागों पर ताले रखना चाहती हैं, लगातार धमकियां मिलती रहीं। मूर्तिपूजा की मुखालफत करने के लिए कुछ समय पहले प्रोफेसर कलबुर्गी के घर पर हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकताओं ने पथराव भी किया था। अतिवादियों के बढ़ते मनोबल के चलते उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, मगर कुछ समय पहले प्रोफेसर कलबुर्गी ने उसे लौटा दिया था। उनका कहना था कि विचारों की रक्षा के लिए संगीनों की जरूरत नहीं होती। -

गौरतलब है कि तीनों हत्याओं का तरीका एक था- मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावर और उनमें से एक का गोली चलाना। भारत के पश्चिमी हिस्से में सक्रिय एक अतिवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो इसके पहले भी आतंकी घटनाओं में शामिल हो चुके हैं, संदेह प्रकट किया जा रहा है, मगर अब भी आधिकारिक तौर पर न दाभोलकर के हत्यारे पकड़े गए हैं और न पानसरे के। क्या प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या में भी यही सिलसिला दोहराया जाएगा?

प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या ऐसे समय में हुई है, जब दक्षिण एशिया के इस हिस्से में बहुसंख्यकवादी ताकतें अपने-अपने इलाकों में कहीं धर्म, तो कहीं समुदाय के नाम पर स्वतंत्रमना आवाजों को खामोश करने में लगी हैं। कलबुर्गी की हत्या के चंद रोज पहले ढाका में निलय चक्रवर्ती नामक ब्लॉगर के घर में घुस कर इस्लामवादी अतिवादियों ने बर्बर ढंग से हत्या की थी। गौरतलब है कि यह विगत दो साल में सेक्युलर मानवतावादी ब्लॉगरों में शुमार पांचवें ब्लॉगर की हत्या है, जिसका सिलसिला फरवरी, 2013 में अहमद राजिब हैदर नामक ब्लॉगर की ढाका की सड़क पर हत्या के साथ शुरू हुआ था।

दो साल पहले बांग्लादेश में जब युद्ध अपराधियों को सजा दिलाने और युद्ध अपराधों में शामिल जमाते-

इस्लामी के कर्णधारों को दंडित करने के लिए खड़ा हुए ऐतिहासिक शाहबाग आंदोलन की लामबंदी में इन सेक्युलर मानवतावादी ब्लॉगरों ने अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी, जिसके चलते वे इस्लामवादियों के निशाने पर लगातार हैं।

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी स्वतंत्रमना, तर्क की बात करने वाले, न्याय, प्रगति और समावेशी समाज की बात करने वाले कट्टरपंथ के निशाने पर हैं। ईशनिंदा के नाम पर जेल में बंद आसियाबी का समर्थन करने पहुंचे पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर, जिन्होंने ईशनिंदा कानून का विरोध किया था और वहां के मंत्री शाहबाज बट्टी इसी तरह अतिवादी इस्लामवादियों के हाथों मारे गए थे।

श्रीलंका में वातारकिया विजिथा थेरो जैसे विद्रोही बौद्ध भिक्खु पर, जिन्होंने बोंडु बाला सेना जैसे बौद्ध उग्रवादी समूहों के निर्देशों को मानने से इनकार किया, हमले हुए हैं।

म्यामां में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में विराथू जैसे बौद्ध संत आगे हैं। उधर पंजाब में पशौरा सिंह और हरजोत ओबेरॉय जैसे सिख विद्वानों को सिख परंपरा के 'रखवालों' की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है.

(साभार- जनसत्ता, संपादकीय)

उदय प्रकाश ने लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार, कहा

मुंह छुपाकर चुप बैठने का समय नहीं है यह

कन्नड़ साहित्यकार कलबुर्गी की फासीवादियों द्वारा की गई हत्या से वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रकाश इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी मशहूर कृति मोहनदास को मिला साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटा दिया। इस सबंध में उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा था, पिछले कुछ समय से हमारे देश में लेखकों, कलाकारों, चिंतकों और बौद्धिकों के प्रति जिस तरह का हिंसक, अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार लगातार हो रहा है, जिसकी ताज़ा कड़ी प्रख्यात लेखक, विचारक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ साहित्यकार श्री कलबुर्गी की मतांध हिंदुत्ववादी अपराधियों द्वारा की गई कायराना और दहशतनाक हत्या है, उसने मेरे जैसे अकेले लेखक को भीतर से हिला दिया है। अब यह चुप रहने का और मुंह सिल कर सुरक्षित कहीं छुप जाने का पल नहीं है। वर्ना ये ख़तरे बढ़ते जाएंगे। मैं साहित्यकार कुलबर्गी जी की हत्या के विरोध में मोहन दास नामक कृति पर 2010-11 में प्रदान किये गए साहित्य अकादमी पुरस्कार को विनम्रता, लेकिन सुचिंतित दृढ़ता के साथ लौटाता हूं। अभी गांव में हूं। 7-8 सितंबर तक दिल्ली पहुंचते ही इस संदर्भ में औपचारिक पत्र और राशि भेज दूंगा। मैं उस निर्णायक मंडल के सदस्य, जिनके कारण मोहन दास को यह पुरस्कार मिला, अशोक वाजपेयी और चित्रा मुद्गल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, यह पुरस्कार वापस करता हूं। आप सभी दोस्तों से अपेक्षा है कि आप मेरे इस निर्णय में मेरे साथ बने रहेंगे, पहले की ही तरह।

> **पेरूमल मुरूगन:**- मैने स्वयं अपना मृत्युलेख फेसबुक में प्रकाशित किया है। दुनिया के तमाम लोग लेखक पेरूमलम मुरूगन की उस मुत्यु पर विश्वास करें या न करें मैं स्वयं उस पर यकीन करता हूँ। मेरा मानना है कि समाज में कोई भी लेखक धमकी या भय के माहौल में ज़िंदा नहीं रह सकता।

पटना, 04 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com
गणादेश

सरकारी जॉब की चाह या बेरोजगारी की इंतहा

जब किसी प्रदेश में चपरासी पद के लिए आवेदन करने वालों में इंजिनियर, पीएचडी, परास्नातक, स्नातक आदि शामिल हों तो उस प्रदेश में रोजगार की स्थिति को समझा जा सकता है। चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों का आवेदन करना प्रदेश में बेरोजगारों की भारी-भरकम फ़ौज को चित्रित करता है। कितना भयावह लगता है कि चपरासी के जिस पद की योग्यता महज पांचवीं उत्तीर्ण होना हो, उससे संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या 53 हजार है जबकि इसके उलट उच्चतर शिक्षा प्राप्त लोगों के द्वारा किये गए आवेदन पत्रों की संख्या कई गुणा अधिक है। खबर है कि डेढ़ लाख से अधिक आवेदन पत्र तो इंजिनियरिंग, बीएससी आदि किये लोगों ने भरे हैं जबकि 255 ऐसे व्यक्तियों ने आवेदन किया है जिन्होंने पीएचडी की हुई है। यकीनन यह संख्या किसी भी रूप में हास्य का, नजरअंदाज करने का मसला नहीं है वरन चिंता करने योग्य है। प्रदेश की सरकार को इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है। यदि सम्पूर्ण देश के बजाय प्रदेश की रोजगार सम्बन्धी स्थिति पर निगाह डालें तो पाएंगे कि विगत कई वर्षों में प्रदेश सरकारों द्वारा रोजगार के अवसर सृजित नहीं किये गए हैं। अनेकानेक विभाग ऐसे हैं जहां दशकों से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। दर्जनों के हिसाब से पद खाली पड़े हैं। यदि उच्च शिक्षा को ही देखा जाये तो कई हजार पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं और आयोग द्वारा लगातार विज्ञापन निकालने के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं किया गया है। कुछ ऐसी स्थिति माध्यमिक में, प्राथमिक में देखने को मिल रही है। कमोवेश ऐसी स्थिति सभी विभागों में है। कहीं नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, कहीं नियुक्तियों में अनियमितताएं हैं, कहीं नियमानुसार रिक्तियों को नहीं भरा जा सका है, कहीं अदालती आदेश के कारण भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, कहीं-कहीं तो रिक्तियों को, नियुक्तियों को रद्द ही किया गया है, कहीं भ्रष्टाचार के कारण नियुक्तियों में अनियमितताएं हैं तो कहीं भाई-भतीजावाद, कहीं जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि की वजह से नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं। हालात यह हैं कि स्थायी नियुक्तियां किये जाने के स्थान पर लगभग सभी जगहों पर मानदेय के रूप में, संविदा के रूप में, अंशकालिक रूप में, अस्थायी रूप में नियुक्तियां करके काम निपटाया जा रहा है। इस तरह से कार्य करते लोगों में जहां युवा बेरोजगार भी है, वहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं।

इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी का होना, बेरोजगार युवाओं का होना दर्शाता है कि प्रदेश के आधारभूत ढांचे में बहुत बड़ी खामी है। इस खामी को दूर करने का कार्य सरकार द्वारा किया नहीं जा रहा है और न ही युवाओं द्वारा इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं कि वे शिक्षा के क्षेत्र में उभरते माफियाराज को दूर करने का काम करें। कुकुरमुत्तों की तरफ जगह-जगह उग रहे बहुत से महाविद्यालयों, इंजिनियरिंग संस्थानों ने अपनी व्यवस्थाओं से शिक्षा व्यवस्था को जहां एक ओर खोखला-सा किया है, वहीं, युवाओं को रसातल में भेजने का काम भी किया है। नक़लयुक्त शिक्षा व्यवस्था, अध्यापनशून्य वातावरण, कागजों पर प्रशिक्षित अध्यापक और वास्तविक में अप्रशिक्षित शिक्षकों का होना, शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बना देना आदि ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण शिक्षा संस्थानों ने बेरोजगारों की फ़ौज का निर्माण किया है। बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी रकम चुकाने के बाद भारी-भरकम डिग्री लेने के बाद भी ऐसे युवाओं का आधारभूत ज्ञान शून्य ही रहा, शिक्षा का उद्देश्य इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करना रहा सो लगातार बेरोजगारी की मार देश-प्रदेश को दे रहे हैं। स्पष्ट है कि यदि सरकार इस स्थिति के लिए दोषी है तो ये युवा जो उच्चतम शिक्षा लेने के बाद भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, कम दोषी नहीं हैं।

इसके अलावा जो बात अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, वह यह कि चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने को रोजगार सम्बन्धी मजबूरी बताने वाले ये उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बताएँगे कि वाकई बेरोजगारी की स्थिति इतनी भयावह है कि इनको चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ा, या फिर इनकी डिग्री, शिक्षा इस स्तर की नहीं है कि कहीं उच्च स्तरीय रोजगार, नौकरी प्राप्त की जा सके, या फिर इन सबको सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की चाह हो और उसी की लालसा में, लोभ में चपरासी पद का आवेदन किया हो। मीडिया में खबर आते ही तमाम लोग जिस तरह से सक्रिय होकर सरकार की, व्यवस्था की, बेरोजगारी की बुराई करने लगे थे, उन सभी लोगों को इस तथ्य को भी गंभीरता से लेना होगा कि क्या ये युवा किसी निजी कंपनी में, निजी शिक्षा संस्थान में, किसी निजी कारखाने में कोई काम नहीं कर सकते जो चपरासी पद से ऊपर हो, इनकी डिग्री-योग्यता पर शोभा देता हो।

साभार
कुमारेन्द्र सिंह सेंगर

बिन बारिश सब सून

मुंबई में पिछले पांच सालों में बारिश के दिनों का अनुभव था कि मैं मॉनसून आने के बाद हमेशा बैग में छतरी रखने लगा। मुंबई आने के बाद पहले साल मैं बिना छाते के ही घर से निकलता था। क्या हुआ जो बारिश आ भी गई तो। थोड़ी देर किसी छत, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे। बारिश रुकेगी तो चल पड़ेंगे। दिल्ली की बारिश ने हमें यही सिखाया था। मगर एक-दो बार बारिश में फंसे, तो घंटों फंसे रह गए। इस साल तो मॉनसून की शुरुआत ही ऐसी हुई कि मुंबईकरों के होश ठिकाने लग गए। तीन दिनों तक ये बारिश और वो बारिश। घर से निकले तो घंटों तक राह में ही अटके रहे। छाते ने बैग में अपना परमानेंट बसेरा बना लिया। मगर जून के माह में हुई वो तीन दिनों की बारिश और ये सितंबर के पूर्वाद्ध में गणपति का घरों में आगमन, छाता बैग से कभी बाहर निकला ही नहीं। पूरे आठ महीने जिस बारिश का मैं इंतजार करता हूं, वह इस बार बहुत निराश कर गई। मैंने पिछले साल बारिश की न जाने कितनी ही तस्वीरें खींच-खींचकर ट्विटर पर पोस्ट की। मैं भूला नहीं कि किस तरह बारिश यकबयक ही आती और मेरे दैनंदिन के कामों से उपजे तनावों को चंद लम्हों में ही धो डालती। कई बार बाहर बारिश गिर रही होती थी और मैं भीतर कोई किताब पढ़ रहा होता था। बारिश का संगीत मुझे बार-बार किताब बंद करने को मजबूर कर देता। अक्सर तो ऐसे में मैं किताब को सीने पर औंधा रख देता और बारिश का संगीत सुनने लगता। मगर इस साल तो छतरी बैग में ही धरी की धरी रह गई। खिड़कियों के परदे हटाए तो बाहर निरभ्र आकाश दिखा। बादल भी दिखे कई बार। मगर वे झूठे बादल थे। उन्होंने सिर्फ आस ही जगाई, प्यास नहीं बुझाई। चलो मैंने फिर भी मॉनसून के ये चार महीने निकाल ही लिए किसी तरह, पर मैं उन किसानों के बारे में सोचता हूं, जिन्हें इस निरभ्र आकाश ने लील लिया। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक छोटी-सी फिल्म देखी थी। फिल्म में एक पांच-छह बरस की लड़की है, जो हमेशा अपने पिता का पीछा करती रहती है। पिता काम पर निकलते, तो वह स्कूल जाने की बजाय पिता से छिपकर उनके पीछे-पीछे चल पड़ती। पिता काम करते तो वह दूर छिपकर देखती रहती। पिता काम से लौटते तो वह भी वापस आ जाती। रोज यही चलता। एक दिन वह देखती है कि घर के बाहर जो रस्सी पड़ी रहती थी, वह गायब है। वह पिता के पीछे भागती है। पिता खेतों में एक पेड़ की डाल पर वह रस्सी फेंक रहे होते हैं कि वह उनसे जा लिपटती है। तब समझ आता है कि किसानों की आत्महत्याओं की त्रासदी कितनी संगीन है। वह बच्ची सतत इसी भय में थी कि दूसरे किसानों की तरह कहीं उसके पिता भी आत्महत्या न कर लें।

मेरी तरह जो लोग महानगरों में रहते हैं, उनमें से सभी की जड़ें अब भी गांव में हैं। दो-तीन पीढ़ियों पहले तक तो हम सभी किसान परिवारों का ही हिस्सा थे। हम महानगरों में रहते हैं, मगर वे ये किसान ही हैं, जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। हम कैसे उनकी ओर आंख मूंद सकते हैं? क्या उन्हें यह बताने की जरूरत है कि किसान बारिश के न होने की वजह से आत्महत्या नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं होता। अंबानी, अडानी जैसे लोग अगर अपने पैसों के दरिया में उंगली डुबो छींटे भी छिड़क दें तो किसानों के वारे-न्यारे हो जाएं। उन्होंने अब तक तो कुछ नहीं किया, पर नाना पाटेकर जैसे लोग हैं, जो अपनी अंटी से पैसा देकर किसानों के परिवारों को राहत दे रहे हैं।

साभार
सुंदरचंद ठाकुर

पावर ही तय करती है पावर के रेट

दिल्ली बहुत खुश है। खुश होने का कारण भी है। इस बार बिजली के बढ़े रेट का करंट दिल्ली को नहीं लगा। यूं तो फ्यूल चार्ज के नाम से पिछले महीने ही बिजली के रेट 6 फीसदी बढ़ गए थे लेकिन अब डीईआरसी (दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन) ने वार्षिक फैसले में रेट और न बढ़ाने का साफ-साफ फरमान सुना दिया। यह भी कम उल्लेखनीय नहीं है कि डीईआरसी के अनुसार प्राइवेट बिजली कंपनियां पहली बार फायदे की स्थिति में आ गई हैं। इन कंपनियों के पास 2015-16 में 445 करोड़ रुपए सरप्लस होंगे। दिल्ली में बिजली का प्राइवटाइजेशन 2002 में हुआ था। तब से अब तक इन कंपनियों को हमेशा घाटे में दिखाया गया है। अब यह घाटा 14 हजार करोड़ तक जा पहुंचा है। इस बार भी कंपनियां 20 फीसदी की बढ़ोतरी मांग रही थीं, लेकिन डीईआरसी ने जो फैसला सुनाया वह दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी ही है।

इस फैसले से एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि डीईआरसी के फैसले सरकार के तेवरों पर ही निर्भर करते हैं। भले ही यह कहा जाता हो कि डीईआरसी स्वायत्त संस्था है, लेकिन सचाई यही है कि इसके फैसले सरकार के मिजाज से प्रभावित होते हैं। इस बार सरकारी तौर पर ये चेतावनियां पहले ही दे दी गई थीं कि दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। आप एमएलए रेट्स के लिए सुनवाई के दौरान यही कहते नजर आए थे कि रेट बढ़ने की बजाय कम होने चाहिए। यूं भी माहौल इस तरह का बना दिया गया था कि बिजली के रेट पहले ही ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। पिछले दिनों लीक की गई सीएजी रिपोर्ट के बारे में भी बताते हैं कि बिजली कंपनियों के खातों में काफी हेरफेर किया गया है। ऐसे में बिजली के रेट बढ़ने का कोई तर्क दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि बिजली कंपनियां भले ही यह दावा करती रहें कि उनका रेवेन्यू गैप बहुत बढ़ गया है, लेकिन रेट न बढ़ाने के डीईआरसी के फैसले के बाद वे भी खामोश हैं। सरकार से वे भी कोई पंगा नहीं लेना चाहतीं।

यह फिर साबित होता है कि सरकारें ही डीईआरसी के कामकाज को प्रभावित करती हैं। अगर अब तक बिजली के ज्यादा रेट वसूले गए तो उसके लिए सरकारें ही जिम्मेदार हैं। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं तो डीईआरसी के तत्कालीन चेयरमैन ने इसी तरह का निष्कर्ष निकाला था कि प्राइवेट कंपनियों के खातों में 3500 करोड़ रुपए सरप्लस हैं। तब उन्होंने रेट कम करने का मन भी बना लिया था लेकिन जब सरकार ने कहा कि ऐसा आदेश जारी नहीं करना है तो वह भी सरकार के निर्देश को मानने के लिए बाध्य हो गए, जबकि उन्हें भी मालूम था कि डीईआरसी स्वायत्त संस्था है। उन्होंने भी वही किया जो सरकार चाहती थी। दरअसल डीईआरसी के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति सरकार ही करती है। यही वजह है कि स्वायत्त होने के बावजूद वे सरकार के कृपालु बने रहना चाहते हैं।

दिल्ली की आप सरकार का अपना अजेंडा है कि जनता को सस्ती दरों पर बिजली मिले। सस्ती बिजली और मुफ्त पानी के नारे के साथ ही तो वह सत्ता में आई। 49 दिन के अपने पहले कार्यकाल में ही आप सरकार ने जनता को दिखा दिया था कि वह अपना वादा पूरा कर रही है। यही वजह है कि 2015 के चुनावों में जनता ने बिजली-पानी सस्ता करने के कांग्रेस-बीजेपी के नारे पर विश्वास नहीं किया। कांग्रेस को वह देख ही चुकी थी और बीजेपी ने भी राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान जनता को ऐसी राहत नहीं दी जबकि आप अपना वादा डिलिवर कर चुकी थी। अगर अब बिजली के रेट बढ़ते तो जनता में यह संदेश जाता कि सरकार वादे से मुकर रही है और उसने ऐसा नहीं होने दिया। केवल इस साल ही नहीं बल्कि उसने अगले चार सालों के लिए भी डीईआरसी से रेट न बढ़ाने का वादा करा दिया। यह वादा आप सरकार के चुनावी वादों में से एक है। ऐसे में भले ही डीईआरसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हों लेकिन जनता खुश है कि बिजली के रेट नहीं बढ़े।

साभार
दिलबर गोठी

दिलचस्प हो गए हैं बिहार चुनाव

मेरा मानना है कि किसी भी लेखक या पत्रकार को एक क्रिकेट कॉमेंटेटर की तरह होना चाहिए। जैसा खेल हो रहा है, खेल का वैसा ही हाल बताना चाहिए, सुनाना चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह संजय ने धर्मक्षेत्र-कुरूक्षेत्र का हाल सुनाया था। इसके लिए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी मगर हमारे लेखकों और पत्रकारों के पास वह दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि से मेरा मतलब है कि आग्रह-दुराग्रह और पूर्वाग्रहों से विमुक्त होकर घटना-क्रमों को देखना। सच्चाई को देखना। इस बार मेरी कोशिश होगी कि आपको बिहार की राजनीति का आंखों देखा हाल उसी नजरिए से बताऊं।

बिहार में लालू राज को जंगल राज के रूप में देखा जाता है और प्रचारित किया जाता है। लालू को दु:ख होता है। इसलिए उन्हें ऊंची जातिवाले ललुआ कहते हैं। ऊंची जातिवालों को भी बिहार में बहुत दिनों के बाद अहसास हुआ कि जब तक वे लालू को ललुआ कहते रहेंगे, लालू गद्दी पर जमे रहेंगे और सिंहासन पर बैठकर ललुआ सत्ता के घी का हलुआ खाता रहेगा। सो, लालू को सत्ता से बेदखल करना है, तो सबसे पहले उसे ललुआ कहना बंद करो। लालू को ललुआ कहना बंद हुआ और लालू की सत्ता का दरवाजा भी बंद हो गया।

बिहार में ओबीसी और दलितों को ऊंची जातिवाले मंडलवाले के रूप में और मंडलवाले ऊंची जातियों को कमंडलवाले के रूप में देखते हैं। कमंडल की राजनीति आडवाणी की रथयात्रा से आरंभ हुई थी, अयोध्या में राममंदिर बनाने के मकसद से और बी. पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके मंडल की राजनीति की शुरुआत नब्बे के दशक में की थी। लालू के बहुप्रचारित जंगलराज को मंडल राज के रूप में इसलिए देखते हैं जबकि कमंडलवाले मंडल राज को जंगलराज के रूप में देखते हैं क्योंकि लालू यादव के सत्ता में आने के बाद यादवों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। मनोबल बढ़ने से मनमानी बढ़ती है। अत्याचार और आतंक बढ़ता है।

मेरे एक समाजवादी मित्र हैं - लखनलाल पाठक। उनके पिताजी भी बड़े समाजवादी नेता थे - राधेश्याम पाठक। राममनोहर लोहिया के करीबी थी। उनके विचारों का बड़ा प्रभाव उन पर था। उनका मानना है कि लालू ने सवर्णों की दबंगई का डर दिखाकर पिछड़ों को एक किया। उनका आकलन सही है। लालू से पहले बिहार में कोई मंगल राज तो था नहीं। आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और ब्राह्मण, हरिजन और मुस्लिम के सामाजिक जातीय समीकरण से चुनाव जीतती रही। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू बने, तो भूमिहारों का मनोबल बढ़ा, मनमानी बढ़ी, दबंगई बढ़ी। हालांकि इसे जंगल राज के रूप में किसी ने नहीं देखा, ऐसा मंडल राजवालों का मानना है। श्री बाबू के बाद विनोदानंद झा, जगन्नाथ मिश्र और भागवत झा आजाद, केदार पांडेय और बिन्देष्वरी दूबे बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो मिथिला होटेल के रसोइये का भी मनोबल सातवें आसमान पर नजर आता था। जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और फिर राजनीति का अपराधीकरण आरंभ हुआ, तब किसी ने नहीं कहा जंगल राज। न कहीं लिखा गया जंगल राज क्योंकि उस वक्त आर्यावर्त और इंडियन नेशन जैसे अखबारों का बोलबाला था।

मंडल राज की खूबी को उजागर करते हुए खुद लालू ने आजतक पंचायत कार्यक्रम में बताया कि यह मंडल राज का ही चमत्कार है कि सुपर थर्टी के सुपर हीरो आनंद कुमार ओबीसी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का परचम संपूर्ण देश में लहरा रहे हैं। मंडल राज ने पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बेशक लालू के इस योगदान की प्रशंसा कमंडलवाले करें न करें, मंडलवाले करते हैं। मगर बिहार न डॉ. जगन्नाथ मिश्र के कार्यकाल में सवर्णों व मुस्लिमों की दबंगई और मनमानी को भूला है और न लालू के जमाने के यादवों व मुस्लिमों की दबंगई को, मनमानेपन को। भय और आतंक का राज तब भी था और उसके बाद भी। सत्ता में जो जाति आती है, उसके दबंगों का आतंक और मनोबल बढ़ता है।

बिहार में बदहाली है। यह सच है और यह भी सच है कि लालू फ़ॉमिनन की वजह से ही नीतीश, रामविलास , जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव आदि ओबीसी और दलित नेताओं का उदय बिहार की राजनीति में हुआ। भाजपा हो या कांग्रेस अब बिना मंडल के सहारे कमंडल की भी राजनीति नहीं चल सकती। ये दोनों राष्ट्रीय दलों को पता चल चुका है। बिहार में मंडल राजनीति का महत्व डॉ. राममनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा की वजह से बढ़ा है। मगर जिस प्रकार से डॉ. लोहिया और कर्पूरी जी ने सामाजिक न्याय की राजनीति को देश में आगे बढ़ाने का विचार किया था, वह परिवारवाद के कारण पटरी से उतर चुकी है। इसी का लाभ उठाने के फेरे में कमंडलवाले हैं लेकिन कमंडल खुद परिवारवाद के भंवर में घूम रहा है। अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके भाजपा सांसद अश्वनी चैबे और सीपी ठाकुर के बेटों को टिकट दिया है। जिस नीतीश राज में बिहार के अस्पतालों का कायाकल्प भाजपा से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चंद्रमोहन राय ने किया था, उसी का टिकट काटकर भाजपा ने संदेश दिया है कि जो काम करे, उसका टिकट कटे। वह एक कुलीन भूमिहार परिवार से आते हैं। इसी का नाम राजनीति है। राजनीति में तिकड़मी ऊपर उठते हैं और काम करने वाले काबिल लोग पीछे छूट जाते हैं। बिहार भाजपा के भीष्म पितामह माने जाने वाले कैलाशपति मिश्र की पुतहू और वर्तमान विधायक का टिकट काटकर भाजपा ने यही संदेश दिया है कि जो चला गया, उसे भूल जा। कहते हैं कि अगर कैलाशपति मिश्र न होते, बिहार में संघ भाजपा की ध्वजा नहीं लहराती। इस प्रकार की भी चर्चा यहां की फिजाओं में है। बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने टिकट बंटवारे में अगर उम्मीदवारों की योग्यता, क्षमता और छवि को ध्यान में रखा होता, तो जनता को वोट डालने में आसानी होती। वरना, नोटा का बटन दबाना मतदाताओं की मजबूरी होगी।

हालांकि दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक में सेंधमारी की नीयत से भाजपा रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मदद ले रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव दिलचस्प हो गया है और विकास की लुटिया, हिंदू-मुसलमान, बैकवर्ड-फॉरवर्ड, दलित आदि जाति और संप्रदाय के सागर में ऊपर-नीचे हो रही है।

साभार
डॉ. सामबे

पाठकनामा

'गणादेश' साप्ताहिक समाचार पत्र अपनी समग्र प्रस्तुति में अच्छा लगा। व्रज कुमार पाण्डेय तथा अरविन्द ठाकुर के आलेख अच्छे लगे। सम्पादकीय तथा साहित्य की अनुस्थिति थोड़ी खाली संभव हो तो आगे के अंको में इसका ध्यान रखा जाय।

सुरेन्द्र भारती, त्रिवेणीगंज, सुपौल

साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में गणादेश का स्वागत है। खेती-बारी से जुड़ी सामग्री स्तरीय है। उसके व्यावसायिक पक्ष पर भी जानकारी मिलनी चाहिए। चुनावी खबरों की प्रस्तुति बेहत्तर है। विहार के और भी जिलों से खबरें आएँ तो ठीक।

बेचन राय, बदुपर, कैमूर

'गणादेश' आने वाले दिनों में अपनी पहचान बनाएगा, ऐस उम्मीदें जगी हैं। भ्रष्टाचार पर सामग्री प्रमाणिक और रोचक थी। चुनाव का कवरेज भी ठीक-ठाक रहा। खेल और कैरियर संबधित जानकारियाँ भी उपयोगी रही। कैरियर पेज पर विशेषओं से बात-चीत अधिक उपयोगी हो सकती है। राणा अवधूत कुमार की रिपोर्ट वेहत्तरीन रही।

कुमार अमित, पटना.

बहुत शानदार लगा गणादेश का नवीनतम अंका भरपूर सामग्री है। इसमें सप्ताहांत तक हम इसे पढ़ सकते हैं। संपादकीय होना चाहिए। बच्चों पर, बुजुर्गो पर सामग्री साप्ताहिक की उपादेयता को और बढ़ा देगा।

रामश्रेर प्रसार वर्मा, बक्सर

'गणादेश' साप्ताहिक में स्थानीय खबरों की कमी खलने वाली रही। आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ी कहानियाँ तथा अन्यान्य सामग्री होनी चाहिए। साहित्य का एक अलग सेभी पन्ना हो। कविताएँ कहनियाँ तथा पुस्तकों के बारे में जानना अच्छा रहेगा परिवारवाद पर ब्रज कुमार पाण्डेय की टिप्पणी अच्छी लगी। वैसे एक संतुलित अंक के लिए साधुवाद।

राहुल कुमार,चीनी मिल, बक्सर

'गणादेश' साप्ताहिक मन को भा गया। खवरें तो थी ही अन्यान्य प्रस्तुतियाँ जैसे खादी वस्त्र से जुड़ी जानकारी, बुनकरों के हालात से रू-ब-रू होता शानदार रहा। डीजल अनुदान की स्थिति और उस पर रिपोर्ट बढिया बन पड़ी है। ऐतिहासिक-पुरातात्विक कहत्व की खबरें भी आप लगातार प्रकाशित करें तो हम लोगों को और अच्छा लगेगा। जैसे शेरशाह के मकवरे वाली रिपोर्ट आई हैं.

सरिता कुमारी, मुसाफिरगंज, बक्सर

एक साप्ताहिक से जो अपेक्षाएं होती हैं, उन्हें 'गणादेश पूरा करता प्रतीत हुआ। इसके लिए साधुवाद समकालीन विचार और ज्वलंत मुददों पर कोई बहस लगातार चले तो बेहत्तर बुजुर्गो के लिए सामग्री देने की भी कोशिश करें। हो सके तो आधी आवादी के लिए भी कुछ जगह रखे गणादेश में।

विजेन्द्र, सासाराम

बधाई, गणादेश के लिए। अच्छे साप्ताहिक के लिए।

संतोष श्रेयांस, आरा

साप्ताहिक राशिफल

04 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2015

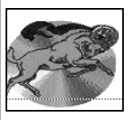

मेष : इस वीक आपका टैलंट सबसे सामने आएगा। इन्वेस्टमेंट फायदा देने वाला साबित नहीं होगा। किसी भी डिसिजन को लेने में जल्दबाजी ना बरतें। अपनी लिमिट्स का भी ध्यान रखें। रोमांस के लिए अच्छा माहौल है। सोशल इवेंट और ट्रिप पर लव पार्टनर से मिलने का चांस हो सकता है। हफ्ता खत्म होने के साथ ही रिलैक्स मूड रहेगा।

वृष : परिवार या प्रफेशनल लेवल पर चेंज होने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों की एडवाइज जरूर सुनें, हो सकता है कि ये आपके काम आ जाएं। ट्रिप थकाने वाले होंगे। घर का जो भी सामान खरीदेंगे, वह फायदे वाला साबित होगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे। इनसे कुछ परेशानी हो सकती है।

मिथुन : इस हफ्ते पूरा फोकस अपनी डील को पूरा करने पर लगाएं। एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपने पैर ना फंसाए। आप अपने लिविंग एरिया की पोजिशन चेंज करें, आपको फायदा होगा। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें और हो सके, तो शांति से काम करें।

कर्क : इस वीक आप कुछ नए बदलाव देखेंगे। नए रिलेशनशिप बनेंगे और वह लंबे समय तक चलेंगे। घर में किए गए इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त केयरफुल रहें। अपना बिजनेस और पार्टनर से रिलेशनशिप सुधारते वक्त थोड़ा सतर्क रहें।

सिंह : अलर्ट रहें, कोई आपको गलत सजेशन दे सकता है। किसी नए दोस्त से सेमिनार में मुलाकात होगी और आपको बिजनेस से जुड़ी नई संभावनाएं भी मिलेंगी। ओपन माइंडेड रहें। किसी से भी अपने पर्सनल सीक्रेट्स शेयर ना करें। कुछ टाइम किताबें पढने में बिताएं।

कन्या : अगर आप दोस्तों या रिलेटिव की बातें नहीं सुनते हैं, तो उनसे बेकार में बहस ना करें। नए लोगों से मिलें। इससे आपको नई-नई जानकारियां मिलेंगी। कोई आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है। हो सके, तो किसी को यह स्कोप ना दें।

तुला : इस हफ्ते आपको अपने अंदर से अच्छे सुझाव मिलेंगे, जो बिगड़ी बातें बना देंगे। आपके पास क्रिएटिव विचार आएंगे। अपना काम दिखाएंगे, तो आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। एक-तरफा आकर्षण से आपको तकलीफ होगी और आपकी इच्छाएं आपको तन्हा भी कर सकती हैं।

वृश्चिक : इस हफ्ते आप दूसरों से पॉजिटिव माइंडसेट से मिलेंगे। यह टाइम डील्स और शॉपिंग के लिए परफेक्ट है। यानी आपको बिजनेस में फायदा होगा या फिर आप कहीं अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। उन लोगों के सामने अपनी सफलता का बखान ना करें।

धनु : आप अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, इसलिए यह जानें कि आपकी खुशी किस में है और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अपने लिए स्टैंड लेने और दिल की सुनने का यह परफेक्ट टाइम है। किसी और के दबाव में ना आएं। अगर कोई आपसे नाराज है, तो उससे मामला सुलझाने की कोशिश करें।

मकर : इस हफ्ते सफलता चाहते हैं, तो पार्टनरशिप में काम करें। उन लोगों से ना जलें, जो इन दिनों आराम कर रहे हैं या छुट्टी पर हैं, क्योंकि आपके ऐसे दिन भी जल्दी ही आएंगे। इसलिए शांत रहें। किसी से बढ़-चढ़कर प्रॉमिस ना करें।

कुंभ : आपका मकसद बिगड़ी हुई चीजों को ट्रैक पर लाने का रहेगा और सारी प्लानिंग आप इसी बात को ध्यान में रखकर ही करेंगे। सबसे ज्यादा जोर दूसरों से कम्यूनिकेशन बढ़ाने पर रहेगा। गलतियां करने से बचें और दूसरों में भी खामियां ना निकालें।

मीन : आपका मकसद बिगड़ी हुई चीजों को ट्रैक पर लाने का रहेगा और सारी प्लानिंग आप इसी बात को ध्यान में रखकर ही करेंगे। सबसे ज्यादा जोर दूसरों से कम्यूनिकेशन बढ़ाने पर रहेगा। गलतियां करने से बचें और दूसरों में भी खामियां ना निकालें।

कविता

आएंगे उजले दिन ज़रूर आएंगे

वीरेन डंगवाल

आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ़
है हवा कठिन, हड्डी-हड्डी को ठिठुराती
आकाश उगलता अन्धकार फिर एक बार
संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती

होगा वह समर, अभी होगा कुछ और बार
तब कहीं मेघ ये छिन्न -भिन्न हो पाएँगे

तहख़ानों से निकले मोटे-मोटे चूहे
जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे
हैं कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें
चीं-चीं, चिक-चिक की धूम मचाते घूम रहे

पर डरो नहीं, चूहे आख़िर चूहे ही हैं
जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएँगे

यह रक्तपात यह मारकाट जो मची हुई
लोगों के दिल भरमा देने का ज़रिया है
जो अड़ा हुआ है हमें डराता रस्ते पर
लपटें लेता घनघोर आग का दरिया है

सूखे चेहरे बच्चों के उनकी तरल हँसी
हम याद रखेंगे, पार उसे कर जाएँगे

मैं नहीं तसल्ली झूठ-मूठ की देता हूँ
हर सपने के पीछे सच्चाई होती है
हर दौर कभी तो ख़त्म हुआ ही करता है
हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है
आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस
इसके आगे भी चलते ही जाएँगे
आएँगे उजले दिन ज़रूर आएँगे

स्मृति शेष

अंधेरों की शिकस्त का दावा करने वाला कवि वीरेन डंगवाल

आत्मग्रस्त छिछलापन ही जैसे रह आया जीवन में शेष/ प्यारे मंगलेश, रात चूं-चर्र-मर्र जाती/ ऐसी गाड़ी में भला नींद कही आती हैं? मंगलेश जैसे न जाने कितने संगी-साथी संस्कृतिकर्मियों और ही जैसे साहित्य प्रेमियों को वीरेन डंगवाल सवालों के कटघरे में छोड़कर एक गहरी चुप्पी साध ली। लेकिन हम सभी से हूटकर भी स्मृतियों के बीच वे घड़कनों में महफूज रहेंगे और हम उनकी पदचाप महसूस करेंगे। वीरेन लिखते हैं-''हर दौर कभी तो खत्म हुआ करता है। हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती।.. आयेगे, उजले दिन जरूर आयेंगे। उजले दिन की प्रतीक्षा बेहतर मनुष्य और बेहतर दुनिया का स्वप्न है। इसमें सिर्फ सत्रा परिवर्तन की गूँज नहीं है बल्कि आम-आदमी की जीवन-शक्ति निहित है। पाब्लो नेरूदा ने कहा था ''कविता आदमी के भीतर से निकली पुकार है।'' वह मनुष्यता की मातृ भाषा है। ठीक इसी संदर्भ में वीरेन डंगवाल मनुष्यता के कवि हैं। मनुष्य की अदभ्य जिजी विषा के कवि हैं। इसलिए जनता के कवि भी हैं। अपने समय और समाज के प्रति गहरी सजगता, तीव्र संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकारों की त्यापकता उनकी कात्यानुभूति की संस्कृति का स्वरूप निर्मित करती है। वीरेन ने अपने पुरखों से बहुत कुछ सीरवा ही नहीं बल्कि आत्मसात किया है और बिल्कुल की नएअंदाज में त्यक्त किया। अस्सी के दशक पीढ़ी में विशिष्ट हैं। इसलिए कि वीरेन ने समकालीन कविता के प्रचलित मुहावरे को उलट-पुलट कर रख दिया है।

वीरेन ने छंद से गद्य तक जो विन्यास रचा है वह उनकी एक अलग विरल पहचान है। साहित्य अकादे भी में दिए गए वक्तव्य में उन्होंने कहा है जरूर छंद कविता को स्मृति ग्राहय बनाता है। लेकिन छंद कविकर्म को आसान और कविता को सरलीकरण भी बना सकता है। कविता अगर हमारे समय में पाठकों का रोना रो रही है तो उसकी एक बड़ी वजह भी बाजार और उपयोग का सारथी भी वहीं वैश्विक मनुष्य है। कविता प्रतिरोध का सांस्कृतिक औजार है, यह प्रतिरोध की चेतना नैतिक साहस से पनपती है। तभी तो वीरने को लगता है ''पर हमने यह कैसा समाज रच डाला है/ इसमें जो दमक रहा, शार्तिया काला है/ वह कव्ल हो रहा, सरे आम सडकों पर। निर्दोष और सज्जन जो भोला-भाला है। किसने ऐसा समाज रच डाला है/ जिसमें बस वही दमकता है, जो काला है? समय और समाज के साथ गहरे तादात्मय के चलते समय और समाज के

साथ कवि संवाद करते है और कविताओं के जरिए पाठकों को सवाल पूछने की प्रेरणा देते हैं।

वीरेन समाज की विसंगतियों पर सिर्फ प्रहार ही नही करते बल्कि भविष्य की सम्भावनाओं की तलाश करते है और तभी यह कहने का साहस रखते हैं- याने साधन तो सभी जुटा लिए हैं, अत्याचारियों ने/ मगर जीवन हठीला फिर भी..... कवि को उम्मीद हैं कि लोग हमेशा चुप नहीं रहेंगे। बोलेंगे और इनकार करेंगे ''और लोग भी हैं कई लोग हैं/ अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार।

वीरेन डंगवाल के पास अपनी भाषा हैं, नितांत मौलिक और-औरों से अलग। कविता ही नहीं मनुष्यता के स्तर पर वीरेन बड़े हैं। अंधरों की शिकस्त का दावा करने वाला कवि अंधेरी खोह खो जरूर गया है लेकिन वह हमें अवाज देता हैं।

रात है रात बहुत रात बड़ी दूर तलक/ सुबह होने में अभी देर हैं माना काफी/ पर न ये नींद रेहे नीदं फ़कत नींद नहीं/ ये बने ख्वाब की तफ़सील अंधरों की शिकस्त।

उनकी विशिष्टताओं को परखने के लिए तीनों संग्रहों से होकर गुजरना होगा।

इस दुनिया में (1991)
दुष्चक्र में स्रष्टा (2002)
स्याही ताल (2009)

संजीव अग्रवाल के दोहे

(1) तू महलों का बादशा मैं तो मस्त फकीर,
तेरे साथ कुबेर है, मेरे साथ कबीर।

(2) रूपये पैसे की भला, कब करती है आस
बूढ़ी अम्मा चाहती, बैठे कोई पास।

(3) हिन्दू-मुस्लिम मौन में, मुश्किल में इंसान,
चाहे हिन्दुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान।

(4) क्या हैरत मैं गिर पड़ा, औंधे मुंह श्रीमान्,
लेखक बनने था चला, बिना बने इंसान।

(5) इज्जत-शुहरत-हैसियत, रूतबा मान-मुकाम,
हम अपने अभिमान को, क्या-क्या देते नाम।

(6) रोग-शोक हथियार की, मुझको क्या दरकार,
अहंकार मेरा मुझे, खुद ही देगा मार।

(7) जिस दिन निकली भूख से, इक बच्चे की जान,
उस दिन संदेह के, घेरे में भगवान।

(8) कैसे दिल की दूरियां, होंगी आखिर दूर,
वो भी मद में चूर हैं, हम भी मद में चूर।

(9) तोड़े हैं रिश्ते सदा, तोड़ा है विशवास,
जब भी चाहे देख ले, दौलत का इतिहास।

(10) जब भी निकाला होंठ से, मन का हाहाकार,
तब-तब लोगों ने कहा, दोहा है दमदार।

बक्सर 9931228025

कहानी

सफर

नरेन

यह दिसंबर से पहले सप्ताह की एक सर्द शाम थी। राजगीर-दानापुर पैसेंजर राजगीर से खुलकर खण्डहर उजाड़ हो गए सिलाव स्टेशन पर ठहरी ही थी कि सीने तक सफेद दाढ़ी लहराते हुए वह बुजुर्ग हांफते-हांफते लपककर डब्बे में सवार हुए। डब्बे के दरवाजे पर ही अपनी सांस पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए उन्होंने डब्बे के भीतर थकी हुई-सी निगाह डाली। खूब भीड़ नहीं थी, लेकिन कोई सीट खाली भी नहीं थी।समूचे डब्बे में निपट गांव-देहात के साधारण हैसियत वाले खेतिहर घरों के ढेर सारी प्रौढ़ाए और पोपले मुंहों वाली बूढ़ी औरतें बैठी हुई थी। और बेसूरे अंदाज में भजन जैसी कोई चीज गाये जा रही थीं-गुरूजी से नेहिया लगा लेहू हे सखियन मिली जुली सब..! कुछ औरतें अपनी आंख मीचे, जोर-जोर से तालियां पीटकर पूरी तन्यमता से गाती दिख रही थी। लेकिन एकदम बूढ़ी औरतें बच्चों के समान आंखें में तनिक विस्मय लिये खिड़की के बाहर के नजारे देखने में खोई हुई थी..। उनके पोपले मुंह खुले हुए थे..और किसी-किसी के मुंह के कोरों से लार रिस रही थी। कभी-कभार उनके अधखुले मुंह से सामूहिक रूप से गाये जा रहे भजन के आधे-अधूरे सब्र हौले से फिसल पड़ते। वे जिस कदर परिवेश को डूबकर अनक-परक रही थीं उसे देखकर यह नहीं लग रहा था कि वे गुरू-स्तुति में मन लगा रही है। वे बस बरबस सामूहिक रूप से गाये जा रहे भजननुमा गुरू-स्तुति के एकाध शब्द अलबलाते हुए दुहरा देने की कोशिश भर कर रही थीं।

डब्बे के दरवाजे पर खड़े सीने तक लहराती सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जरा सहमे हुए से और सशंकित दीख रहे थे। वे काफी मजबूत कद-काठी के थे और साफ लग रहा था कि वे नालंदा जिले के कोई मेहनतकश किसान थे। आभा बिखेरती गहरी तांबई रंगत। शिर पर क्रोशिए से बुनी हुई सफेद जालीदार टोपी उनकी खोपड़ी पर चिपकी हुई। आंखों में तनिक सजग सोच का भाव लिये, अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए एक बार उन्होंने सरसरी निगाह से समूचे डब्बे को देखा। बेसुरे लहजे में गाये जा रेहे भजन की गहमागहमी के बीच उनकी निगाह एक जगह टिक गई। थोड़ी-सी जगह थी वहां, जहां सीट के किनारे-कुछ परेशान सी एक कम उम्र मां अनमनी सी बैठी हुई थी। सामान्य से ज्यादा दुबली-पतली उस युवती मां को देखने से साफ लग रहा था कि वह भरपेट अनाज न मिलने की मारी हुई है। धंसे गालों वाला उसका लंबोतरा चेहरा निश्प्रभ दिख रहा था। उसने अपनी गोद में लगभग एकाध साल की दुबली-पतली अपनी बेटी संभाल रखा था। बगल की सिंगल सीट पर उसका नौजवान मरद बैठा हुआ था दो आदमियों को अपनी सिंगल सीट पर जगह दिए हुए। वह बेहद दार्षनिक भाव से तेजी से खिड़की के बाहर पीछे छूटते जा रहे नजारे पर अपनी निगाह टिकाये हुये था। दोनों पति-पत्नी बेहद उदास और परेषान लग रहे थे। दोनों के पैरों में गोरी मिट्टी की धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उन दोनों के पैरों के बगल में घिसी हुई सी पुरानी हवाई-चप्पलें आड़ी-तिरछी छितरायी पड़ी थी।

उस औरत के बगल में से, जहां जरा सी जगह दिख रही थी, एक कुबड़ी बुढ़िया उठी और बगल के गलियारे में अपनी सहेली के पास बतियाने चली गई। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े बुजुर्ग मुस्लिम सज्जन तनिक झिझकते हुए लपके और खाली हुई जगह पर अपने आपको एकदम संभाल कर जा बैठे एवं भरसक यह प्रयास करते दिख रहे थे कि उनकी देह से किसी की देह न छुआए तो बढ़िया रहे। नवयुवती मां ने बुजुर्ग को जरा सशंकित निगाहों से देखा और अनमनी सी अपने आप में जरा और सिमट कर सीट के एक ओर चिपक कर बैठ गई।

रेल अपनी सफर पर चलती रही। जाड़े की षाम गहरा गई थी और बाहर का सर्द अंधेरा डब्बे में पूरी तरह घर कर गया था। डब्बे में एकाध जगह मरियल सी पीली रौशनी उलीचता बल्ब टिमटिमा रहा था। बुढ़ियाएं गुरूजी से नेह लगाने का भजन गा-गाकर थक गई थीं और उनमें से अधिकांष ऊंघने लगी थीं।

वह नौजवान मां भी ऊंघ रही थी अपने के समान ही। षायद वे दोनों पति-पत्नी काफी दूर देहात से पैदल चलकर आए थे और थक गए थे। मां की गोद से बच्ची सरक कर चलती ट्रेन में डगमगाती हुई खड़र रहने की कोशिश कर रही थी अपनी मां का घुटना थामे हुए।वह बार-बार लरजकर गिर जा रही थी। एक-दो बार उसकी थकी-मांदी ऊंघ रही मां ने उसे उठाया लेकिन तीसरी बार उसने खीजकर बेटी की पीठ पर एक हल्का धौल जमा दिया। बच्ची सहम गई और इधर-उधर मासूमियत भरी निगाहों से निहारती हुई अपने होंठ सिकोड़कर बिसुरने लगी। बगल में बैठे बुजुर्ग के मुंह से बरबस निकल गया- आह! नंय मारा उसको बेटी..' और जरा झिझकते हुए उसने बच्ची को मां की हाथों से लपक लिया। जरा असमंजस में पड़ी मां ने बेटी को उस बुजुर्ग के हाथों में चली जाने दिया।

वह अब भी अपनी बगल में बैठे, सीने तक सफेद दाढ़ी लहराते हुए बूढ़े को जरा षंका भरी निगाहों से देख रही थी। उजली दाढ़ी-मूछों के बीच से झोकती उस बूढ़े की आत्मविष्वास से भरी झक्क उजली मुस्कुराहट ने शायद उस थकी उदास मां को कहीं हौले से आश्वस्त किया। थकान और हावी होती हुईनींद की वजह से थोड़ी ही देर में वह नौजवान मां अनमनी सी ऊंघने लग गयी।

सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग और उसकी गोद में बैठी नन्हीं बच्ची को आपस में ताल-मेल बिठाने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। यह पता ही नहीं चला कि वह बच्ची और बुजुर्ग एक दूसरे के साथ कब सहज हो चले थे और आपस में खेलने लगे थे। धूल-धूसरित वह बच्ची बूझे की गोद में जा बैठी थी और उनकी लहराती दाढ़ी को मुट्ठियों में भींच कर खींच रही थी। बूढ़े सज्जन नेह और छोह से इतराये हुये, दुधिया मुस्कान बिखरते-बिखेरते कह उठते- आह... झुलुआ समझले है का हमरी दाढ़ी को..?

कुछ देर बाद बच्ची ने बुजुर्ग की गोद में पेशाब कर दिया। बुजुर्ग जरा चैंके जरूर मगर उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं उभरी। मां ने अपराध भाव से बूढ़े की आंखों में झांका और बच्ची को जरा डांटते हुए अपनी गोद में खींच लिया। उसने बच्ची की गीली चड्ढी को उतारकर बगल में पड़ी अपनी प्लास्टिक की डोलची में फेंक दिया। उसने बच्ची को दूसरी चड्ढी नहीं पहनायी।क्या पता उसके पास बच्ची की दूसरी चड्ढी थी भी या नहीं। थोड़ी ही देर में बच्ची फिर से सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की गोद में जाने के लिए मचलने लगी थी और आखिरकार वह जबरन बुजुर्ग की गोद में जाकर ही मानी। बुजुर्ग बच्ची को चुटकी बजा-बजाकर खेलाने में मशगुल हो गये। उनके गहरे तांबई चेहरे पर दूधिया चांदनी सी उजलीहंसी खिल रह थी।

ट्रेन अपना सफर तय करती रहीं। अब डब्बे में ऊंघते लोग जागने लगे थे। पटना नजदीक आनेवाला था और गाड़ी गुलजार बाग से खुल चुकी थी। बच्ची अब मां की गोद में बैठी थी और दोनों बाहें पसार-पसारकर बुजुर्ग के साथ खेल रह थी। बच्ची की मां भी अब पूरी तरह से जाग गई थी। अभी उसके चेहरे पर थकान और निराषा के भाव काफी हल्के हो गये दिख रहे थे। उसने बच्ची की नन्हीं मुट्ठियों को अपनी मुट्ठी में थाम रखा था और थोड़ी कुबड़ी होती हुई बच्ची के चेहरे से अपना चेहरा सटाकर हौले-हौले, आगे-पीछे झूम-झूमकर बुजुर्ग की ओर इषारा कर-कर के उसकी जुबान से बोलवाने का प्रयास कर रही थी-'बोल बुनिया..नान्ना!...बोन नान्ना!

बुजुर्ग का चेहरा ममता का उजास फेंकेता बेइंतहां खुशी से झलमल-झलमल कर रहा था। वह भी बच्ची की मुट्ठी को अपनी मेहनतकश बूढ़ी, खुरदुरी भारी-भरकम हथेली में समेटे उसे बोलने के लिए उत्साहित कर रहे थे। हां-हां!बोल बिटिया..बोला..नान्ना!..., बोल नान्ना! बच्ची खुषी से किलकती हुई कभी मां को देखती..और कभी बुजुर्ग को। उसके दो दुधिया दांत उग आये थे। उसी को चमकाती हुई वह किलकी..और चनकती हुई बोली-'नान्ना!'

नवयुवती मां और बुजुर्ग, दोनों निहाल हो गये। खुशी से निहाल होते इन दोनों प्राणियों को यह आभास नहीं था कि डब्बे में बैठी आस-पास की सारी औरतें इस घटना को गौर से परख रहे थे और उसके साथ-साथ वे लोग भी खुषी से निहाल हो गये थे।

गाड़ी पटना जंक्षन के ठीक पहले किसी अंधेरे से स्टेशन पर खड़ी होने के लिए धीमी हो रही थी। नवयुवती के मरद ने, जो अब तक वीतरागी मुद्रा में यह सब देख रहा था, खिड़की के बाहर अंधेरे में झांका। वह हड़बड़ा गया और अपने पैरों के पास रखे झोले को उठाते हुए, धूल-धूसरित हवाई-चप्पलों में अपने पैर फंसाकर अपनी घरवाली से कहा-'अरे रजिन्नर नगर टीसन आ गेलऊ, चल जल्दी उतर।'

नवयुवती मां अपनी बेटी के साथ तन्मय होकर खेल रही थी। पति की पुकार सुनकर वह फौरन चैंकी और एक हाथ में अपनी हवाई चप्पल और दूसरे हाथ में बिटिया को सम्हाले डब्बे के दरवाजे की ओर लपक पड़ी अपने मरद के पीछे-पीछे। बुजुर्ग भी जरा भौंचक रह गये। उनके चेहरे पर दुधिया उजास फेंकती मुस्कुराहट जमी की जमी रह गई। शायद वह तनिक निराश हो गये थे। शायद इसकी वजह यह रही होगी कि उस मां ने लपक कर जाते समय उनसे कुछ कहा नहीं था। कोई औपचारिक विदाई नहीं। कोई दुआ सलाम नहीं। ट्रेन रूकी। भीड़ के साथ वे दोनों औरत मरद भी अंधेरे प्लेटफार्म पर उतरे और परछाईयों में तब्दील हो गए; बुजुर्ग के चेहरे पर एकदम हल्की-सी स्याह परछाई तैर रही थी-ठिसुआएपन की। वह सामने की खिड़की से अनमने अंदाज में प्लेटफार्म के अंधेरे को घूर रहे थे। अचानक खिड़की के फ्रेम में नवयुवती मां का चेहरा आ जड़ा। उसकी गोद में उसकी धूल-धूसरित बेटी थी और वह उसे हुलकार रही थी बुजुर्ग की ओर इषारा करते हुए- 'बोल मुनिया! नान्ना..नान्ना! नाना को परनाम कर दे..! और उसने हड़बड़ी में ही बेटी की दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर उससे प्रणाम कराने की कोषिष की...'नाना के परनाम कर दें!' ट्रेन में बैठे बुजुर्ग के चेहरे पर मानो हजारों सूरज का नूर छा गया। उन्होंने भाव-विह्वल होकर अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाते हुए पलकें बंद कर के लगभग विचलित होते हुए कहा-अल्लाह!...अल्लाह!...खुदा तुझे सलामत रक्खे, मेरी बच्ची!..तुझे मेरी उमर लग जाये..।' खिड़की के बाहर गहरे अंधेरे प्लेटफार्म पर खड़ी मां के चेहरे पर भरपूर मुस्कान जगमगाने लगी। अपनी मां की कमर पर टिकी हुई नन्हीं बच्ची ने जोर से किलकते हुए हवा में अपनी दायीं हथेली उछालकर फिर कहा-नाना। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई राजधानी के केन्द्र में पहुंचने के लिए अपने आगे के सफर पर निकल चुकी थी।

उस बुजुर्ग को, उस ग्रामीण मां को, और उसकी बेटी को, भजन गा-गाकर थक कर ऊंघने लगी गंवई बूढ़ियों को-इनमें से किसी को भी यह मालूम नहीं था कि आज पूरे देश में वर्षो पहले अयोध्या शहर में किसी विवादास्पद ढांचे के गिरा दिये जाने की बरसी मनायी जा रही थी, जिसकी वजह से सर्वत्र एक अदिशय सा तनाव व्याप्त था।

पटना, 04 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com
गणादेश

बदलते परिवेश में अब संरक्षण खेती की जरूरत

आज किसानों को ऊर्जा संकट, विशेष आर्थिक क्षेत्रों कृषि मदों की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

खेती से तात्पर्य संसाधन संरक्षण की ऐसी तकनीक से है, जिसमें अच्छी फसल की पैदावार का स्तर बने रहने के साथ-साथ संसाधनों की गुणवत्ता भी बनी रहे ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी अपने से अच्छा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान परिवेश को देखते हुए संरक्षण खेती अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके प्रयोग से बहुत सारे फायदे पाए गए हैं जिनमें फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ-साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ी है जोकि कृषि के लगातार अच्छे हालात के लिए बहुत जरूरी है।

पिछले कई दशकों से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में संसाधनों का अत्यधिक, असंतुलित और अनुचित प्रयोग किया गया। परिणामस्वरूप आज स्थिति यह है कि हमारे संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परंपरागत खेती के कारण भूमि के उपजाऊपन एवं फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, मृदा में पोषक तत्वों की कमी, भूजल स्तर में निरंतर गिरावट, खेतों में खरपतवारों का बढ़ता प्रकोप, बिगड़ती मृदा समतलता, मृदा लवणीयता, खाद्य पदार्थों में विषैले कृषि रसायनों की उपस्थिति, बिगड़ता मृदा स्वास्थ्य, मौसम की विषमताएं तथा उत्पादकता में स्थिरता अथवा कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

साथ ही संसाधनों के असंतुलित प्रयोग से वायु, जल और मृदा प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा खेती में बढ़ती उत्पादन लागत और किसानों की घटती आय चिंता का विषय बनी हुई है। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगकीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिनों-दिन घटता जा रहा है। भविष्य में देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जा रहा है। यदि समय रहते हमने प्राकृतिक संसाधनों को प्रमुख रूप से मृदा एवं जल संरक्षण पर विशेष जोर नहीं दिया तो भविष्य में गम्भीर खाद्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है (शुक्ला एवं द्विवेदी, 2009)। इस सम्बन्ध में मृदा उपजाऊपन एवं उत्पादकता बढ़ाने में संरक्षण खेती की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

संरक्षण खेती से तात्पर्य संसाधन संरक्षण की ऐसी तकनीक से है, जिसमें अच्छी फसल की पैदावार का स्तर बने रहने के साथ-साथ संसाधनों की गुणवत्ता भी बनी रहे ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी अपने से अच्छा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। भविष्य में खाद्यान्न आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, पौष्टिकता, उत्पादकता और संसाधन उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सीमित भूमि में मृदा उर्वरता और जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। जिससे जलवायु परिवर्तन, भुखमरी और कुपोषण जैसी गम्भीर समस्याओं से मुक्ति मिल सके।

परंपरागत फसल उत्पादन के अंतर्गत समस्याएं

1. संसाधनों की मात्रा व गुणवत्ता में गिरावट
2. पैदावार एवं गुणवत्ता में गिरावट
3. बिगड़ता मृदा स्वास्थ्य
4. मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी
5. भूजल स्तर में निरंतर गिरावट
6. खेतों में खरपतवारों का बढ़ता प्रकोप
7. किसोनों की घटती आय
8. बिगड़ती मृदा समतलता
9. मृदा लवणीयता
11. खाद्य पदार्थों में विषैले कृषि रसायनों की उपस्थिति।

समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारक

1. रासायनिक उर्वरकों का अनुचित व असंतुलित प्रयोग
2. दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली
3. मृदा का अनुचित व अत्यधिक दोहन
4. खेती में कृषि रसायनों का बढ़ता प्रयोग
5. बिगड़ती मृदा समतलता
6. सतह व भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन
7. जैविक खादों का कम प्रयोग
8. दलहनी फसलों की खेती को नजरअंदाज करना।

लाभदायक है शून्य जुताई की खेती

खाद्यान्न फसलों में धान और गेहूं का महत्वपूर्ण स्थान है। धान-गेहूं फसल प्रणाली भारत में बहुत प्रचलित है। यह फसल प्रणाली देश की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में लगभग 12.3 मिलियन हेक्टेयर क्षत्रे धान-गेहूं फसल चक्र के अंतर्गत आता है। यह फसल प्रणाली उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तरांचल में बहुतायत में अपनायी जाती है। इन प्रदेशों में कुल कृषि क्षेत्रों का अधिकांश भाग इस फसल चक्र के अंतर्गत आता है। आज किसानों को ऊर्जा संकट, विशेष आर्थिक क्षेत्रों कृषि मदों की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ये समस्याएं स्वत: ही विभिन्न समस्याओं को जन्म देती हैं। पिछले चार दशकों में खेती में बहुत-सी समस्याएं आई हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए भारत अब दूसरी हरितक्रान्ति की आरे अग्रसर है। जीरो टिलजे तकनीक का गेहूं की खेती में लागत कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक खेती में संरक्षित टिलेज पर जोर दिया जा रहा है। इस तकनीक द्वारा खेतों की बिना जुताई किए एक विशेष प्रकार की सीडड्रिल द्वारा फसलों की बुवाई की जाती है। जहां बीज की बुवाई करनी हो, उसी जगह से मिट्टी को न्यूनतम खोदा जाता है। इसमें दो लाइनों के बीच की जगह बिना जुती ही रहती है। बुवाई के समय ही आवश्यक उर्वरकों की मात्रा बीज के नीचे डाल दी जाती है। इस तरह की बुवाई मुख्यत: रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसो और अलसी में ज्यादा कामयाब सिद्ध हुई है।

संरक्षण खेती से तात्पर्य

संरक्षण खेती से तात्पर्य संसाधन संरक्षण की ऐसी तकनीक से है जिसमें अच्छी फसल की पैदावार का स्तर बने रहने के साथ-साथ संसाधनों की गुणवत्ता भी बनी रहे ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी अपने से अच्छा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

इन फसलों की बुवाई देरी की अवस्था में 7-10 दिन पहले यानी समयानुसार की जा सकती है। अत: इस तकनीक द्वारा बुवाई करने पर देरी से बोयी गई फसलों में होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। आईएआरआई के अनुसंधान फार्म पर किए गए प्रयोगों में बिना जुताई से बोयी गई फसलों की पैदावार 5-10 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। साथ ही बिना जुताई द्वारा बुआई करने में लागत कम आती है क्योंकि आम किसान बुवाई के पूर्व खेत की 3-4 बार जुताई करते हैं जिसके कारण होने वाला खर्चा बच जाता है। साथ ही ट्रैक्टर के रखरखाव पर भी कम लागत आती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि रबी फसलों की बुवाई में 2500-3000 रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्चा बचाया जा सकता है।

इस तकनीक से बुवाई करने पर पानी की मात्रा भी कम लगती है क्योंकि एक तो पलेवा यानी बुवाई-पूर्व सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा बाद में भी 1-2 सें.मी. प्रति सिंचाई पानी कम लगता है। यह भी अवलोकन किया गया है कि बिना जुताई वाले खेतों में खरपतवारों का कम प्रकोप होते हैं। इसका कारण यह है कि इस तकनीक में मिट्टी की ज्यादा उलट-पुलट नहीं करते हैं।

मेड़ों पर खेती

इस तकनीक में फसलों की बुआई मेड़ों पर करने के लिए एक यंत्र तैयार किया गया है। इस तकनीक में 70-75 से.मी. की दूरी पर मेड़ों बनाई जाती है जिसमें लगभग 35 सें मी. चौड़ी मेड़ और इतनी ही दूरी व गहराई पर नाली-सी बन जाती है। बुवाई मेड़ों पर और नाली में भी फसल के अनुसार की जा सकती है। गेहूं के लिए मेड़ों पर 3 लाइनें बो सकते हैं जबकि सोयाबीन, सरसों, चना, मूंग की दो लाइन काफी होती है। यह तकनीक खेतों की भली-भांति जुताई करने के बाद या फिर पिछली फसल के लिए बनाई मेड़ों पर बिना जुताई के भी अपनाई जा सकती है।

लेजर विधि द्वारा मिट्टी का समतलीकरण

संसाधन संरक्षण संबंधी तकनीकी जैसे कि बिना जुताई की खेती या मेड़ो पर बुआई के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि खेत पूरी तरह से समतल होना चाहिए। अन्यथा बुआई ठीक से नहीं हो पाती है। बीज मिट्टी में सही गहराई पर नहीं पहुंचने से बीजों का अंकुरण एक समान रूप से नहीं हो पाता है। खाद व पानी भी सभी पौधों को समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वास्तव में किसी संसाधन संरक्षण संबंधी तकनीक की सफलता खेत के समतल होने पर निर्भर करती है। लेजर विधि एक नई वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें एक विशेष उपकरण द्वारा खेत की मिट्टी को पूरी तरह समतल किया जाता है। समतल भूमि पर फसल उगाने का सबसे बड़ा फायदा पानी की बचत व अधिक फसल उत्पादकता का है। सिंचाई का पानी खेत के हर हिस्से में एक समान मात्रा में और सारे खेत में कम समय में फैल जाता है। धान की फसल के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी है जिसमें सिंचाई जल की मात्रा लगभग आधी हो जाती है।

कम पानी से धान उगाने की विधि

जल एक सीमित संसाधन है। देश में कृषि हेतु उपलब्ध कुल जल का लगभग 50 प्रतिशत भाग धान उगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। धान उत्पादन की इस विधि में धान के बीज को खेत तैयार कर सीधे ही खेत में बो दिया जाता है। इससे पानी की असीम बचत होती है। चूंकि इस विधि के अंतर्गत खेतों में पानी नहीं भरते हैं इसलिए धान के खेतों में वायुवीय वातावरण बना रहता है। परिणामस्वरूप विनाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन के ह्रास को रोका जा सकता है। साथ ही इस विधि में धान के खेतों से ग्रीन हाऊस गैसों का निर्माण नग्न के बराबर होता है।

एसआरआई तकनीक का प्रयोग

धान की खेती में सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसीफिकेशन (एसआरआई) तकनीक को अपनाने से प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन के साथ मृदा, समय, श्रम और अन्य साधनों का अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग होना पाया गया है। इस विधि में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी को केवल नम रखा जाता है। खेत में पानी खड़ा हुआ नहीं रखते हैं। जल निकास की उचित व्यवस्था की जाती है जिससे पौधों की वृद्धि और विकास के समय मृदा नम बनी रहे। इस प्रकार धान के खेतों में मृदा वायुवीय दशाओं में रहती है, और मृदा में डीनाइट्रीफिकेशन की क्रिया द्वारा दिए गए नाइट्रोजन उर्वरकों का कम से कम ह्रास होता है। साथ ही धान के खेतों से नाइट्रस आक्साइड का उत्सर्जन भी नगण्य होते है। एसआरआई विधि से धान की खेती करने पर लगभग 30-50 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत भी होती है। इस विधि का महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण सुधार है। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग और अन्य आदानों जैसे उर्वरक व कीटनाशकों का कम प्रयोग होने से यह विधि पर्यावरण हितैषी भी है। क्योंकि इस विधि से खेतों में पानी खड़ा नहीं होते जिससे उनमें मीथेन व नाइट्रस आक्साइड गैसों का निर्माण नहीं होते हैं तथा भूमि जैव-विविधता भी बढ़ती है।

पर्यावरण संरक्षण का हो सामूहिक प्रयास

जिस गति से ग्रामीण विकास हो रहा है, उसी तरह से हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां भी खड़ी होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें विकास के साथ ही उन चुनौतियों को लेकर भी सजग रहना होगा। जहां तक ग्रामीण विकास की बात है तो गांवों में हर स्तर पर विकास की चकाचौंध दिख रही है। विकास की इस चकाचौंध में सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण संकट की है। पर्यावरण को संरक्षित करना आवश्यक हो गया है। यदि अभी से इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो भविष्य की स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी।

पर्यावरण की अनदेखी करने की वजह से आज हमारे पास शुद्ध पेयजल का अभाव है। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा कम पड़ने लगी है। वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। पहले गांवों में बाग-बगीचों की भरमार थी, लेकिन अब बाग-बगीचों की जगह इमारतें नजर आती हैं। निश्चित रूप से इन इमारतों का बनना विकास का प्रतीक है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना हमारे जीवन के लिए खतरा है। जिस तरह से विकास की परिभाषा व्यापक है, उसी तरह से पर्यावरण की परिभाषा में जल, जंगल, जमीन और खेतीबाड़ी से लेकर मौसम तक शामिल है। हमें हर स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है।

आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। इसका मूल कारण ग्रीनहाउस गैसों से जोड़ा जाता है। जहां तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का सवाल है तो सर्वाधिक उत्सर्जन के मामले में भारत ने काफी सावधानी बरती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देश भारत से कई गुना अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन परत लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। विश्वव्यापी गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग) का कारण ओजोन का क्षरण ही है। सबसे अधिक (21.3 प्रतिशत) ग्रीनहाउस गैसें विद्युत निर्माण संयंत्रों से निकलती हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली का योगदान सर्वाधिक है।

फिलहाल भारत के गांवों में जब तक पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक विकास की अवधारणा पूरी नहीं होगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें स्वच्छता अभियान सर्वोपरि है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जहां गांवों में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है वहीं अवशिष्टों को संधारित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत सफाई हो रही है। इस दिशा में बेहतर काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में स्वच्छता एवं पर्यावरण को लेकर जागरूकता आई है। इसके साथ ही कूड़े को निस्तारित करने और उसे खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए भी ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इन सबके बीच गोबर गैस को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।

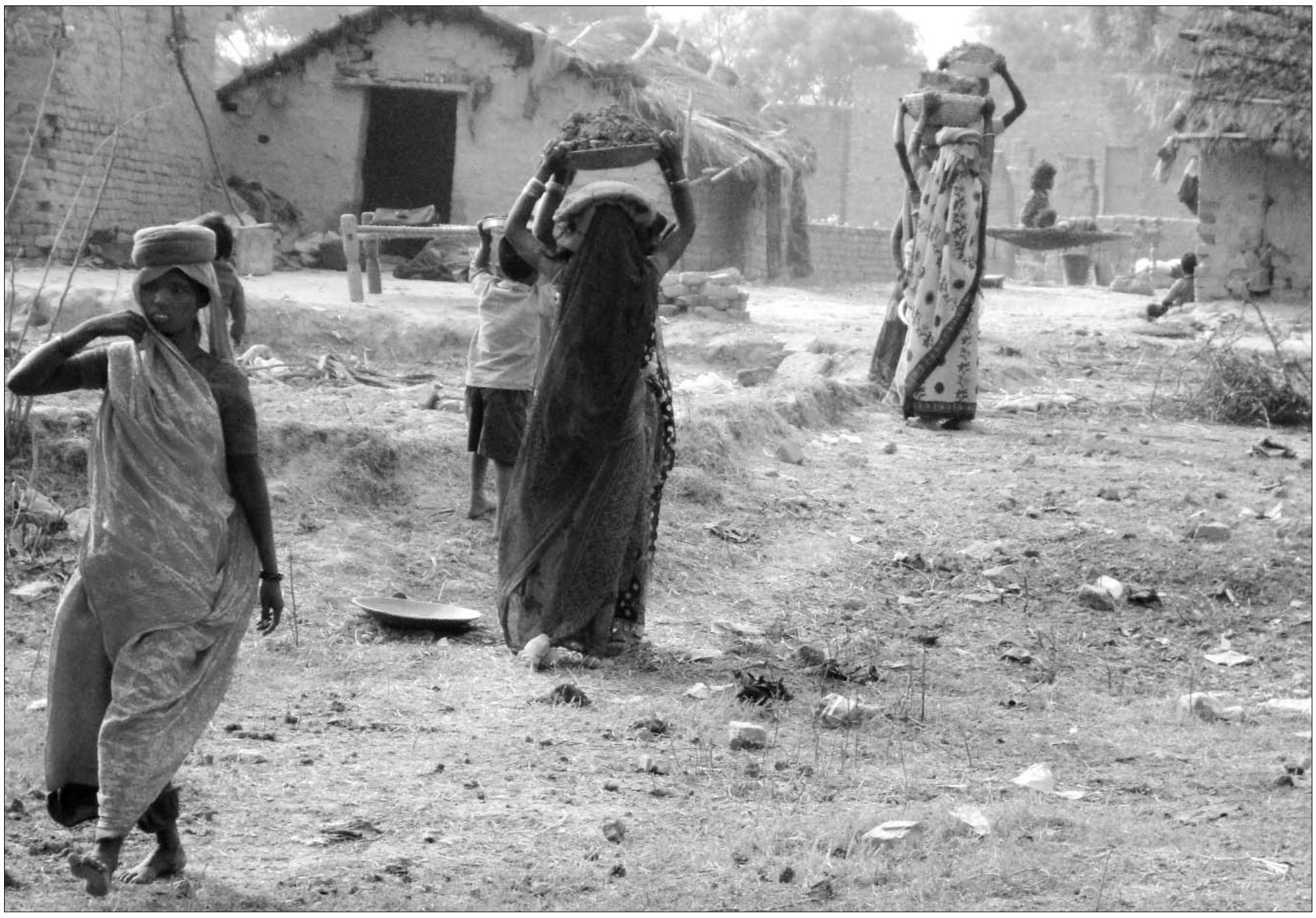

गांवों में कैसे हो विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण

गांवों में विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार के केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को केंद्र सरकार केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर और मजबूती प्रदान कर रही है। स्वच्छता के विचार को विस्तारित कर 1993 में व्यक्तिगत स्वच्छता, गृह स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल तथा कूड़े-कचरे, मानव मलमूत्र और नाली के दूषित पानी के निस्तारण को इसमें शामिल किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिए स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, शुष्क शौचालयों का फ्लश शौचालयों में उन्नयन, महिलाओं के लिए ग्राम स्वच्छता भवनों का निर्माण, स्वच्छता बाजारों तथा उत्पादन केंद्रों की स्थापना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता के लिए सघन अभियान चलाना आदि भी इस कार्यक्रम के अंग हैं।

कृषि और पर्यावरण

गांवों में कृषि कार्य अच्छे से हो, कुएं-तालाब, बावड़ियों की सफाई यथा समय हो, गंदगी से बचाव के उपाय किए जाएं। संक्षेप में यह कि वहां ग्रामीण विकास योजनाओं का ईमानदारीपूर्वक संचालन हो तो ग्रामों का स्वरूप निश्चय ही बदलेगा और वहां के पर्यावरण से प्रभावित होकर शहर से जाने वाले नौकरीपेशा भी वहां रहने को आतुर होंगे।

पशुओं के गोबर एवं अन्य अवशिष्ट का प्रबंधन

ग्रामीण इलाके में कृषि के साथ ही पशुपालन जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले पशुओं के गोबर से निकलने वाली मिथेन गैस को धरती का तापमान बढ़ने का कारण बताया गया था। इसी तरह निरर्थक रूप से गोबर के जल में मिलने से जल भी प्रदूषित हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को पशुओं के गोबर का उचित प्रयोग करने की दिशा में न सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है बल्कि इसके लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए जहां जैविक खेती के प्रति किसानों को आकर्षित किया जा रहा है वहीं गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में किसान गोबर के साथ ही अन्य कूड़ा-करकट भी संधारित करके खाद तैयार कर रहे हैं। इसे बड़े पैमाने पर विस्तारित करने की जरूरत है। यदि हर किसान जैविक एवं कंपोस्ट खाद तैयार करने लगे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण काम होगा। इससे किसानों का पैसा भी बचेगा और अधिक उत्पादन भी मिलेगा। साथ ही रासायनिक खादों और कीटनाशक से भी मुक्ति मिल जाएगी।

मशीनीकरण का प्रभाव

वैश्विक गर्मी का कारण मशीनीकरण भी माना जाता है। जहां मोटर-गाड़ियों में हजारों लीटर डीजल-पेट्रोल खर्च होता है वहीं कृषि कार्य में भी अब डीजल-पेट्रोल की खपत बढ़ने लगी है। मशीनीकरण से जहां पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वहीं ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाने वाली मधुमक्खी, तितली और गौरैया सहित अन्य जीव-जन्तु खत्म हो रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा काम प्रदूषणरहित तरीके से करें।

वायु और ध्वनि प्रदूषण

जब गांवों में सड़कें पहुंची तो वहां वाहनों का शोर और उनका धुआं भी बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ कल-कारखाने भी पहले से कई गुना अधिक बढ़े हैं। इसके विपरीत पेड़-पौधों की संख्या घटी है। चूंकि पेड़-पौधे कार्बन-डाइ-ऑक्साइड सहित अन्य हानिकारक गैस को ग्रहण कर हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। जब पेड़-पौधों की संख्या कम है तो ऑक्सीजन का कम तैयार होना लाजिमी है। ऐसी स्थिति में वायु के साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वायु में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन, 0.03 प्रतिशत कार्बन-डाइ-ऑक्साइड तथा शेष निष्क्रिय गैसें और जल वाष्प होता है। हवा में विद्यमान ऑक्सीजन ही जीवधारियों को जीवित रखती है। मनुष्य आमतौर पर प्रतिदिन 22 हजार बार सांस लेता है और सोलह किलोग्राम ऑक्सीजन का उपयोग करता है जोकि उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन और जल की मात्रा से बहुत अधिक है।

खेतों में रसायनों का असंतुलित प्रयोग

भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का तथा फसल को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। इनके कारण भूमि को लाभ पहुंचाने वाले मेंढक व केंचुआ जैसे जीव नष्ट हो जाते हैं जबकि फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े-मकोड़ों से बचाव में यही जीव सहायक होते हैं। इसलिए कृषि फसल में एलगी, कम्पोस्ट खाद तथा हरी खाद का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि खेतों में ऐसे लाभदायक जीवों की वृद्धि हो सके जो खेती की उर्वराशक्ति बढ़ा सकें। कृषि तथा अन्य कार्यों में कीटनाशकों के प्रयोग की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिकांश कीटनाशकों को विषैला घोषित किया है, बावजूद इसके हमारे देश में तो इनका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक जैविक खाद और रसायन का प्रयोग करें। इससे पर्यावरण संरक्षण होगा और हमें फायदा भी मिलेगा।

मिट्टी का कटान

भारत के एक अनुमान के तहत खेती योग्य भूमि का 60 फीसदी भूमि कटाव, जलभराव और लवणता से ग्रस्त है। यह भी अनुमान है कि मिट्टी की ऊपरी परत में से प्रतिवर्ष 4.7 से 12 अरब टन मिट्टी कटाव के कारण खो रही है। पानी के साथ बहने वाली यह मिट्टी अपने साथ विभिन्न रासायनिक तत्वों को भी ले जाती है। इससे बचने के लिए खेतों की मेड़बंदी करना जरूरी है। मिट्टी का कटाव रोककर हम कई तरह के फायदे ले सकते हैं। इसके लिए हमें पौधारोपण का फंडा अपनाना होगा।

ग्रामीण जीवन में जंगल की महत्ता

गांव से लेकर शहर तक तेजी से विकास हो रहा है। विकास की इस दौड़ में सबसे ज्यादा नुकसान जंगलों का हुआ है। जंगल जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा असर भी गांवों पर ही पड़ेगा क्योंकि जंगल किसी न किसी रूप में ग्रामीण जनजीवन से जुड़े हुए हैं। ये ग्रामीणों के लिए जहां जीवनयापन के साधन बनते हैं, वहीं पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण इलाके में खाना बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो घर बनाने से लेकर तमाम उपकरण बनाने में भी इनका प्रयोग होता है।

साथ ही पशु संपदा समृद्धि में भी जंगलों की भूमिका उल्लेखनीय है। इसके बाद भी जंगल कम हो रहे हैं। इसे बचाने की जरूर है। यदि इसी तरह से जंगलों की कटाई होती रही तो आने वाले दिनों में लोगों को लकड़ी के लिए तरसना पड़ेगा।

बाजार में जिस तरह से दूसरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कई गुना अधिक लकड़ी के दाम बढ़े हैं, लेकिन शहरों की अपेक्षा गांवों में अभी भी पेड़ों की संख्या बरकरार है। यही वजह है कि काम चल रहा है, लेकिन लोगों को जंगलों की महत्ता अभी कम समझ में आ रही है। यदि यही हाल रहा तो भविष्य में स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। इस वजह से जंगलों को बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। यदि हम अपने उपयोग के लिए एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम एक पौधा लगाने और उसे पोषित करने की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां लकड़ी के लिए तरसेंगी। जंगल बचाने की दिशा में किए जा रहे सरकारी प्रयासों में भी अपनी भूमिका निभानी होगी।

बचाना होगा वन्य जीवों को

ग्रामीण जनजीवन में चक्रिय व्यवस्था है। मानव जीवन के लिए पशु-पक्षियों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनके जरिए पर्यावरण का चक्रण बना रहता है लेकिन ग्रामीण विकास की दौड़ में पशु-पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तमाम प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं तो कई संकट से जूझ रही हैं। भारत में 50 करोड़ से भी अधिक जानवर हैं जिनमें से पांच करोड़ प्रति वर्ष मर जाते हैं और साढ़े छह करोड़ नए जन्म लेते हैं। वन्य प्राणी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। उनकी घटती संख्या पर्यावरण के लिए घातक है। सरकार की ओर से पशु-पक्षियों को संरक्षित करने की दिशा में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सामूहिक भागीदारी के बिना यह प्रयास पूरा नहीं हो सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से वन्य प्राणियों की रक्षा अनिवार्य है।

जल प्रदूषण बनी चुनौती

विकास की दौड़ में जीवन की सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संपदा जल खत्म होता जा रहा है। जो पानी बचा हुआ है वह प्रदूषित होता जा रहा है। यही वजह है कि जल संकट से निबटने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई जा रही है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जल को बचाने और प्रदूषित जल से मुक्ति पाने के लिए बजट में करोड़ों रुपये का प्रावधान कर रही है क्योंकि जल ही जीवन है। प्राणी कुछ समय के लिए भोजन के बिना तो रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं। यह सच है कि पृथ्वी का तीन चौथाई हिस्सा जलमग्न है फिर भी करीब 0.3 फीसदी जल ही पीने योग्य है। विभिन्न उद्योगों और मानव बस्तियों के कचरे ने जल को इतना प्रदूषित कर दिया है कि पीने के करीब 0.3 फीसदी जल में से मात्र करीब 30 फीसदी जल ही वास्तव में पीने के लायक रह गया है। नदियों एवं अन्य जलस्रोतों में कारखानों से निष्कासित रासायनिक पदार्थ व गंदा पानी मिल जाने से वह प्रदूषित हो जाता है।

नदियों के किनारे बसे नगरों में जले-अधजले शव तथा मृत जानवर नदी में फेंक दिए जाते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने और कीड़ों से उनकी रक्षा हेतु जो रासायनिक खाद एवं कीटनाशक प्रयोग में लाए जाते हैं वे वर्षा के जल के साथ बहकर अन्य जल-स्रोतों में मिल जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। नदियों, जलाशयों में कपड़े धोने, कूड़ा-कचरा फेंकने व मलमूत्र विसर्जित करने से भी यह स्थिति पैदा होती है। विश्व में 260 नदी बेसिन ऐसे हैं, जो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई देशों तक पहुंचते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में आधी से ज्यादा नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं और इनका पानी पीने योग्य नहीं रहा है और इन नदियों में पानी की आपूर्ति भी निरंतर कम हो रही है। हमें पीने का पानी ग्लेशियरों से प्राप्त होता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का पानी भी हमसे दूर होता जा रहा है।

दुनिया में जल उपलब्धता 1989 में 9000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति थी जो 2025 तक 5100 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी और यह स्थिति मानव जाति के संकट की स्थिति होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86 फीसदी से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित व दूषित पेयजल है। वर्तमान में 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहां वर्तमान में 303.6 मिलियन क्यूबिक फीट पानी प्रतिवर्ष एशियाई नदियों को हिमालय के ग्लेशियर्स से प्राप्त हो रहा है। भारत में सिंचाई कार्यों के लिए 70 प्रतिशत जल भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है और घरेलू कार्यों के लिए 80 प्रतिशत जल की आपूर्ति भूमिगत जल स्रोतों से की जाती है। लेकिन यह भूमिगत जल भी अब प्रदूषित होता जा रहा है। दूसरी तरफ बढ़ती आबादी और बढ़ता औद्योगिकीकरण जल की खपत बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने दोहरी चुनौतियां हैं। एक तरफ स्वच्छ पानी कम हो रहा है तो दूसरी तरफ पानी की जरूरत बढ़ रही है।

पटना, 04 अक्टूबर-10 अक्टूबर 2015
www.ganadesh.com
गणादेश

डेंगू : डरें नहीं, सम्भव है बचाव व उपचार

रोगी होने के बाद इलाज कराना मजबूरी हो जाता है, लेकिन रोगी न हो इसके लिए सावधानी जरूरी है। बीमारी को पैर पसारने न दिए जाएं साथ ही सुरक्षा के जितने हो सकें उपाय करें। संक्रामक बीमारियों के रोगाणु संपर्क में आने पर हमला करते हैं। रोग प्रतिरोधक प्रणाली को इतना मजबूत कर लें कि रोगाणुओं का हमला भी बेकार चला जाए। डेंगू मादा एडीस इजीप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। इसी तरह मलेरिया भी मच्छर के काटने से फैलता है। इस मौसम में मलेरिया होने की आशंका अधिक रहती है। ऐसे मरीज को तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में, जहां आईसीयू सुविधा हो, ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्लेटीलेट कोशिकाओं (रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, जो खून के शरीर में बहाव को रोकती है) की कमी हो जाती है। इन वायरसजनित बीमारियों का जलवायु परिवर्तन से गहन रिश्ता है अत: मौसम अनुसार खुद-ब-खुद भी बीमारी का फैलना रुक जाता है। यह बीमारी ब्राजील जैसे देश में सर्वाधिक होती है, जहां तापमान पर्यावरण में अधिक रहता है। भारत में प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के वायरस फैल नहीं पाते हैं।

बचाव के तरीके

रोगग्रसित मरीज का तुरंत उपचार शुरू करें व तेज बुखार की स्थिति में पेरासिटामाल की गोली दें। एस्प्रिन या डायक्लोफेनिक जैसी अन्य दर्द निवारक दवाई न लें। खुली हवा में मरीज को रहने दें व पर्याप्त मात्रा में भोजन-पानी दें जिससे मरीज को कमजोरी न लगे।

- जहां बीमारी अधिक मात्रा में हो, वहां फेस मॉस्क पहनना चाहिए।
- घर के आसपास मच्छरनाशक दवाइयां छिड़काएं।
- एडिस मच्छर दिन में काटते हैं, अत: शरीर को पूर्ण रूप से ढंकें।
- पानी के फव्वारों को हफ्ते में एक दिन सुखा दें। घर के आसपास छत पर पानी एकत्रित न होने दें।
- घर का कचरा सुनिश्चित जगह पर डालें, जो कि ढंका हो।
- कचरा आंगन के बाहर न फेंककर नष्ट करें।
- पानी की टंकियों को कवर करके रखें व नियमित सफाई करें।

इस तरह थोड़ी-सी सावधानी से स्वस्थ रहा जा सकता है।

डेंगू के लक्षण

डेंगू के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसके मच्छर दिन के समय काटते हैं तथा यह मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। बड़ों के मुकाबले यह बच्चों में ज्यादा तेजी फैलता है। डेंगू के दौरान यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स का स्तर बहुत तेजी से नीचे गिरता है जिससे कई बार अंदरूनी रक्तस्त्राव होने की संभावना भी रहती है।

डेंगू का लक्षण प्रथम चरण

डेंगू का लक्षण प्रथम चरण में सामान्य बुखार की तरह ही होता हैं इसलिए पहले चरण में इसका पता लगाना मुश्किल होता है। प्रथम चरण में डेंगू के लक्षण इस प्रकार के होते हैं...

- 104 डिग्री तक बुखार का टेम्परेचर चढ़ जाता है
- बुखार आने के वक्त ठंड लगने लगता है
- सर में बहुत दर्द होना
- मांसपेशियों या जोड़ों में बहुत दर्द होना
- गिलटी (gland) में दर्द या सूजन होना
- उल्टी होना
- भूख न लगना
- ब्लडप्रेशर कम हो जाना
- चक्कर आना
- शरीर में रैशज का होना
- खुजली होना
- कमजोरी होना

यह तो डेंगू के प्रथम अवस्था के लक्षण हैं जो साधारणत: रोगी के शरीर के मुताबिक होता है। लेकिन जब डेंगू के रोग की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तब शरीर में कुछ और समस्याएं नजर आने लगती है।

- पेट में तेज दर्द होना
- पेशीशूल (myalgia)
- लीवर में फ्लूइड का जमा होना
- सीने में फ्लूइड का जमा होना
- रक्त में बिंबाणु (platelet) का कम होना
- रक्तस्राव (hemorrhages) आदि

डेंगू वायरस जनित बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर गंदे पानी की बजाय साफ पानी में ही पनपता है। इसलिए घर के अंदर या घर के आसपास पानी ना जमने दें। बरसात में गमलों, कूलरों, टायर आदि में एकत्रित हुए पानी में यह मच्छर ज्यादा पाया जाता है। डेंगू में बुखार बहुत तेज होता है और इसके साथ ही कमजोरी चक्कर भी आता रहता है। कुछ लोगों को चक्कर आने की वजह से बेहोशी छा जाती है। रोगी के मुंह का स्वाद बदल जाता है और उसे उल्टियां भी आती हैं। सिरदर्द, बदन दर्द और पीठ के दर्द की भी शिकायत होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और प्लेटलेट्स काउंट चेक कराएं। समय पर किया गया इलाज आपको डेंगू से निजात दिला सकता है वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। डॉक्टरों के मुताबिक घर में इलाज करते हुए कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी पीने और कुछ भी खाने में दिक्कत हो और बार-बार उल्टी आए तो डीहाइड्रेशन का खतरा हो जाता है। प्लेटलेट्स के कम होने या ब्लड प्रेशर के कम होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर रोगी को खून आना शुरू हो जाए तो तुंरत अस्पताल जाना चाहिए।

डेंगू के लिए जरूरी टेस्ट

डेंगू एक ऐसा बुखार है, जो ठहरे हुए पानी में पैदा हुए मच्छरों के काटने पर होता है, और इन्हीं के द्वारा यह रोग एक इंसान से दूसरे को संक्रमित करता है। यदि डेंगू पीड़ित व्यक्ति को काटने के बाद कोई मच्छर आपको काटता है, तो आपको भी डेंगू हो सकता है। डेंगू से बचने के लिए सतर्कता रखना और बचाव के उपाय करना आवश्यक है। डेंगू के लक्षण महसूस करने के बाद इसकी जांच करना भी बेहद आवश्यक है। इसके लिए आपको यह टेस्ट जरूर करवाना चाहिए...

एनएस 1 : एनएस 1 टेस्ट डेंगू के लक्षण सामने आने पर शुरूआती पांच दिनों के अंदर किया जाना चाहिए, ताकि इसके सार्थक और सटीक परिणाम प्राप्त हो सके। शुरूआती 5 दिनों के अंदर डेंगू के लक्षण होने पर यह जांच करवाना चाहिए, ताकि डेंगू की उपस्थिति को बेहतर तरीके से जाना जा सके। इसके बाद इस टेस्ट को करवाने पर परिणाम गलत भी सामने आ सकते हैं। एनएस1 टेस्ट प्रारंभिक 5 दिनों के भीतर बीमारी का पता लगाने में सक्षम होता है, लेकिन इसके अलावा इसके परिणामों की प्रमाणिकता संदेहास्पद होती है। अगर आप यह जांच देरी से करवाते हैं, तो यह जरूरी नहीं है, कि इसके परिणामों में डेंगू बुखार की पुष्टि हो। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती है, जब मरीज को डेंगू होते हुए भी समय पर जांच नहीं करवाने के कारण गलत परिणाम सामने आते हैं और डेंगू की पुष्टि नहीं हो पाती। ऐसे में मरीज डेंगू का सामना जरूर करता है, लेकिन उसे सही इलाज नहीं मिल पाता और उसकी स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जाती है।

एलाइजा : डेंगू के लिए की जाने वाली यह एक ऐसी जांच है, जिसमें डेंगू की पुष्टि प्रमाणिक रूप से हो जाती है, जिससे डॉक्टर्स को मरीज का बेहतर तरीके से इलाज करने में आसानी होती है। एलाइजा टेस्ट में आईजीएम डेंगू के लक्षण सामने आने के लगभग 3 से 5 दिन के अंदर व आईजीजी 5 से 10 दिन के अंदर होता है। इसके परिणामों में सटीकता, जांच के समय पर आधारित होती है। मतलब समय रहते जांच करवाने पर डेंगू की पुष्टि प्रमाणिक हो जाती है और इलाज भी बेहतर होता है।

डेंगू के अधिकांश मामलों में डॉक्टर्स एनएस1 टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि यह टेस्ट शुरूआती 5 दिनों में ही करवाया जाता है, जबकि एलाइजा टेस्ट में अधिक समय लगता है। ऐसे में मरीज अधिक समय तक इंतजार करने के बजाए, एनएस1 करवाना ही बेहतर समझते हैं। हालांकि एलाइजा टेस्ट के परिणाम एनएस1 की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक होते हैं। लेकिन डेंगू की जांच कराने के बाद परिणाम का इंतजार करने के स्थान पर लक्षणों के आधार पर प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा मरीज की हालत बिगड़ भी सकती है।

डेंगू से निपटने के घरेलू नुस्खे

डेंगू बुखार मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। एडीज मच्छर (प्रजाती) के काटने से डेंगू वायरस फैलता है। बुखार के दौरान प्लेटलेट्स कम होना इसका मुख्य लक्षण हैं। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। बुखार के साथ सबसे सामान्य लक्षण है सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और त्वचा का खराब हो जाना। कभी-कभी, यह लक्षण फ्लू के साथ मिलकर कंफ्यूज भी कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू इंफेक्शन का पता ब्लड टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। इससे बचने के लिए कोई स्पेशल दवाई नहीं है, लेकिन इस दौरान आपको सही से आराम करने और बहुत सारे पेय पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है। डेंगू की चपेट में आने के बाद लोग इससे बचने के लिए कुछ प्राकृतिक नुस्खे अपना रहे हैं। हम आपको हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर की सलाह से कुछ ऐसे ही घरेलू और प्राकृतिक नुस्खे बता रहे हैं ताकि आप खुद को डेंगू के प्रकोप से बचा सकें...

डेंगू के लिए पपीते के पत्ते

पपीते की पत्तियों को डेंगू के बुखार के लिए सबसे असरकारी दवा कही जाती है। पपीते की पत्तियों में मौजूद पपेन नामक एंजाइम शरीर की पाचन शक्ति को ठीक करता है, साथ ही शरीर में प्रोटीन को घोलने का काम करता है। इसके अलावा इस जूस से प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से बढ़ती है। डेंगू के उपचार के लिए पपीते की पत्तियों का ताजा जूस निकाल कर एक-एक चम्मच करके रोगी को दें। पपीते का पेड़ आसानी से मिल जाता है।

प्रभावशाली बकरी का दूध

बकरी का दूध बहुत से लोगों को भले ही पसंद न हो लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। डेंगू बुखार के लिए बकरी का दूध एक और बहुत ही प्रभावशाली दवा है। बकरी के दूध में गिरते हुए प्लेबटलेट्स को तुरंत बढ़ाने की क्षमता होती है। डेंगू के उपचार के लिए रोगी को बकरी का कच्चा दूध थोड़ा-थोड़ा करके पिलाएं, इससे प्लेटलेट्स बढ़ने के साथ-साथ जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा।

विषाक्त पदार्थ बाहर निकाले मेथी के पत्ते

मेथी के पत्ते भी डेंगू के बुखार को ठीक करने में मददगार होते हैं। मेथी से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिससे डेंगू के वायरस भी खत्म होते हैं। साथ ही यह पीड़ित का दर्द दूर कर उसे आसानी से नींद में मदद करती हैं। मेथी के पत्तों को पानी में उबालकर हर्बल चाय के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, मेथी पाउडर को भी पानी में मिलाकर पी सकते हैं।

रक्त की कमी पूरा करें अनार

डेंगू बुखार में रक्त की कमी को पूरा करने और प्लेटलेट्स के स्तर को बढ़ाने के लिए अनार का रस पीना चाहिए। अनार में मुख्य रूप से विटामिन ए, सी, ई, फोलिक एसिड और एंटी ऑक्सीडेंट पाये जाते हैं। जो रोगी को रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। डेंगू में रोगी को नियमित रूप से ताजा अनार का जूस देना चाहिए।

प्लेटलेट बढ़ाने के लिए गिलोय

गिलोय की बेल का सत्व मरीज को दिन में 2-3 बार दें, या गिलोय के 7-8 पत्तों को लेकर कुचल लें उसमें 4-5 तुलसी की पत्तियां लेकर एक गिलास पानी में मिला कर उबालकर काढा बना लीजिए और इसमें पपीता के 3-4 पत्तों का रस मिला कर दिन में तीन चार लेने से रोगी को प्लेटलेट की मात्रा में तेजी से इजाफा होता है। प्लेटलेट बढ़ाने का इस से बढ़िया कोई इलाज नहीं है। यदि गिलोय की बेल आपको ना मिले तो किसी आयुर्वेदिक स्टोर से आप गिलोय घनवटी लेकर एक एक गोली रोगी को दिन में 3 बार दे सकते हैं।

तुलसी : 10 से 12 तुलसी के पत्ते और 4-5 काली मिर्च को गर्म पानी में उबालकर छानकर, डेंगू के मरीज को पिलाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। तुलसी की यह चाय डेंगू रोगी को बेहद आराम पहुंचाती है। यह चाय दिनभर में तीन से चार बार ली जा सकती है। यह चाय आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है और एंटी-बैक्टीरियल तत्व के रूप में कार्य करती है।

गोल्डनसील: यह नार्थ अमेरिका में पाई जाने वाली एक हर्ब है, जिसे दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हर्ब में डेंगू बुखार को बहुत तेजी से खत्म कर शरीर में से डेंगू के वायरस को खत्म करने की क्षमता होती है। यह पपीते की पत्तियों की तरह ही काम करती हैं और उन्हीं की तरह इन्हें भी यूज किया जाता है। इन्हें कूट के सीधे चबाकर या फिर जूस पीकर लाभ उठाया जा सकता है।

हल्दी : यह मेटाबालिज्म बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यही नहीं, घाव को जल्दी ठीक करने में भी मददगार साबित होती है। हल्दी को दूध में मिलाकर पीया जा सकता है।

एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बेस्ट करियर ऑप्शन

संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रदूषण जिस तेजी से बढ़ रहा है और उसे कम करने की दिशा में आए दिन नए शोध और विकास कार्य होते रहते हैं। यही वजह है कि इस दिशा में कार्य कर रहे एन्वायरमेंटल इंजीनियर्स की मांग न सिर्फ देश में, बल्कि विदेश में भी काफी बढ़ रही है। एक प्रशिक्षित एन्वायरमेंटल इंजीनियर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इस तरह डिजाइन, कन्सट्रक्ट और मेंटेन करे, ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले लोग स्वस्थ्य जीवन जी सकें।

स्वच्छ वातावरण में जीयो जी भर के!

एन्वायरमेंटल इंजीनियर्स विज्ञान और इंजीनियरंग के तरीकों को मिला-जुलाकर पर्यावरण सुधारने का कार्य करते हैं, ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, सांस लेने के लिए प्रदूषण रहित हवा और अनाज आदि पैदा करने के लिए उपजाऊ भूमि मिल सके। पिछले कुछ दशकों में तो इस क्षेत्र में संभावनाएं और भी बढ़ी है। अब इस क्षेत्र के प्रेफेशनल्श की मांग कैमिकल, जियोलॉजिकल, पेट्रोलियम और माइनिंग सेक्टर्स से जुड़ी कंपनियों में भी हैं।

शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक स्तर पर एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग स्नातक और स्नातकोतर और शोध तीनों स्तरों पर उपलब्ध है। एन्वायरनमेंटल साइंस में बीएससी तीन वर्षीय स्नातक कोर्स है, वहीं एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एमएससी दो साल का स्नातकोतर कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी में 12वीं पास छात्र एन्वायरमेंटल साइंस में बीएससी कर सकते हैं। इसी प्रकार एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमएससी करने के लिए छात्र का एन्वायरमेंटल साइंस में बीएससी होना अनिवार्य है। इस क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के अलावा छात्र पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में आपके ज्ञान और योग्यताओं को नया आयाम देता है। वहीं अगर आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहा है तो आप एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बीई कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी एंड एन्वायरमेंट मैनेजमेंट में एमटेक भी की जा सकती है जो आप एन्वायरमेंट में बीई या सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद कर सकते हैं।

संभावनाएं

कैमिकल, बायोलॉजिकल, थर्मल, रेडियोएक्टिव और यहां तक कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड छात्रों के लिए भारत में एन्वायरमेंटल इंजीनियिंग के क्षेत्र में काफी स्कोप है। इसके अलावा प्रोसेस इंजीनियरिंग, एन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वॉटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट रिडक्शन मेनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रीवेन्शन आदि क्षेत्रों के प्रोफेशनल्श की भी यहां काफी मांग है। गैर सरकारी संस्थाएं और कई सरकारी विभाग भी हरित विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। शोध से जुड़े कार्यक्रम में भी इस क्षेत्र केम प्रोफशनल्श की अच्छी-खासी मांग है। एमटेक इंजीनियंरिग कर चुके छात्र सरकारी एसेसमेंट कमेटियों में भी कार्य कर सकते हैं।

विदेश में संभावनाएं

कई अंतरराष्ट्रीय विभाग और यूएनओ जैसी संस्थाओं में एन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रशिक्षितों की मांग है। पर्यावरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर फ्रीलांस के तौर पर कम करने का मौका भी मिल सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की ऐवज में अच्छा-खासा वेतन भी मिलता है, साथ ही कई जरूरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। यूएस में एन्वायमेंटल इंजीनियर्स को अच्छी तनख्वाह दी जाती है।

वेतन

एन्वायरमेंटल इंजीनियर्स को केंद्र और राज्य स्तरीय पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ काम करने का अवसर मिलता है। स्टेट पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ काम कर रहे प्रशिक्षितों को 15 से 30 हजार रुपए तक का वेतन मिल सकता है। वहीं एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक कर चुके छात्र इस क्षेत्र में 50 हजार रुपए तक का वेतन पा सकते हैं। बात करें इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर होने वाले शोध कार्यों की तो इसमें 75 हजार रुपए तक कमाए जा सकते हैं।

संस्थान

साउथ गुजरात यूनीवर्सिटी, सूरत
दिल्ली विश्वविद्यालय
मैसूर यूनिवर्सिटी
दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग
राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंदौर
आईआईटी, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास

एन्वायमेंटल इंजीनियरिंग का क्षेत्र चुनने के लिए आपके अंदर इस विषय के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। यह करियर बेशक चुनौतियों भरा है, क्योंकि यहां आपसे पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर हर बार क्रांतिकारी समाधान देने की अपेक्षा की जाएगी। पर बात करें वेतनमान की तो यह काफी आकर्षित करने वाला होता है।

जॉब अलर्ट

LIC में पार्ट टाइम नौकरी पाने का मौका

लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र में पार्ट टाइम नौकरी के लिए वैकेंसी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।

पद का नाम : LIC एजेंट
पदों की संख्या : 39
योग्यता : ग्रेजुएट
वैकेंसी टाइप : अस्थाई
उम्र सीमा : 18-55 साल
ईमेल आईडी : sudhir-sanap@yahoo.com
ज्यादा जानकारी के लिए लिंक : www.maharojgar.gov.in

मेट्रो में कई पदों के लिए नौकरी पाने का मौका

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।

पद का नाम :
जूनियर इंजीनियर
सेक्शन इंजीनियर
मेंटेनर
ट्रेन ऑपरेटर
पदों की संख्या :188
सैलरी : 8,000-30,770 रुपये
योग्यता : 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा
उम्र सीमा :18-25 साल
ज्यादा जानकारी के लिए लिंक : http://kochimetro.org/

NPCIL में नौकरी पाने का मौका

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) में वैकेंसी निकली हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 नवंबर 2015 तक आवेदन कर सकते हैं।

पदों के नाम :
टेक्निकल ऑफिसर : 57 पद
डिप्टी मैनेजर : 2 पद
जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर :1 पद
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी : 24 पद
उम्र सीमा : 18-24 साल
चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है।

10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) में कई पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।

पद का नाम :
जूनियर असिस्टेंट
असिस्टेंट
सिक्योरिटी सुपरवाइजर
जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट
पदों की संख्या : 111
सैलरी : 12000-27000 रुपये
उम्र सीमा : 18-30 साल
योग्यता : संबंधित पद के हिसाब से 10वीं/12वीं/बैचलर डिग्री
ज्यादा जानकारी के लिए लिंक : http://www.ongcindia.com/

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी

उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (क्कस्स्स्ष्ट) में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 19 अक्टूबर 2015 तक आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण :
ड्राफ्टमैन : 39 पद
पे स्केल : 5200-20200 रुपये
सर्वेयर : 29 पद
पे स्केल : 5200-20200 रुपये
ट्यूबलर : 22 पद
पे स्केल : 5200-20200 रुपये
एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्पेक्टर : 17 पद
पे स्केल : 5200-20200 रुपये
सीनियर एग्रीकल्चर मार्केटिंग **इंस्पेक्टर :** 11 पद
पे स्केल : 5200-20200 रुपये
उम्र सीमा : 18 से 40 साल

OSSC में कई पदों के लिए 186 वैकेंसी

ओडिशा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSC) में वैकेंसी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 2 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

पद का नाम :
आर्ट इंस्ट्रक्टर
टीचर एजुकेटर
फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
पदों की कुल संख्या : 186
योग्यता : संबंधित स्ट्रीम में मास्टर डिग्री
आवेदन फीस : 100 रुपये
उम्र सीमा : 21-35 साल
ज्यादा जानकारी के लिए लिंक : http://www.ossc.gov.in/

आप भी पहुंच सकते हैं शिखर पर..

सभी लोग अपने करियर को सफल और संतुष्टिजनक बनाना चाहते हैं। शिखर पर भला कौन नहीं पहुंचना चाहता? करियर में सही मुकाम हासिल करने की राह में लोग कई तरह के प्रयोग करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में उनसे कई तरह की गलतियां भी होती हैं। हम आपको यहां कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने करियर को सफल और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं और आपके लिए शिखर पर पहुंचने की राह आसान हो सकती है।

काम के प्रति हो जुनून

आपमें यदि अपने काम के प्रति गहरा जुनून नहीं है, तो सफलता की राह पर बढ़ना आसान नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी संभव हो, अपने करियर में ऐसा कुछ तलाशें जो आपको प्रेरित करता हो। आप यदि ऐसा कोई काम करते हैं, जिसे करने पर आपकी आंखों में ऊर्जा और उत्साह भरी चमक आ जाती है तो आपके करियर को उज्ज्वल होने से कोई रोक नहीं सकता।

ऊपर ही नहीं, अगल-बगल भी देखें

अक्सर लोग सफलता की ओर बढ़ने का एकमात्र तरीका यह मान लेते हैं कि सीढ़ी पर कदम रखते हुए ऊपर की ओर बढ़ते चला जाए। लेकिन कई बार यह तरीका सही नहीं होता। जब आप सीढ़ी पर वर्टिकल चढ़ते जाते हैं तो अपनी टीम से कट जाते हैं और कई हॉरिजंटल मौकों को गंवा देते हैं। अपने अगल-बगल देखते हुए भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इस तरह मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाएं, अन्यथा यह भी हो सकता है कि जल्दबाजी में आप सीढ़ियां चढ़ते जाएं और टॉप पर पहुंचने के बाद ऐसा लगे कि अरे! यह तो हमारी मंजिल थी ही नहीं।

काम का कोई उद्देश्य हो

आपकी मौजूदा भूमिका जो भी हो, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। सफलता की कुंजी यह है कि आज पर फोकस रखते हुए भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। आपको अपनी करियर आकांक्षाओं और मौजूदा जॉब के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा।

लीडरशिप जरूरी है

किसी सफल करियर को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है, कुशल नेतृत्व का गुण सीखना। ध्यान रहे, यदि आप बहुत गहरी खाई में उतर कर नेतृत्व करने लगते हैं तो आपको ऐसी किसी सुविधाजनक जगह पहुंचने में मुश्किल आएगी जहां से रणनीतिक नेतृत्व कर सकते हों। इसी तरह, बहुत ऊंचाई पर चढ़कर नेतृत्व करने से आप अपनी टीम से कट जाएंगे, अलग-थलग पड़ जाएंगे और आपको सिर्फ अपने लिए नेतृत्व करने वाला समझा जाएगा। एक सफल नेतृत्व और सफर करियर के लिए यह जरूरी है कि आपको अपने कर्मचारियों के बीच समुचित सम्मान मिले। इसके लिए आपको टीम को साथ लेकर चलना सीखना होगा।

मंजिल का सफर अकेले आसान नहीं

ध्यान रहे कि करियर का निर्माण कभी भी अकेले दम पर नहीं हो सकता। आप किसी महान शेफ के साथ किचन में जाएं तो देखेंगे कि उसके साथ कई शेफ की पूरी टीम लगी हुई है और इस टीम के पूरे लय में मिलकर काम करने के बाद ही कोई स्वादिष्ट डिश तैयार होती है। इसी तरह बिजनेस या नौकरी में भी सफलता अकेले हासिल नहीं की जा सकती। आपको अपने प्लान को लागू कराने के लिए सक्षम सहकर्मियों, मित्रों व अन्य लोगों की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको समय-समय पर भरोसेमंद लोगों की सलाह की जरूरत भी पड़ती है।

वाटर साइंस में हैं संभावनाएं

आप शायद ही जानते होंगे कि पानी में भी कॅरियर संवारा जा सकता है। वो भी एक जल वैज्ञानिक के तौर पर। विश्वभर में पानी की बढ़ती समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस क्षेत्र से जुड़कर लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। जल वैज्ञानिकों के लिए इस फील्ड में काफी स्कोप नजर आ रहा है। वाटर साइंटिस्ट के तौर पर आप जहां पानी पर कई प्रयोग कर सकते हैं, वहीं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में सेवाएं देकर अच्छा वेतनमान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको वाटर साइंस में कोर्स करना होगा। यह अपने आप में बड़ी शाखा है, जिसके अध्ययन के फलस्वरूप आप अपने करियर में नई उड़ान भर सकते हैं।

क्या है वाटर साइंस

वाटर साइंस पानी की पृथ्वी और भूमिगत क्रियाओं से संबंधित विज्ञान है। इसमें पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों और खनिजों के साथ पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के साथ-साथ सजीव शरीर-रचनाओं के साथ इसकी विवेचनात्मक पारस्परिक क्रियाएं शामिल हैं। जल विज्ञान के क्षेत्र में हाइड्रोमिटिरोलॉजी, भूतल, जल विज्ञान, हाइड्रोजिओलॉजी, ड्रेनेज बेसिन मैनेजमेंट और जल गुणवत्ता से संबंधित विषय आते हैं। इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे-रासायनिक जल विज्ञान, पारिस्थितिकी जल विज्ञान, हाइड्रोइन्फॉरमैटिक्स जल विज्ञान, हाइड्रो मिटियोरोलॉजी, भूतल जल-विज्ञान।

इस क्षेत्र में काफी कुछ कर सकते हैं

जल वैज्ञानिक जलीय पर्यावरण की सुरक्षा, निगरानी और प्रबंधन के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित करते हैं। जल विज्ञान के तहत डाटा की व्याख्या तथा विश्लेषण संबंधी गतिविधियां शामिल हैं और जल-वैज्ञानिक निरंतर उनके द्वारा जांच की जाने वाली भौतिक प्रक्रियाओं की अनुकरणात्मकता के लिए गणितीय मॉडल्स का विकास तथा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पानी के नमूने लेना तथा उनका रासायनिक विश्लेषण करना, नदियों तथा झीलों की स्थितियों की निगरानी के लिए जीव-विज्ञानियों और पारिस्थितिकीविदों के साथ कार्य करना भी इनके कार्यक्षेत्र में आता है।

यहां कर सकते हैं काम

वाटर साइंटिस्ट बनकर आप विभिन्न प्रकार के संगठनों के लिए काम कर अच्छी सैलेरी पा सकते हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में वाटर साइंटिस्ट को अच्छे वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा आप परामर्शदाता के रूप में भी काम कर सकते हैं। जैसे- सिविल इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय प्रबंधन और मूल्यांकन में सेवाएं उपलब्ध कराना।

ये हैं कोर्स

देशभर की कई यूनिवर्सिटी जल-विज्ञान और जल-संसाधन विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स संचालित करती हैं।

कहां से करें कोर्स

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, उत्तराखंड।
- अन्ना यूनिवर्सिटी, ग्विंडी, तमिलनाडु। एम. एस. बड़ौदा यूनिवर्सिटी, वड़ोदरा। इग्नू, नई दिल्ली।
- श्री गुरुगोबिंद सिंह ज़ी कॉलेज, नांदेड़। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरूचिरापल्ली।
- आन्ध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर।
- दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली।
- इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़।

हार के बाद भी बने कई शानदार रेकॉर्ड

नई दिल्ली : टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज के पहले टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका से हार भले ही गई, लेकिन मैच में उसके खिलाड़ी छाए रहे। मैच में हिटमैन रोहित शर्मा और टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। विराट कोहली ने टी-20 करियर के 1000 रन पूरे किए, वहीं रोहित शर्मा ने धमाकेदार सेन्चुरी लगाई। विराट यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 20 वें बल्लेबाज बन गए हैं।

हार के बाद भी धोनी ने बनाया रेकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए पहले टी20 मैच में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और रेकॉर्ड जुड़ गया। धोनी 50 टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जब धोनी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन के इस मैदान पर उतरे वह 50 टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 34 वर्षीय धोनी की कप्तानी ने भारत ने 2007 में खेला गया पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था। धोनी ने अपनी कप्तानी में 26 मैच जीते हैं और 23 में उन्हें हार मिली है। पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच टाइ हुआ था जिसका फैसला बॉल-आउट से हुआ था। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था। शुक्रवार को टी20 मुकाबले में बतौर कप्तान धोनी एक वर्ष से भी ज्यादा वक्त बाद उतरे। पिछली बार धोनी ने बतौर कप्तान में सितंबर 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे। इसके बाद से वह वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और टेस्ट मैचों में व्यस्त रहे।

धर्मशाला में इतने छक्के लगे कि टूट गए भारत में बने पुराने रिकॉर्ड

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में रनों की जोरदार बारिश हुई। टीम इंडिया के 200 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने दो गेंद शेष हासिल कर लिया। इस मैच के दौरान दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

इसी का नतीजा रहा कि भारत में किसी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगने का रिकॉर्ड टूट गया। इस मैच में कुल 20 छक्के लगे जिनमें से 11 भारतीय बल्लेबाजों ने और नौ दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के बल्ले से निकले।

इससे पहले 2009 में मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच मैच में 17 छक्के लगे थे। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 5, विराट कोहली ने 3, सुरेश रैना ने दो और एमएस धोनी ने एक छक्का लगाया। वहीं प्रोटीज टीम की ओर से जेपी डुमिनी ने अकेले ही सात छक्के उड़ा दिए। इसके साथ ही डुमिनी ने भारत के खिलाफ एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। उनसे पहले डेविड वार्नर, क्रिस गेल, शेन वाटसन और इयॉन मॉर्गन भी भारत के खिलाफ एक मैच में 7-7 छक्के लगा चुके हैं।

टी-20 : कोहली ने पूरे किए सबसे तेज 1000 रन

टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अपना 28वां रन बनाते ही एक साथ दो रिकॉर्ड कायम कर दिए। कोहली टी-20 मैचों में 1000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने के साथ ही सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। 28 मैचों में 46.28 के औसत से 972 रन बनाने वाले कोहली ने लेग स्पिनर इमरान ताहिर पर छक्के के साथ यह उपलब्धि हासिल की। भारत की टेस्ट टीम के कप्तान कोहली इंटरनेशनल टी20 मैचों में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 20वें बल्लेबाज हैं। महज 29 मैचों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले कोहली सिर्फ 27 पारियों में ही इस उपलब्धि तक पहुंच गए जो कि विश्व रिकॉर्ड है। इस लिस्ट में क्रिस गेल, ब्रैंडन मैकलम, ए. बी. डिविलियर्स, सुरेश रैना जैसे बिग हिटर भी शामिल हैं लेकिन ये सभी इस मामले में कोहली से काफी दूर हैं।

धोनी की टीम नहीं मिल पाई विराट के चहेतों को जगह

टीम इंडिया के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को टीम को जादुई कप्तान माना जाता है। वे जब भी टीम का चयन करते है, तो अपने हिसाब से करते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल मैच में धोनी ने जो टीम चुनी, उसमें टीम के इनफॉर्म बल्लेबाज अंजिक्या रहाणे, अमित मिश्रा, हरभजन सिंह और स्टुअर्ट बिन्नी को बाहर रखा गया। आपको बता दें कि अंजिक्या रहाणे, अमित मिश्रा और हरभजन सिंह विराट कोहली के करीबी माने जाते हैं। धोनी के कई फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते है, लेकिन यही उनका अंदाज है। कुछ लोगों का मानना है कि टीम इंडिया के अंदर हो रही राजनीति के कारण रहाणे और हरभजन सिंह को बाहर किया गया है। इस समय अंजिक्या रहाणे जबरदस्त फार्म में हैं। हाल ही में उन्होंने श्रीलंका दौरे पर टेस्ट में दो शतक लगाए थे। इससे पहले उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के नेतृत्व करने का मौका भी मिला था।

रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल ने ललित मोदी से जुड़े दस्तावेज मांगे

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से घिरे आईपीएल के पूर्व मुखिया ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय से कांट्रेक्ट और दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल से मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा था। जिन कॉन्ट्रक्ट्स के दस्तावेज मांगे गए हैं उसमें मल्टी स्क्रीन मीडिया सिंगापुर, वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप मॉरीशस और बीसीसीआई के बीच हुए सौदे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय इंटरपोल को जवाब देने की प्रक्रिया में है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के मध्य तक वैश्विक एजेंसी द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने मामले पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार वर्ष 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल के मीडिया राइट वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को 642 मिलियन डॉलर में और मल्टी स्क्रीन मीडिया सिंगापुर को 276 मिलियन डॉलर में सौंप दिए थे। मार्च 2009 में मोदी ने मल्टी स्क्रीन मीडिया सिंगापुर के साथ अनुबंध को निरस्त कर दिया था।

सूत्रों के अनुसार इंटरपोल ने जानकारी चाही है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच में वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (भारत) और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (मॉरीशस) का नाम क्यों शामिल किया गया। इसके अलावा इंटरपोल ने फिर ईडी से कहा है कि क्या मोदी के खिलाफ वर्तमान जांच फेमा अथवा प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के उल्लंघन से सम्बंधित है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मोदी के खिलाफ अब तक 16 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 15 फेमा और एक पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दर्ज है।

चैम्पियंस ट्रॉफी : वेस्ट इंडीज नहीं कर पाया क्वॉलिफाइ

दुबई : पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव से गुजर रही वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड में 2017 में होने वाली आईसीसी चैंपियन्स ट्रोफी के लिए क्वॉलिफाइ करने में नाकाम रही क्योंकि वह 30 सितंबर 2015 तक वनडे रैंकिंग में शीर्ष आठ टीमों में जगह नहीं बना पाई। यह 1998 में इस टूर्नमेंट की शुरुआत के बाद पहला अवसर होगा जब कैरेबियाई देश इसका हिस्सा नहीं होंगे।

दूसरी तरफ बांग्लादेश इस प्रतिष्ठित टूर्नमेंट में खेलने का अधिकार हासिल करने में सफल रहा। वह 2006 के बाद पहली बार चैंपियन्स ट्रोफी में वापसी करेगा। इंग्लैंड में एक से 18 जून 2017 में होने वाले टूर्नमेंट के लिए बुधवार को आठ टीमों की पुष्टि कर दी गई। आईसीसी चैंपियन्स ट्रोफी 2017 में जिन आठ टीमों को जगह मिली है उनमें (रैंकिंग के अनुसार) ऑस्ट्रेलिया, मौजूदा चैंपियन भारत, 1998 का विजेता साउथ अफ्रीका, 2000 का चैंपियन न्यू जीलैंड, 2002 का सह चैंपियन श्रीलंका, मेजबान इंग्लैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। बांग्लादेश ने आखिरी बार भारत में आईसीसी चैंपियन्स ट्रोफी में हिस्सा लिया था। तब इसमें क्वॉलिफाइंग राउंड भी हुआ करता था। वह तब श्रीलंका से 37 रन से और वेस्ट इंडीज से दस विकेट से हार गया था। उसने एकमात्र जीत जिम्बाब्वे के खिलाफ 101 रन से दर्ज की थी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2015 से ही बांग्लादेश की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसने पाकिस्तान, भारत और साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतीं जिससे वह आईसीसी वनडे रैंकिंग में सातवें स्थान पर पहुंचने में सफल रही।

आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग (30 सितंबर 2015 के अनुसार)
1. ऑस्ट्रेलिया (127 पॉइंट), 2. भारत (115 पॉइंट), 3. साउथ अफ्रीका (110 पॉइंट), 4. न्यू जीलैंड (109 पॉइंट), 5. श्रीलंका (103 पॉइंट), 6. इंग्लैंड (100 पॉइंट), 7. बांग्लादेश (96 पॉइंट), 8. पाकिस्तान (90 पॉइंट), 9. वेस्ट इंडीज (88 पॉइंट), 10. आयरलैंड (49 पॉइंट), 11. जिम्बाब्वे (45 पॉइंट), 12. अफगानिस्तान (41 पॉइंट)

चैंपियन्स ट्रोफी 2017 में कुल 15 मैच होंगे। इसके लिए टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा तथा प्रत्येक ग्रुप से चोटी पर रहने वाली दो टीमें सेमी फाइनल में पहुंचेंगी। ग्रुप और आईसीसी चैंपियन्स ट्रोफी का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। अब जबकि आईसीसी चैंपियन्स ट्रोफी 2017 के लिए टीमों की पुष्टि कर दी गई है तब अगला महत्वपूर्ण क्वॉलिफिकेशन तिथि आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग होगी। इसमें 30 सितंबर 2017 तक शीर्ष आठ पर रहने वाली आठ टीमें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए सीधे क्वॉलिफाइ करेंगी।

इसके बाद की चार टीमों को आईसीसी वर्ल्ड कप क्वॉलिफायर 2018 में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसमें आईसीसी क्रिकेट लीग चैंपियनशिप और आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन दो से आगे बढ़ने वाली टीमें भी हिस्सा लेंगी।

फीफा रैंकिंग : भारत को 12 स्थान का नुकसान

ज्यूरिख : भारतीय फुटबाल टीम ताजातरीन फीफा रैंकिंग में 12 स्थान गिरकर 167 वें स्थान पर पहुंच गई है। बीते महीने भारतीय टीम 155 वें स्थान पर थी। भारत को 12 स्थान का नुकसान फीफा 2018 विश्व कप क्वालीफायर मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण हुआ है।

भारत अब तक खेले गए तीन क्वालीफायर मैच हार चुका है। अब भारत को 8 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान और फिर 13 अक्टूबर को ओमान से भिड़ना है।

अर्जेंटीना वैश्विक सूची में पहले स्थान पर है जबकि जर्मनी दूसरे स्थान पर है। इसके बाद बेल्जियम की टीम है और फिर पुर्तगाल है। इस सूची में कोलम्बिया पांचवें, स्पेन छठे, पांच बार का चैम्पियन ब्राजील सातवें और वेल्स आठवें स्थान पर है। मौजूदा कोपा अमरीका विजेता चिली नौवें स्थान पर है जबकि इंग्लैंड इस सूची में 10वें क्रम पर है।

आईपीएल की तर्ज पर बेसबॉल लीग शुरू करेगा एबीएफआई

इंदौर : क्रिकेट की लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से प्रेरणा लेते हुए अमैच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (एबीएफआई) इस तर्ज पर अगले साल बेसबॉल की लीग शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है।

एबीएफआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसराज मेहता ने संवाददाताओं को बताया, 'हम आईपीएल की तर्ज पर देश में अगले साल बेसबॉल की लीग शुरू करेंगे। इस बेसबॉल लीग का प्रारूप अगले कुछ दिनों में तय कर लिया जायेगा। हमें उम्मीद है कि इस लीग से देश में बेसबॉल को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी।'

मेहता ने कहा, 'भारत में बेसबॉल के अच्छे मैदानों की कमी इस खेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में बेसबॉल के ऐसे मैदान न के बराबर हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मापदंडों पर खरे उतरते हों। लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि देश में बेसबॉल के अच्छे मैदान तैयार किये जायें।'

उन्होंने कहा कि एबीएफआई के अध्यक्ष के तौर पर उनकी प्राथमिकताओं में देश में बेसबॉल का बढ़िया आधारभूत ढांचा विकसित करना और खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेने के लिये विदेश भेजने का इंतजाम करना शामिल है।

मेहता ने यह भी बताया कि एबीएफआई अगले साल जनवरी में इंदौर में सीनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता आयोजित करेगा। इसके बाद जून में शहर में जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल स्पर्धा का भी आयोजन होगा।

2017 के शूटिंग विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत

नई दिल्ली : भारतीय निशानेबाजी फैंस के लिए एक अच्छी खबर हैं। भारत 2017 में शॉटगन/ राइफल/ पिस्टल शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अगर ये टूर्नामेंट सफल रहा तो उसके बाद भारत 2018 की प्रतिष्ठित विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी हासिल करने का प्रयास करेगा। 2017 का शूटिंग विश्व कप भारतीय शूटर्स के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा। ये साल में होने वाले चार आइएसएसएफ वर्ल्ड कप में से एक होगा। देश में शूटिंग का संचालन करने वाली संस्था एनआरएआइ के अध्यक्ष रनिंदर सिंह ने कहा, हमें 2017 के कंबाइन वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई है और सब अच्छे से हुआ तो हम 2018 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दावा ठोंकेंगे जहां 2020 ओलंपिक खेलों के लिए 70 स्थान दांव पर होंगे।

आईसीसी टीम रैंकिंग में भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर

दुबई : भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर है जबकि नई बहुप्रारूप रैंकिंग प्रणाली आईसीसी ने लागू कर दी है। नई प्रणाली के तहत टी 20, वनडे और टेस्ट मैचों के नतीजे मिलाकर एक रैंकिंग तय की जाएगी।

आईसीसी महिला विश्व कप 2013 और टी 20 विश्व कप 2014 विजेता आस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। इंग्लैंड दस टीमों में दूसरे स्थान पर है जबकि न्यूजीलैंड तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। इसके बाद वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और आयरलैंड हैं।

भारतीय कप्तान मिताली राज ने कहा, 'मैं खुश हूं कि आईसीसी ने महिला टीम रैंकिंग शुरू की है। अब द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में और मजा आयेगा क्योंकि जीत से न सिर्फ टीमें आईसीसी महिला विश्व कप में जगह पाने के करीब पहुंचेंगी बल्कि उनकी रैंकिंग भी बेहतर होगी।' उन्होंने कहा, 'भारत का लक्ष्य महिला विश्व कप 2017 के लिये क्वालीफाई करना और रैंकिंग में शीर्ष पर रहना है। यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम कड़ी मेहनत करके इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।' टीम रैंकिंग में सालाना अपडेट हर साल एक अक्तूबर को होता जबकि पुरूषों की टेस्ट, वनडे और टीम रैंकिंग के सालाना अपडेट मई में होते हैं।

बिजनेस न्यूज

महाराष्ट्र में 1,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगा मर्सेडीज

नई दिल्ली : मर्सेडीज-बेंज महाराष्ट्र में लग्जरी कारों के उत्पादन पर 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, मर्सेडीज-बेंज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ एबरहर्ड कर्न और कंपनी के भावी मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ रॉलैंड फोल्जर के बीच हुई एक बैठक में यह घोषणा की गई। फडणवीस ने इस परियोजना पर सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस महीने की शुरआत में मर्सेडीज-बेंज इंडिया ने घोषणा की थी कि उसने मर्सेडीज-मेबैक एस500 का अपने चाकन संयंत्र से उत्पादन करने का निर्णय किया है। मर्सेडीज-मेबैक एस500 कंपनी की उन सबसे आलीशान कारों में से एक है जिसका स्थानीय स्तर पर उत्पादन भारतीय बाजार के लिए किया जाएगा। भारत जर्मनी के बाद दूसरा देश होगा जहां कंपनी मर्सेडीज-मेबैक एस500 का प्रॉडक्शन करेगी।

फ्लिपकार्ट की 'बिग बिलियन सेल', 13 अक्टूबर से मिलेंगे खास ऑफर

बेंगलुरू : ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी 'बिग बिलियन सेल' का दूसरा संस्करण अगले महीने आयोजित करने की घोषणा की। यह सेल 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहेगी। कंपनी के बयान के अनुसार इसमें केवल एप के जरिये खरीदारी का मौका मिलेगा। कंपनी ने इस दौरान 70 से अधिक उत्पाद श्रेणियों में खास ऑफर्स और डिस्काउंट की घोषणा की है। इस पांच दिवसीय आयोजन के दौरान फ्लिपकार्ट और मिंत्रा 'बिग बिलियन डेज़' में भागीदारी भी करेंगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल कंपनी तकनीकी गड़बड़ी के चलते 'बिग बिलियन डे' सेल में ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई थी।

हीरो माइस्ट्रो एज स्कूटर लॉन्च, कीमत 49,500 रुपये

नई दिल्ली : हीरो मोटोकॉर्प ने नए हीरो माइस्ट्रो एज स्कूटर को लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस स्कूटर के एलएक्स वैरियंट की कीमत 49,500 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली), जबकि वीएक्स वैरियंट की कीमत 50,700 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तय की है।

हीरो माइस्ट्रो एज 13 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हीरो के इस नए स्कूटर में एवीएल द्वारा विकसित 110सीसी का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजन लगाया गया है, जिससे 8.4पीएस की ताकत और 8.3एनएम का टॉर्क पैदा होता है। इस इंजन को सीवीटी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। माइस्ट्रो एज को मुख्य रूप से पुरुष ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस स्कूटर में तमाम प्रीमियम फीचर्स हैं जिनमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फॉर्क्स, 12-इंच अलॉय वील्स, ट्यूबलेस टायर्स, इंजन इमोबिलाइजर, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, पार्ट डिजिटल-पार्ट ऐनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल, कंबाइन्ड ब्रेकिंग सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग सॉकिट, अंडरसीट लगेज लैम्प और एलईडी टेललाइट शामिल हैं।

हीरो इ्यूट
इसके अलावा कंपनी ने अपने हीरो इ्यूट स्कूटर की भी झलक दी जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाना है। यह स्कूटर भी देखने में बढ़िया है और कंपनी को उम्मीद है कि यह एंट्री-लेवल स्कूटर ग्राहकों को आकर्षित करेगा।

एफडीआई निवेश में भारत नंबर- 1, चीन को पछाड़ा

2015 की पहली छमाही में भारत विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। भारत में विदेशी निवेशकों के बढ़ते रुझान के चलते एफडीआई निवेश में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। इस साल भारत में अब तक 31 अरब डॉलर एफडीआई निवेश हो चुका है जो चीन से 3 अरब डॉलर ज्यादा है। इसके अलावा डब्ल्यूईएफ के ग्लोबल कंपिटीटिव इंडेक्स में भारत 71वें से 55वें नंबर पर पहुंच गया है। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की कोशिश रंग ला रही है और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का फायदा देखने को मिल रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के जरिए निवेशकों को लुभाने की कोशिश सरकार कर रही है।

नयी दिल्ली : डीआईपीपी सेक्रेटरी अमिताभ कांत से इस विषय में चर्चा करते हुए कहा की भारत में स्थिरता और पॉजिटिव माहौल है जिसके चलते एफआईआई यहां पैसे लगाना पसंद कर रहे हैं। हालांकि देश में अभी भी कुछ मुद्दों पर एफआईआई चिंतित रहते हैं और इसे दूर करने और देश में बिजनेस करना आसान बनाने के लिए बैंकरप्सी कानून लाना जरूरी है। इस बार वर्ल्ड बैंक के विश्लेषण में भारत में फिर से ग्रोथ देखी जाएगी और अगले 3 सालों में भारत एफडीआई के मोर्चे पर विश्व के शीर्ष 50 देशों में शामिल हो जाएगा।

बैंकरप्सी कानून स्टार्टअप्स के लिए बेहद जरूरी है और देश में कारोबार शुरू करना और खत्म करना काफी आसान होना चाहिए जिससे कारोबारियों को यहां आने में सोचना ना पड़े। मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारत आकर्षक डेस्टीनेशन बन गया है। यही वजह है कि इस साल अभी तक चीन के मुकाबले भारत में 300 करोड़ डॉलर का ज्यादा एफडीआई आया है।

देश में उभरते हुए स्टार्टअप्स के लिए भी कई मौके बने हैं और इसके चलते विदेशी स्टार्टअप्स भी यहां कारोबार करने के लिए आना चाहते हैं। ऊबर, ओला जैसे स्टार्टअप्स भारत में कारोबार की विशाल संभावनाओं के चलते ही यहां आए हैं। ऊबर-ओला जैसे बिजनेस मॉडल को यहां बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि इसके चलते लोगों को सस्ती सेवाएं मिल रही हैं।

अमिताभ कांत ने कहा कि ई-कॉमर्स रिटेल में रिटेल एफडीआई के नियमों पर जल्द सफाई जारी की जाएगी। ई-कॉमर्स में बी2सी मॉडल किसी भी देश में सफल नहीं हुआ है। हमारे देश में भी बी2सी मॉडल में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी नहीं दी गई है। देश में 9-10 फीसदी ग्रोथ के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना जरूरी है और स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। दिल्ली-मुंबई के 5 शहरों में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर पर काम शुरू किया जाएगा और चेन्नई में भी जल्द इंडस्ट्रियल कॉरीडोर पर काम होगा।

ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 16 पायदान चढ़ा भारत

जिनीवा : मोदी सरकार के आर्थिक सुधार का असर नजर आने लगा है। दुनिया की सर्वाधिक कॉम्पिटिटिव इकॉनमी के ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने हैरतअंगेज तौर पर बढ़त हासिल की है। भारत ने 16 पोजिशन छलांग लगाते हुए 71वें पायदान से आगे बढ़कर अब 55वें पायदान पर अपनी जगह बना ली है। इस लिस्ट में अभी टॉप पर स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की लेटेस्ट ग्लोब कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की रैंकिंग में इजाफा देश में हुई हालिया इकनॉमिक रिकवरी को दिखाता है। इससे पता चलता है कि देश के संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता में बेहतरी आई है और आधारिक संरचना में भी थोड़ी बेहतरी आई है।

इस लिस्ट में लगातार सात सालों से टॉप पर स्विट्जरलैंड है और उसके बाद सिंगापुर, संयुक्त राज्य, जर्मनी और नीदरलैंड टॉप 5 में शामिल हैं। इनके बाद टॉप 10 में जापान, हांगकांग, फिनलैंड, स्वीडन और यूके का स्थान है। उभरते मार्केट्स में भारत में 5 साल से गिरावट का रुझान समाप्त हुआ है और 16 पोजिशन छलांग के साथ 55वें पायदान पर पहुंच गया है। दक्षिणी अफ्रीका 7 पोजिशन की छलांग के साथ 56वें से 49वें पायदान पर पहुंच गया है।

तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी का मुद्दा अगले साल तक ठंडे बस्ते में

तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनी छापने के मामले में मोदी सरकार तंबाकू लॉबी के आगे झुकती दिख रही है। इस दबाव का ही नतीजा है कि केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों के 85 फीसदी हिस्से पर चेतावनी छापने के मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक अनुमान के मुताबिक देश में कुल 9,00,000 लोग हर साल तंबाकू उत्पादों के सेवन की वजह से जान गंवा देते हैं।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी छापने के मामले को अप्रैल, 2016 तक के लिए टाल दिया है, इसे इसी साल अप्रैल से लागू किया जाना था। सरकार ने पिछले साल सिगरेट, गुटखा और खैनी आदि के पैकेटों के 85 पर्सेंट हिस्से पर चेतावनी छापे जाने का आदेश दिया था। इस मामले पर संसदीय समिति का कहना है कि वह इस बात की समीक्षा कर रही है कि 85 पर्सेंट हिस्से पर चेतावनी छापे जाने से इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तंबाकू विरोधी प्रचार से जुड़े लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्या बात है कि चेतावनी छापे जाने के मसले को लटकाया जा रहा है। सवाल इस बात पर भी उठाया जा रहा है कि इस संसदीय समिति में ऐसे सांसद को क्यों शामिल किया गया है, जो खुद तंबाकू कारोबारी हैं।

गौरतलब है कि बीते साल तंबाकू लॉबी ने केंद्र सरकार की ओर से 85 फीसदी हिस्से पर चेतावनी छापे जाने के आदेश कारोबार विरोधी और अव्यवहारिक करार दिया गया था। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई में केंद्र सरकार से इस कानून को तत्काल लागू करने को कहा था।

भारत के बगैर SDG के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकती दुनिया : बिल गेट्स

नई दिल्ली : पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया से गरीबी, जलवायु परिवर्तन और असमानता को दूर करने के लिए 17 महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों को धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) का नाम दिया गया है जिसे अगले 15 सालों के अंदर हासिल करना है। इससे पहले वर्ष 2,000 में मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स के तहत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनको हासिल करना था। एमडीजी से लेकर एसडीजी में टेक महारथी और परोपकारी बिल गेट्स ने दिल खोलकर हिस्सा लिया है। गरीबी के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में वह आगे-आगे रहे हैं। उन्होंने 41.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 2,000 अरब रुपये इन्हीं कामों पर खर्च करने के लिए दान कर दिया। गेट्स ने फिल्ममेकर रिचार्ड कुर्तीस के ब्रेनचाइल्ड ग्लोबल गोल्स कैंपेन को भी अपना सक्रिय समर्थन दिया है। इस कैंपने के तहत 7 दिनों के अंदर 7 अरब लोगों के बीच एसडीजी के 17 लक्ष्यों को लोकप्रिय बनाना है। ये 17 लक्ष्य भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इनको हासिल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, इस संबंध में उन्होंने बताया कि सबकी नजर भारत पर है। एमडीजी में जो भूमिका चीन की थी, एसडीजी में वही भूमिका भारत को निभानी है। जिस तरह दुनिया गरीबी उन्मूलन के अपने लक्ष्य को चीन की मदद के बगैर हासिल नहीं कर सकती थी, ठीक उसी तरह एसडीजी के लक्ष्यों को भारत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता है।

कॉल ड्रॉप प्रॉब्लम का निकाला हल, ये होगा नया फार्मूला

मोबाइल फोन्स से कॉल करने पर अचानक कॉल कटने और बैलेंस कट जाने की लम्बे समय से चली आ रही समस्या का हल निकाल लिया गया है। बताया जाता है कि कॉल ड्रॉप का हल सभी कम्पनियों ने मिलकर निकाला है।

ये है नया हल
अब तक अधिकतर मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियां प्रति मिनट के हिसाब से कॉल रेट चार्ज कर रही हैं। इससे कॉल चाहे एक मिनट पहले कट जाए या फिर कुछ ही सैकेंडस में, पैसा पूरे मिनट का ही लगता है। यही वजह है कि उपभोक्ताओं को इस समस्या से खासी नाराजगी थी। अब कम्पनियों ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रति सैकेंड कॉल रेट करने का सुझाव दिया है। इससे जितनी बात उतना पैसा वाला प्लान शुरू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी कम्पनी की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

इन कम्पनियों ने पहले ही किया शुरू
एक तरफ जहां प्रति सैकेंड कॉल चार्ज लेने की नीति पर मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियां विचार कर रही हैं। वहीं एयरटेल और आइडिया ने इसे लागू भी कर दिया है। दोनों कम्पनियों ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। इस महीने में ये कम्पनियां अपने सभी यूजर्स को इस प्लान पर ले आएंगी। सूत्रों का कहना है कि प्रति सैकेंड कॉल चार्ज प्लांस को और आकर्षक बनाने के लिए कई तरह की नई स्कीम्स भी शुरू की जाएंगी।

घटने लगी कॉल ड्रॉप की समस्या
केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कॉल ड्रॉप की समस्या धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि इससे ग्राहकों को लाभ मिल रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस संबंध में हिदायत दे दी गई है कि वे तकनीक में सुधार के साथ ही कॉल ड्रॉप बिलकुल खत्म करें। हाल ही में हुई बैठक का नतीजा दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल के टॉवर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही सभी कम्पनियों को अपने नेटवर्क में सुधार लाने और कॉल ड्रॉप को खत्म करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की योजना : गडकरी

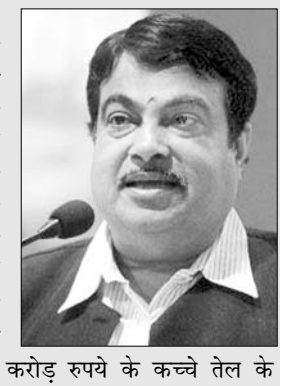

नयी दिल्ली : केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने राज्य की परिवहन निगमों द्वारा चलाई जा रही करीब डेढ़ लाख डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की योजना बनाई है जिससे आठ लाख करोड़ रुपये के कच्चे तेल के आयात बिल में कमी लाने व प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, देश में राज्य सड़क परिवहन निगमों की डेढ़ लाख बसें चल रही हैं। हमारा प्रयास इन्हें इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली बसों में तब्दील करना है जिससे कच्चा तेल व पेट्रोलियम का आयात बिल 8 लाख करोड़ रुपये घटेगा और भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए देश को बायो-डीजल व एथनॉल जैसे पर्यावरण अनुकूल ईंधन पर चलने वाले वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। 'हरित राजमार्ग' पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर अंकुश लगाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर इसरो जल्द ही देशज लिथियम आयन बैटरियां पेश करेगा जिनसे सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाए जा सकेंगे।

छह महीने में 100 कंपनियों की रेटिंग घटकर डिफॉल्ट हुई

नई दिल्ली : पिछले छह सालों में पहली बार वित्त वर्ष 2015 में भारतीय कंपनियों का सबसे कमजोर रिपोर्ट कार्ड रहा है। लीमन ब्रदर्स संकट के बाद से उनकी कमाई में सबसे बड़ी गिरावट आई है और रेवेन्यू ग्रोथ एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गई है। बीएसई 500 की कंपनियो में हर चौथी कंपनी की कमाई में गिरावट हुई है। ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, केयर्न इंडिया और बीएचईएल की कमाई में 8 फीसदी से 23 फीसदी के बीच में गिरावट हुई है।

> ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, केयर्न इंडिया और बीएचईएल की कमाई में 8 फीसदी से 23 फीसदी के बीच में गिरावट

फाइनैंशल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून क्वॉर्टर में 2,129 कंपनियों की कुल कमाई में 2.45 फीसदी की गिरावट हुई है। इससे स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। कंपनियों की कमाई में गिरावट का परिणाम उनके द्वारा बॉन्डहोल्डरों का पैसा चुकता नहीं करने की शक्ल में सामने आया। पिछले छह महीने में करीब 100 कंपनियों की रेटिंग कम करके डिफॉल्ट स्टेटस कर दिया गया है। पिछले सप्ताह आमटेक ऑटो ने बॉन्डहोल्डरों के 800 करोड़ रुपये का रिपेमेंट नहीं किया।

पिछला सप्ताह रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की रेटिंग स्थिर से नेगेटिव कर दी। इस साल अब तक तीन मुख्य एजेंसियों के बीच कम से कम 70 कंपनियों की डेट रेटिंग घटाई गई है और अप्रैल से करीब 100 कंपनियों, जिनमें से 20 लिस्टेड है और 76 गैर लिस्टेड, को डिफॉल्ट रेटिंग दी गई है। रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि वर्तमान समय में कंपनियों की कमाई पर कम मांग के कारण दबाव बना हुआ है। बैंकरों का कहना है कि कमजोर कैश फ्लो के कारण छोटी कंपनियों की रेटिंग घटाई गई है क्योंकि उनकी प्राप्तियों की संख्या बढ़ रही है।

जेपी इंफ्राटेक और जय प्रकाश वेंचर्स समेत आठ कंपनियों के लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग बीबीबी ग्रेड से घटाकर कम कर दी गई है। जय प्रकाश असोसिएट्स को अब डी ग्रेड यानी डिफॉल्ट रेटिंग दी गई है। रेटिंग घटाने को लेकर रेटिंग एजेंसियों की आलोचना की गई जिसका बचाव करते हुए रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि वे किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग तय करते समय कई कारकों पर गौर करती हैं।

अपने घटते वजन से परेशान है आलिया

मुंबई : बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस और महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट अपने घटते वजन से बेहद परेशान है। वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत करने वाले आलिया ने अपना बहुत सारा वजन घटा लिया है। वजन घटाने के चलते अब लोग आलिया को जरूरत से ज्यादा दुबला कहने लगे हैं। यही वजह है कि आलिया अपने लगातार घटते वजन से चिंतित हैं। आलिया ने कहा कि हां, मैंने बहुत वजन कम कर लिया है। ये कुछ महीने पहले की ऑस्ट्रिया की मेरी ट्रिप का नतीजा है, जहां मैंने डिटॉक्सीफेशन करवाया था। अब मैं रेग्युलर वर्कआउट भी कर रही हूं तो परफेक्ट शेप में आ गई हूं। मैं खुश हूं, क्योंकि अब हर तरह के कपड़े पहन सकती हूं और वो मुझ पर अच्छे भी लगते हैं। गौरतलब है कि आलिया अपनी अपकमिंग फिल्म शानदार में बिकनी पहने नजर आएंगी। आलिया बिकनी में काफी हॉट लग रही है। इस फिल्म में पहली बार आलिया और शाहिद कपूर की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी। विकास बहल डायरेक्टेड ये फिल्म 22 अक्टूबर को रिलीज होगी।

दीपिका मानती है रणवीर को बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उन्होंने तोड़ा दिल

मुंबई : बॉलीवुड के लव बड्स रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच ऑन स्क्रीन ही नहीं, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी जबरदस्त कैमेस्ट्री है। लेकिन हाल ही में जब दीपिका ने रणवीर से पूछा कि क्या वे उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं, तो रणवीर ने इससे इनकार कर दिया। इतना सुनते ही दीपिका को चेहरा उतर गया। अरे घबराइए नहीं, ये केवल एक डबस्मैश की कहानी है। रणवीर और दीपिका का ये डबस्मैश बहुत ही मजेदार है। रणवीर ने इस डबस्मैश वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। गौरतलब है कि रणवीर और दीपिका ने अब तक अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनकी कैमेस्ट्री साफ देखी जा सकती है। जल्द ही दोनों संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में नजर आएंगे।

कुछ लोगों में अदा होती है, कुछ में नहीं : मलाइका

मुंबई : अभिनेत्री-निर्माता मलाइका अरोड़ा खान का कहना है कि कुछ लोगों में अदा होती है और कुछ लोगों में नहीं होती। हिंदी फिल्म उद्योग में मलाइका को उनके खास फैशन के लिए जाना जाता है। मलाइका ने फेमिना स्टाइल दिवा वेस्ट 2015 अवार्ड पर कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोगों में अदा होती है और कुछ में नहीं, यह मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं या क्या कोशिश करते हैं। मलाइका, सुजैन खान, विकास बहल और रॉकी एस के साथ पुरस्कार के निर्णायक दल का हिस्सा भी थीं। कार्यक्रम के अंत में सोनल रिहानी को सर्वसम्मति से विजेता घोषित किया गया, जबकि आयशा घोष और श्रेया चौधरी पहली और दूसरी विजेता रहीं। इस कार्यक्रम की मेजबानी रोशेल मारिया राव ने की। मिर्जा अली कुली ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी।

गागा को मिलेगा वुमन ऑफ द ईयर सम्मान

लॉस एंजिल्स : पॉप आइकॉन लेडी गागा को महिलाओं के लिए होने वाले सालाना जलसे में सम्मानित किया जाएगा। यह दिसंबर में पहली बार ऑन एअर होगा। द मैगजीन के अनुसार 29 वर्षीय गागा का मनोरंजन में अतुलनीय योगदान किए जाने को लेकर सम्मान किया जाएगा। ईऑनलाइन के अनुसार सिंगर और गीतकार गागा ने ट्विटर पर लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बिलबोर्ड ने वुमन ऑफ द ईयर के लिए चुना है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूं। मैं इस बात के लिए आभारी हूं। गागा जल्द ही एक्टिंग में भी अपना डेब्यू करने जा रही है। अमेरिकन हॉरर स्टोरी : होटल में गागा नजर आएंगी। इस सम्मान के साथ ही गागा का नाम भी उन हस्तियों में शुमार हो जाएगा जहां पहले से टेलर स्विफ्ट, पिंक, केटी पेरी और बियोंसे का नाम मौजूद हैं।

शादी को लेकर किए गए सवालों पर सलमान क्यूं देते है हर बार अजीबोगरीब जवाब।

क्या कभी होगी सलमान की शादी?

मुंबई : बॉलीवुड में सिर्फ सलमान खान ही ऐसे एक्टर है जिनकी शादी का बी-टाउन के लोगो के साथ-साथ उनके फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है। बावजूद इसके लगता है कि सलमान का जैसे शादी करने का कोई विचार ही नहीं है? हाल ही में उनकी शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कुछ ऐसा ही जवाब दिया सलमान ने। सलमान अपने अपकमिंग टीवी रियालिटी शो बिग बॉस-9 में व्यस्त है और इस शो के प्रमोशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार मौजूद रहते है। ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस में जब सलमान से उनकी शादी करने का सवाल पूछा गया तो उनके जवाब से सब चौंक गए। हमारे देश में शादी सात जन्मों का बंधन होता है, जबकि सलमान को ऐसा नहीं लगता। सलमान के मुताबिक शादियां अब उम्र भर के लिए नहीं होती क्योंकि समय बदल गया है। आजकल होने वाली शादियां टेम्परेरी शादी कहलाती है। बताओ, अब कौन शादी के बाद खुश रहता है? सलमान खान का नाम अब तक ना जाने कितनी ही एक्ट्रेस के साथ जुड़ सकता है और हर बार उनकी शादी की उम्मीद लगती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल तो सलमान बिग बॉस-9 में व्यस्त है तो शादी की संभावना कम ही है।

अंकिता के साथ अगले साल फेरे लेंगे सुशांत

नई दिल्ली : छोटे पर्दे से बॉलीवुड फिल्मों तक का सफर तय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत काफी लंबे समय से अंकिता लोखंडे के साथ अफेयर में हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी टीवी शो पवित्र रिश्ता के सेट से शुरू हुई थी और अब जल्दी ही ये दोनों शादी भी करने वाले हैं। खबर है कि ये दोनों एक्टर्स साल 2016 के अंत तक शादी कर लेंगे और इस खबर की पुष्टि खुद सुशांत ने की है। पिछले 6-7 सालों से रिलेशनशिप में होने के बाद ये दोनों फिलहाल लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। अपने एक इंटरव्यू में सुशांत ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि शादी करते ही वो अपनी फीमेल फैन फॉलोइंग खो देंगे। सुशांत का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो वो एक्टिंग छोड़ देंगे। सुशांत ने साल 2013 में फिल्म काई पो छे से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वो शुद्ध देसी रोमांस (2013), पीके (2014) और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी (2015) जैसी फिल्में कर चुके हैं। जल्दी ही सुशांत इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बन रही बायोपिक फिल्म में नजर आएंगे। एम एस धोनी - द अनटोल्ड स्टोरी नाम से बन रही इस फिल्म को नीरज पाण्डेय डायरेक्ट कर रहे हैं। अपनी शादी के प्लान के बारे में सुशांत बताते हैं कि अंकिता को एक सुसंपन्न शादी करनी है और ऐसा अगले साल के अंत तक ही हो सकता है जब मैं अपने सारे प्रोजेट्स पूरे कर लूंगा। तब मैं भी इत्मीनान से अपनी शादी एन्जॉय कर पाऊंगा।

Aawara Pagal Deewana के सिक्वल के लीड एक्टर, जॉन नहीं अक्षय

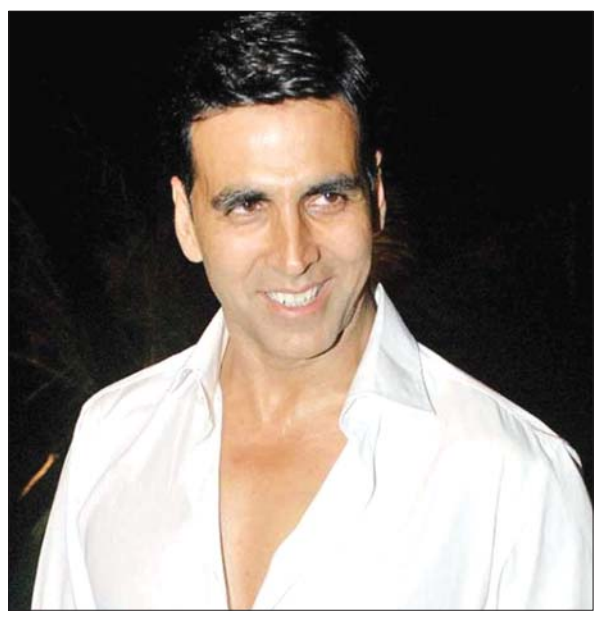

मुंबई : बॉलीवुड में काफी दिनों यह चर्चा हो रही है कि जॉन अब्राहम ने अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है। अक्षय की दो सुपरहिट फिल्मों के सिक्वल में जॉन ही थे इसलिए कयास लगाया जा रहा था कि अक्की की आवारा पागल दीवाना के सिक्वल में भी वो ही लीड करेंगे।

प्रोड्यूसर फिरोज ए नाडियावाला ने गुरू गुलाब खत्री यानी अक्षय को साल 2002 की हिट आवारा पागल दीवाना के सिक्वल के लिए तैयार कर लिया है। फिरोज ने हेरा फेरी-3 के शूट में अक्षय को बहुत मिस किया था और वैलकम बैक की सफलता के बाद उन्होनें अक्षय के साथ अपनी जोड़ी के कमबैक की योजना तैयार कर ली और अक्षय की हां ने उन्हें काफी खुश कर दिया है।

2002 में आइ इस फिल्म में अक्की के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर और आफताब भी थे। सिक्वल में आफताब की अलावा सभी एक्टर्स होंगे और इस बार विक्रम भट्ट इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे। अक्षय की सिंग इज ब्लिंग हाल ही में हिट साबित हुई है और अपकमिंग मूवी हाऊसफुल- 3 और ए यारलिफ्ट का दर्शकों को इंतजार है।

आपको बता दें कि जॉन ने अक्षय की जगह उनकी दो फिल्मों में काम किया है। वैलकम बैक जो कि हिट रही और हेराफेरी- 3 जो जल्द रीलिज होने वाली है। जॉन द्वारा अक्की की दो फिल्में करने पर हर जगह ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जॉन ने अक्षय को रिप्लेस कर दिया है। अब अक्षय की आवारा पागल दीवाना के सिक्वल की हां ने सबके मुंह बंद कर दिए है।

आर.एन.आई. रजि. नं. **39661/84.** वर्ष-31, अंक-38 (04 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2015 तक). **स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक** राघवेन्द्र द्वारा बाबा प्रिंटर्स पटना से मुद्रित एवं 105 चंद्रिका ब्लॉक, विश्वनाथ प्लाजा, मीठापुर डी एरिया, पटना-1 से प्रकाशित, **संपादक**- डॉ दीपक कुमार राय, 9431433478, ई मेल- **ganadesh.patna@gmail.com.** *कानूनी मामले पटना के सक्षम न्यायालय में ही निपटाये जायेंगे.